उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल

रिट याचिका (एम/एस) नं. 2015 का 2364

हीरा सिंह पांगते और अन्य..... .....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य।..... उत्तरदाता

मौजूदाः–

श्री T.A. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविशंकर कांडपाल ने खान की सहायता की।
श्री V.D. उत्तराखंड राज्य के लिए बिसेन, संक्षिप्त धारक।
श्री राकेश थपलियाल, सहायक सॉलिसिटर जनरल, भारत संघ के लिए श्री पंकज चतुर्वेदी और श्री ललित शर्मा, स्थायी वकील द्वारा सहायता की गई।

आरक्षण की तिथिः05.10.2021

निर्णय की तिथिः04.03.2022

न्यायाधीश माननीय शरद कुमार शर्मा, जे.

फ्लोरैट अल्मा मेटर, हमारा महान राष्ट्र भारत।

2. उपर्युक्त संदर्भ की प्रासंगिकता संबंधित मुद्दे के संदर्भ निहित है, और प्रत्येक नागरिक के लिए एक देश की प्रासंगिकता है, जो इसनिहित रहता है।अपने शाब्दिक और प्रासंगिक अर्थ में "अल्मा मेटर" शब्द के संदर्भ का अर्थ होगा "उदार माँ" और यही कारण है कि हमारा देश दुनिया का एकमात्र देश है, जिसे "मातृभूमि" कहा जाता है।यदि "अल्मा

मेटर" शब्द के दो संदर्भों से पहले "पुष्प" के रूप में उपयोग किया जाने वाला शब्द है, तो उसमें भी एक संदर्भ है जो फूलों के विकास को दर्शाता है। देश और उसके लंबे जीवन के लिए, जो याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे से निपटने के दौरान प्रासंगिक बारहमासी महत्व का होगा।

3. मौजूदा रिट याचिका में निहित मुद्दा एक गंभीर राष्ट्रीय चिंता का विषय है, जो 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' से सटे देश की सीमा सीमाओं को विनियमित करने से संबंधित है, जो हमारे पड़ोसी देश, चीन की सीमा रेखाओं को जोड़ती है और साझा करती है, जो लगभग 20 से 25 किलोमीटर है। केवल भूमि से दूर, विवाद में, जिसे ITBP की रक्षा आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है, i.e. भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (इसके बाद I.T.B.P. के रूप में संदर्भित किया जाएगा।)।

4. मुद्दा यह होगा कि क्या कुछ सीमित वैधानिक संरक्षण होने के बावजूद; आरक्षित समुदाय के एक निर्दिष्ट वर्ग को दिया जा रहा है, i.e. अनुसूचित जनजाति, क्या उनके व्यक्तिगत अधिकार, यदि यह कानून के तहत प्रचलित है, तो राष्ट्र के अधिकार और हित ठीक होना प्रबल होगा, i.e. हमारी मातृभूमि, विशेष रूप से, जब यह हमारे राष्ट्र की महत्वपूर्ण और रणनीतिक सीमा की रक्षा करने का आह्वान करती है,

ताकि पड़ोसी देश चीन द्वारा किसी भी अभूतपूर्व विद्रोह या समूह आक्रामकता का सामना करने के लिए तैयारी की जा सके।

5. मौजूदा रिट याचिका के याचिकाकर्ता, तर्क देते हैं और खुद को गाँव "मिलम", तहसील मुनस्यारी, जिला पिथौरागढ़ का निवासी होने का दावा करते हैं, जो हिमालय की ऊँची गोदियों में उच्च ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से ऊंचाई में लगभग 12,000 से 13,000 फीट।उक्त गाँव "मिलम", जहाँ विवादित भूमि स्थित है और जिसे रक्षा उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है, केवल लगभग 20 से 25 किलोमीटर है। सीमावर्ती सीमा से दूर, i.e. भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा, और रणनीतिक रूप से, यह देश की रक्षा के लिए एक गंभीर सैन्य महत्व की है।

6. याचिकाकर्ता मामले के साथ आए हैं, और उन्होंने एक दावा उठाया है, कि वे उक्त गांव के निवासी हैं, जो फिर से एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, क्योंकि इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत वर्गीकृत किया गया है और "जनजातियों" के रूप में शामिल किया गया है, जैसा कि U.P. के तहत निर्दिष्ट किया गया है। अनुसूचित जनजाति U.P. 1967 का आदेश।याचिकाकर्ताओं सम्बंधित है कि उपरोक्त गाँव में स्थित भूमि खसरा संख्या में स्थित है। 1417, 1416, 1419, 1397, 1409, 1410 और 1411।याचिकाकर्ता

संख्या. 3 ने तर्क देना है कि जहां तक उपरोक्त वर्णित भूमि का संबंध है, यह कथित रूप से याचिकाकर्ता संख्या. 3 के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।

7. दूसरी ओर, स्वर्गीय याचिकाकर्ता नंबर 1, जो बाद में था; याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिस्थापित सं। 1/1 से 1/5, ने इसी तरह खसरा नं. गाँव मिलम के 1370 और 1371 और उन्होंने दावा किया है और तर्क देना है कि वे भी अपने पूर्ववर्तियों के समय से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं।याचिकाकर्ता नंबर. 2 के पिता स्वर्गीय श्री महिमान सिंह, और उन्होंने दावा किया है कि एक ही गाँव के खसरा नं. 1421 और 1417 में अज्ञात भूमि पर उनका अधिकार हैं I

8. इसी सम्बंधित, याचिकाकर्ता नं। 4, ने यह भी दावा किया था और तर्क देना था कि वह खसरा संख्या ठीक होना दर्ज भूमि का मालिक है। 1470 और 1408, जिसे याचिकाकर्ता संख्या. 4 द्वारा अभिलेख पर रखा गया है, ताकि भूमि पर उसके दावे को प्रमाणित किया जा सके। याचिकाकर्ताओं ने तर्क देना कि उपरोक्त भूमि हिमालय सम्बंधित अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण, वर्ष सम्बंधित अधिकांश अवधि के लिए लगभग छह महीने तक, यह बर्फ स्वीकृत रूप से रहती है और गर्मियों के दौरान वर्ष के कुछ चुने हुए महीनों को छोड़कर, उनके

द्वारा भूमि पर शायद ही कोई कृषि गतिविधियाँ सम्बंधित जा रही हैं। याचिकाकर्ताओं का स्वीकार किया गया मामला यह है कि इस प्रकार दर्ज की गई उपरोक्त भूमि को विशेष रूप से "कृषि भूमि" के रूप में दिखाया गया है और "नो अबादी" के रूप में दिखाया गया है क्योंकि इस सम्बंधित से भूमि के किसी भी हिस्से से बाहर निकलता है।

9. रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने स्वीकृत रूप से किया था कि भूमि, जो अधिग्रहण का विषय है, जैसा कि 2013 के अधिनियम की **धारा** 11 (1) के तहत जारी अधिसूचना की अनुसूची में निहित है, एक 'कृषि भूमि' है, और निश्चित रूप से, इसका उपयोग कभी भी 'अबादी' के रूप में नहीं किया जा रहा है, जैसा कि राजस्व कानून के तहत परिभाषित किया गया है। "कृषि भूमि" शब्द को U.P. के प्रावधानों के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। जमींदारी उत्सादन और भूमि सुधार अधिनियम, बल्कि यह 'भूमि' शब्द को परिभाषित करता है, जिसमें कृषि की गतिविधि शामिल है।इसलिए, राजस्व कानून के संदर्भ ठीक होना भूमि और इसकी उपयोगिता विशेष रूप से कृषि उद्देश्यों के लिए सीमित है, और यहां तक कि इस न्यायालय की राय के अनुसार, इसका अर्थ होगा कि कृषि संपत्ति के किसी निवासी या मालिक द्वारा मिट्टी की जुताई के अधिकार की रक्षा के लिए एक निरंतर और निरंतर कृषि गतिविधि की जानी चाहिए।

10. याचिकाकर्ताओं ने तर्क देना कि चूंकि वे अनुसूचित जनजाति i.e. से संबंधित हैं। "भोटिया", जो अपने आप में भारत के संविधान द्वारा संरक्षित जनजातियों का एक वर्ग है, साथ ही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे इसके बाद 2013 का अधिनियम कहा जाएगा) के प्रावधानों के तहत, उनकी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए था, यहां तक कि रक्षा कर्मियों की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्यों के लिए, क्योंकि उनकी स्व–प्रशंसित प्रतिरक्षा के कारण, जिसे उन्होंने 2013 के अधिनियम की धारा 41 के साथ पढ़ने के लिए धारा 40 के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में निहित करने का दावा किया है।

11. साथ ही, उन्होंने U.P. के आधार पर सुरक्षा की भी मांग की है। अनुसूचित जनजाति आदेश, जैसा कि 1967 में अधिसूचित किया गया था; क्योंकि "भोटिया जनजातियों" को 1967 की अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों की उक्त सूची में शामिल किया गया है।

12. याचिकाकर्ताओं ने तर्क देना है कि इस तथ्य के अलावा, कि वे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं और वे 1880 से भूमि के कब्जे में थे, और उन्होंने यह भी दावा किया है कि U.P. के प्रावधानों का प्रवर्तन। जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम/कुजा अधिनियम, उन्होंने भूमि के "भूमिधर" होने का

दर्जा हासिल कर लिया है, जो कि उनसे संबंधित होने का दावा किया जाता है, क्योंकि वे दावा करते हैं कि भूमि के संबंधित पार्सल U.P. Z.A. & L.R. एक्ट के प्रवर्तन के साथ उनके साथ "निहित" थे।

13ण यह सभी जानते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो पड़ोसी देश चीन के साथ हमारी महान मातृभूमि की सीमा रेखा को नियंत्रित और निर्धारित करती है, देश की रक्षा के दृष्टिकोण से रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, और विशेष रूप से, किसी भी अप्रत्याशित और अप्रत्याशित दुश्मन सैन्य कार्रवाई की स्थिति में, अगर देश की रक्षा आवश्यकता को मुकदमा करने के लिए हमें जवाबी कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, या यदि यह हमारे देश के खिलाफ लिया जाता है, और वह भी, जहां हमारे सशस्त्र बलों को उच्च ऊंचाई वाले युद्ध में देश की रक्षा करनी है, विभिन्न सांख्यिकीय, रणनीतिक और तकनीकी मुद्दा हैं, जिन पर सैन्य दृष्टिकोण से कुशल रक्षा कर्मियों द्वारा तकनीकी रूप से विचार करने की आवश्यकता है इसका मूल्यांकन, सक्षम सैन्य अधिकारियों द्वारा किया जाना है, और क्योंकि, चूंकि यह इसके बजाय, उक्त परिप्रेक्ष्य और भूमि के रणनीतिक स्थान पर आधारित है, जैसा कि पहले से ही वर्णित और ऊपर विस्तृत है, सक्षम अधिकारी, 2013 के अधिनियम के अध्याय–II के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, i.e. "सामाजिक प्रभाव निर्धारण" और "लोक प्रयोजनों" का अवधारण, उक्त आदेशिका और निर्धारण आदेशिका, जो विधि के अधीन अपेक्षित थी, को आरंभ वचन

देना पश्चात्, एक अधिसूचना, जो रिट याचिका में आक्षेपित है, अधिसूचना सं. 800/XVII–5/15–13 अर्ध सैनिक/**2015** दिनांक **1 अगस्त 2015,** जिसके तहत उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव, समूह कल्याण विभाग ने राज्य के राज्यपाल, महामहिम की पूर्व सहमति से 2013 के अधिनियम की **धारा** 11 (1) के तहत अधिसूचना जारी की थी, जिसमें मल्ला जौहर, मौज मिलम, जिला पिथौरागढ़ में स्थित उक्त भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया गया था और भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना के इरादे और उद्देश्य के बारे में एक सरल पठन पर, यह स्पष्ट और स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि भूमि अधिग्रहण का एकमात्र और एकमात्र उद्देश्य देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना था, इसके रणनीतिक स्थान को देखते हुए, और विशेष रूप से लगातार सैन्य विद्रोहों और सीमा रेखा के पार गोलाबारी के कारण, जो हाल ही में हमारा यह महान देश, पडोसी देश चीन द्वारा आसन्न खतरों का सामना कर रहा है और अधिग्रहण के लिये खुद ही एक प्रासंगिक उद्देश्य, जिसके बारे में यहा अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है–

राज्यपाल भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सर्व साधारण की सूचना के लिये अधिसूचित करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात जिला पिथौरागढ़ के ग्राम मिलम, परगना जौहार, तहसील मुनस्यारी में 14 वीं वाहिनी भा0ति0सी0पु0 बल, की अग्रिम चौकी मुख्यालय की स्थापना हेतु ग्राम मिलम की 2.4980 है, भूमि की आवश्यकता है।

चूंकि धारा 40 के अधीन आत्यायिकता उपबन्धों का अवलम्ब लेते हुए उक्त अधिनियम, 2013 की धारा 9 के अनुसार समुचित सरकार में सामाजिक समा ात निर्धारण अध्ययन कराने से छूट प्रदान करने की शक्ति दी गयी है। अतएव अब राज्यपाल की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यकता है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन निर्देश देते हैं, कि यद्यपि धारा 40 के अधीन कोई अभिनिर्णय/आदेश नहीं दिया गया है तथापि राज्यपाल उक्त लोक प्रयोजन के लिए

धारा 40 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा के साथ निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि की उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार विज्ञप्ति अधिसूचित की जाती हैः

14. इस समय जो अवलोकन करना प्रासंगिक होगा वह यह है कि यदि अधिग्रहण का उद्देश्य, जिसे 1 अगस्त, 2015 की आक्षेपित अधिसूचना में दिखाया गया है, को ही ध्यान में रखा जाता है, तो इसका उद्देश्य विशेष रूप से सीमा चौकी, i.e. की स्थापना के उद्देश्यों के लिए आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करना है। आईटीबीपी के 14 वें विंग के लिए गाँव मिलम में बॉर्डर आउट पोस्ट (संक्षेप में बीओपी)। भूमि अधिग्रहण के लिए कार्रवाई करते समय; 2013 के अधिनियम की **धारा** 11 के तहत, यह विशेष रूप से देखा गया कि सरकार और उसके समाज कल्याण विभाग ने 2013 के अधिनियम के अध्याय II, **धारा** 4 के अनुसार एक विस्तृत सर्वेक्षण किया था, और छूट के प्रयोजनों के लिए, जो देश की रक्षा के लिए देश के रक्षा बलों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के लिए, अधिनियम की **धारा** 40 के तहत निहित प्रावधानों या शर्तों के आलोक ठीक होना, जो सरकार को छूट के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है, जैसा कि अधिनियम 2013 की **धारा** 9 के तहत प्रदान किया गया है, अधिनियम 2013 की **धारा** 40 के निहितार्थ से, भूमि के संबंध ठीक होना "सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन" की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए, जिसे सैन्य या रक्षा आवश्यकता को पूरा करने के लिए

अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है, जब देश की रक्षा के मुद्दे की बात आती है, जो सर्वोपरि और सभी कानूनी या व्यक्तिगत अधिकारों से ऊपर है,–

"धारा 2.अधिनियम का अनुप्रयोगः–(1) भूमि अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास और पुनर्वास से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान तब लागू होंगे जब उपयुक्त सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक उद्देश्य सहित अपने स्वयं के उपयोग, धारण और नियंत्रण के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है और इसमें निम्नलिखित उद्देश्य शामिल होंगे, अर्थात्:–

(a) केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सहित संघ के नौसेना, सैन्य, वायु सेना और सशस्त्र बलों से संबंधित रणनीतिक उद्देश्यों के लिए या राष्ट्रीय सुरक्षा या भारत या राज्य पुलिस की रक्षा, लोगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण किसी भी कार्य के लिए; या .....

धारा 9.सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से छूट।– जहां धारा 40 के तहत तत्काल प्रावधानों को लागू करते हुए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव है, वहां उपयुक्त सरकार सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के वचन देना को छूट दे सकती है।"

15. अधिग्रहण के इरादे और उद्देश्य पर वापस लौटते हुए, यदि विशेष रूप से विचार किया जाता है, तो वास्तव में, राज्य सरकार ने 2013 के

अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (1) के तहत 01.08.2015 को अधिसूचना जारी करते हुए, अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करने के उद्देश्यों के लिए अधिनियम 2013 की धारा 9 के आक्षेपितार्थ को उचित रूप से ध्यान में रखा था।

16. रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से 1 अगस्त, 2015 की उपरोक्त अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी है कि अधिनियम की धारा 40 का उल्लंघन, अधिनियम की धारा 21 के तहत नोटिसों के प्रकाशन के बाद, भूमि का कब्जा लेने के लिए अनिवार्य रूप से जारी किए जाने की आवश्यकता थी; भले ही इसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित किया जाना था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया था।

17. 2013 के अधिनियम की धारा 40 के साथ पठनीय धारा 21 के प्रभावों के संबंध में याचिकाकर्ताओं के वकील के उपरोक्त विवाद का संदर्भ देने और प्रभावी ढंग से उत्तर देने ठीक होना, वास्तव में, उनके दलील का स्वयं अधिग्रहण की अधिसूचना के उद्देश्य में सिद्ध गया है, मेरा विचार है कि एक बार राज्य सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है, जैसा कि 2013 के अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रदान की गई छूट धारा के तहत प्रदान किया गया है, उस स्थिति में, 'सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन', जो अन्यथा 2013 के अधिनियम के अध्याय–II के तहत निहित

प्रावधानों द्वारा संरक्षित है, को छूट दी जानी चाहिए, जिसे 2013 के अधिनियम की धारा 40 के तहत प्रदान की गई शर्त और इरादे के संबंध में लागू किया जाना चाहिए।

18. इसके अतिरिक्त, यदि 2013 के अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (2), यदि उस पर विचार किया जाता है, तो वह स्वयं ही 2013 के अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) के उपबंधों के सख्त अनुपालन से छूट प्रदान करती है, जहां उपयुक्त सरकार, जिसे 2013 के अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (ङ) के अधीन परिभाषित किया गया है, जब यह निष्कर्ष निकलता है कि आपात अधिग्रहण की आवश्यकता – धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत आने वाले प्रयोजनों के लिए और जब इसके निहितार्थ का अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा (1) के उपधारा (क) के अधीन उपबंधित अधिनियम के अनुप्रयोग के प्रयोजनों के साथ प्रत्यक्ष प्रभाव और संबंध है।मेरा विचार है कि देश के रक्षा उद्देश्यों को चालक की सीट प्राप्त होती है, और यह मुख्य रूप से 2013 के अधिनियम के सभी प्रतिबंधात्मक इरादों को ओवरराइड करेगा, क्योंकि यह संवैधानिक इरादे के विपरीत है, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए या यहां तक कि समाज के एक वर्ग के अधिकार के लिए भी, क्योंकि इस न्यायालय का विचार है कि किसी भी व्यक्तिगत अधिकार या यहां तक कि सार्वजनिक अधिकारों को किसी भी समय देश

की रक्षा के अधिकार से बेहतर अधिकार नहीं माना जा सकता है, जिसके कारण, हम सभी नागरिक शांति से संपन्न हो रहे हैं, क्योंकि देश के हमारे सीमावर्ती क्षेत्र, हमारी वीर समूह और अर्धसैनिक कर्मियों के सुरक्षित हाथों में हैं।भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी यही इरादा किया गया है।

19. उस घटना और संदर्भ में, 2013 के अधिनियम की **धारा** 21 और **धारा** 40 का संदर्भ, यहां नीचे निकाले जाने के लिए प्रासंगिक हो जाता है; क्योंकि दी गई परिस्थितियों के तहत, विशेष रूप से जब अधिसूचना 2013 के अधिनियम की **धारा** 9 के प्रकाश में है, और विशेष रूप से, जब यह 2013 के अधिनियम की **धारा** 21 और **धारा** 40 के निहितार्थ को कम करता है, और काफी तार्किक रूप से भी, जब भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से देश की रक्षा के लिए और हमारी रक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की सीमा चौकियों की स्थापना के लिए है। पड़ोसी दुश्मन देश से मातृभूमि।2013 के अधिनियम की **धारा** 21 और 40 को नीचे निकाला गया हैः–

> "21. इच्छुक व्यक्तियों को सूचित करें।– (1) कलेक्टर अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा और ली जाने वाली भूमि पर या उसके निकट सुविधाजनक स्थानों पर

सार्वजनिक सूचना देगा, जिसमें कहा गया है कि सरकार भूमि का कब्जा लेने का इरादा रखती है, और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए क्षतिपूर्ति और पुनर्वास और पुनर्वास का दावा उसे किया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सार्वजनिक सूचना में इस प्रकार अपेक्षित भूमि का विवरण दिया जाएगा और भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता या अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर के समक्ष सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित समय और स्थान पर उपस्थित हों जो सूचना के प्रकाशन की तारीख के तीस दिन से कम और छह महीने से अधिक न हो और भूमि में उनके संबंधित हितों की प्रकृति और ऐसे हितों के लिए मुआवजे के उनके दावों की राशि और विवरण, धारा 20 के तहत किए गए मापों पर उनकी आपत्तियों के साथ-साथ पुनर्वास और पुनर्वास के उनके दावे, यदि कोई हों, का उल्लेख किया जाए।

(3) कलेक्टर किसी भी मामले में उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसे कथन को पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा लिखित रूप में और हस्ताक्षरित किए जाने की अपेक्षा कर सकता है।

(4) कलेक्टर ऐसी भूमि के अधिभोगकर्ता, यदि कोई हो, और ऐसे सभी ज्ञात या इच्छुक माने जाने वाले व्यक्तियों को भी

इसी प्रभाव का नोटिस देगा। उसमें, उस राजस्व जिले के भीतर, जिसमें भूमि स्थित है, इस तरह के इच्छुक व्यक्तियों के लिए कार्य करने का हकदार होगा, जो रहते हैं या उनकी ओर से सेवा प्राप्त करने के लिए अधिकृत एजेंट हैं।

(5) यदि ऐसा इच्छुक कोई व्यक्ति अन्यत्र रहता है और उसका कोई अभिकर्ता नहीं है तो कलेक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सूचना डाक द्वारा उसके अंतिम ज्ञात निवास, स्थान या व्यवसाय के पते पर उसे संबोधित पत्र में भेजी जाएगी और उसे कम से कम दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में और उसकी वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा।

40. कुछ मामलों में भूमि अधिग्रहण की तात्कालिकता के मामले में विशेष शक्तियाँ।– (1) तात्कालिकता के मामलों में, जब भी उपयुक्त सरकार ऐसा निर्देश देती है, कलेक्टर, हालांकि ऐसा कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है, **धारा** 21 में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से तीस दिनों की समाप्ति पर, किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक किसी भी भूमि का कब्जा ले सकता है और उस पर ऐसी भूमि सभी बाधाओं से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से सरकार में निहित होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन समुचित सरकार की शक्तियां संसद के अनुमोदन से भारत की रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा या प्राकृतिक आपदाओं या किसी अन्य आपात स्थिति से उत्पन्न होने वाली किसी आपात स्थिति के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्र तक सीमित रहेंगीः

बशर्ते कि कलेक्टर इस उप–धारा के तहत किसी भी भवन या भवन के हिस्से का कब्जा कम से कम उसके अधिभोगकर्ता को दिए बिना नहीं लेगा ऐसा करने के उसके इरादे की अड़तालीस घंटे की सूचना, या ऐसी लंबी सूचना जो ऐसे अधिभोगकर्ता को अनावश्यक असुविधा के बिना ऐसी इमारत से अपनी चल संपत्ति को हटाने में सक्षम बनाने के लिए उचित रूप से पर्याप्त हो सकती है।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी भूमि का कब्जा लेने से पहले कलेक्टर अस्सी प्रतिशत का भुगतान करेगा।ऐसी भूमि के लिए मुआवजे का, जैसा कि उसके द्वारा उसके हकदार इच्छुक व्यक्ति को अनुमानित किया गया है.

(4) किसी ऐसी भूमि की दशा में, जिस पर समुचित सरकार की राय में उप**धारा** (1), उप**धारा** (2) या उप**धारा** (3) के उपबंध लागू होते हैं, समुचित सरकार यह निदेश दे सकेगी कि अध्याय 6 के अध्याय 2 के उपबंधों में से कोई या सभी उपबंध लागू नहीं होंगे और यदि वह ऐसा निदेश देती है तो **धारा** 11 की उप**धारा** (1) के अधीन प्रारंभिक

अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् किसी समय भूमि के संबंध में घोषणा की जा सकेगी।

(5) पचहत्तर प्रतिशत का अतिरिक्त मुआवजा।**धारा** 27 के अधीन यथा अवधारित कुल प्रतिकर का संदाय कलेक्टर द्वारा भूमि और संपत्ति के संबंध में किया जाएगा, जिनके अर्जन के लिए इस **धारा** की उप**धारा** (1) के अधीन कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं:

बशर्ते कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और रणनीतिक हितों या विदेशी राज्यों के साथ संबंधों को प्रभावित करने वाली परियोजना के मामले में किसी अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।"

20. याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि 1 अगस्त, 2015 की अधिसूचना में एक और विसंगति है, कि **धारा** 11 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की कार्यवाही के चरण के बाद, इसमें बाद में आपत्तियों की सुनवाई निहित थी, जैसा कि **धारा** के तहत प्रदान किया गया है 2013 के अधिनियम के 15 का अनुपालन नहीं किया गया था, उन्हें प्रदान नहीं किया गया था, और इसलिए, यह स्वयं ही पूरी अधिग्रहण कार्यवाही को कम कर देगा।जहां तक अधिग्रहण आदेशिका की **धारा** 15 के प्रभाव का संबंध है, इसके लिए किसी संदर्भ की आवश्यकता नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली

शक्ति के असाधारण प्रयोग में, जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों को सुने बिना भी भूमि का अधिग्रहण करने के लिए किया जा सकता था, इसका प्रयोग निरीक्षण में किया जाना है, जो भूमि मालिकों को अपने व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने और सार्वजनिक अधिकारों या सार्वजनिक हित की कीमत और जोखिम पर बहुत सीमित शक्ति देता है, और वह भी जब यह राष्ट्र और विशेष रूप से सार्वजनिक हित से संबंधित है, जब यह राष्ट्र की रक्षा में वृद्धि की सीमा की ओर ले जाता है। आपत्ति की सुनवाई, जो कि तब भी थी जब यह आपत्ति के क्षेत्रों तक सीमित थी, 2013 के अधिनियम की **धारा** 15 की उप–**धारा** (1) के तहत प्रदान की गई थी।2013 के अधिनियम की **धारा** 15 के तहत सुनवाई के लिए खुली और सीमित रखी गई आपत्तियों के क्षेत्र इस प्रकार हैं:–

"15. आपत्तियों की सुनवाई।– **(1) धारा** 11 की उप**धारा** (1) के अधीन अधिसूचित की गई किसी भूमि में रुचि रखने वाला कोई व्यक्ति, जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अपेक्षित या अपेक्षित होने की संभावना है, 60 के भीतर प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिन, आपत्ति –

(a) अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का क्षेत्र और उपयुक्तता;

(b) सार्वजनिक उद्देश्य के लिए दिया गया औचित्य;

(c)सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के परिणाम।"

21. इस न्यायालय की राय है कि विभिन्न शीर्षों के तहत आपत्तियों की सुनवाई का क्षेत्र, जो 2013 के अधिनियम की **धारा** 15 के तहत प्रदान किया गया था, को आकर्षित नहीं किया जाएगा या इसकी प्रयोज्यता नहीं होगी, क्योंकि 08.08.2015 की अधिसूचना में व्यक्त किया गया उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे बॉर्डर आउट पोस्ट की स्थापना के लिए था, जो एक ऐसा पहलू नहीं होगा, जिसे कार्यकारी या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अटकलों और मूल्यांकन के लिए बिल्कुल भी खुला रखा जा सकता है, क्योंकि इसकी जांच केवल रक्षा बलों के अधिकारियों द्वारा सशस्त्र कर्मियों की तैनाती या उनकी सीमा चौकियों की स्थापना की उनकी आवश्यकता के मुकदमा की जा सकती है, जिसे कार्यकारी द्वारा मूल्यांकन के लिए खुला नहीं छोड़ा जा सकता है, और राय के अनुसारअधिनियम की **धारा** 15 के तीसरे **धारा** (ग) के प्रभाव पर आते हुए, यह तत्काल मामले की परिस्थितियों में लागू नहीं होगा, क्योंकि 2013 के अधिनियम की **धारा** 2 (1) (क) को **धारा** 9 के साथ पढ़ा जाएगा। पहले ही निपटाया जा चुका है, जिसने 2013 के अधिनियम की **धारा** 40 की प्रयोज्यता को छूट दी थी।

22. इस मुद्दे पर विस्तार से बताते हुए, जिसे याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा केवल और विशेष रूप से तर्क दिया गया है, **धारा** 15 के

गैर–अनुपालन के प्रभाव के संबंध में, आपत्तियों की सुनवाई और **धारा** 21 के तहत नोटिस जारी करने के संबंध में, इच्छुक व्यक्तियों को दिया जाना है।वास्तव में, यदि **धारा** 21 के बजाय **धारा** 21 के अनुपालन की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है, तो यह **धारा** 40 (1) के तहत निहित प्रावधानों का हिस्सा है, जो एक नोटिस प्रदान करने के पहलू से संबंधित है; समाचार पत्रों में नोटिस के प्रकाशन के माध्यम से, जिसका तत्काल मामले में प्रतिवादीओं द्वारा 27 अगस्त 2015 को "दैनिक जागरण" में एक प्रकाशन जारी करके सहारा लिया गया था।लेकिन, 2013 के अधिनियम की धारा 15 और 21 के गैर अनुपालन के आरोप का संबंध है, इस न्यायालय का विचार है कि यह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने आवेदन में स्वतंत्र नहीं है, विशेष रूप से, 2013 के अधिनियम के कारण के विवरण (एसओआर) के तहत प्रदान किए गए इरादे के कारण, यदि इसे ध्यान में रखा जाता है, विशेष रूप से जब यह "सार्वजनिक उद्देश्य" के पहलू से संबंधित होता है, तो इसे व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, ताकि भूमि अधिग्रहण में सरकारी हस्तक्षेप देश की रक्षा आवश्यकता तक सीमित हो सकता है, ताकि कम से कम प्रभावित परिवारों की सहमति सुनिश्चित हो सके, लेकिन एक तात्कालिक **धारा** के तहत अधिग्रहण भी राष्ट्रीय रक्षा, सुरक्षा उद्देश्यों, प्राकृतिक आपदाओं के उद्देश्यों के लिए इसकी प्रयोज्यता में सीमित था। जो अधिनियम के तहत अपवाद हैं, और यही कारण है कि, की परिभाषा

"सार्वजनिक प्रयोजन", जैसा कि अधिनियम में दिया गया है, हालांकि इसके अनुप्रयोग में यह काफी व्यापक है, जहां इसमें सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे का अधिग्रहण शामिल है, लेकिन मेरे विचार से भी, यह देश की रक्षा की आवश्यकता को शामिल नहीं करेगा।

23. मामले का यह पहलू 2013 के अधिनियम की **धारा** 2 (1) (ए) के तहत निहित प्रावधानों द्वारा भी पुष्ट और प्रमाणित है, जहां किसी भी काम के लिए सैन्य या अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता को पूरा करने के संबंध में एक अपवाद पहले ही तैयार किया जा चुका है; जो राष्ट्रीय सुरक्षा या भारत की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।**धारा** 2 (1) (ए) के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में, यदि **धारा** 9 के विधायी उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है, जिसे पहले ही ऊपर निपटा दिया गया है, तो **धारा** 40 की प्रयोज्यता को लागू करने से छूट दी गई है, जो अपने आप में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के आवेदन को समाप्त कर देती है, और एक बार जब 2013 के अधिनियम की **धारा** 9 को ध्यान में रखा जाता है; 2013 के अधिनियम की **धारा** 40 के तहत तत्काल प्रावधान ने सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के मूल्यांकन को छूट दी है, और यदि उप–**धारा** के लिए संदर्भ दिया जाता है यह **धारा** 40 की **धारा** 21 के तहत नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों का नोटिस प्रदान करता है और इसमें अंततः, जब

धारा 40 स्वयं धारा 21 के प्रभाव को शामिल करती है, जिसे 2013 के अधिनियम की धारा 9 को लागू करके ओवरराइड किया गया था, जिसे 2013 के अधिनियम की धारा 9 के तहत निहित प्रावधानों द्वारा लागू करने से छूट दी गई है, तो धारा 21 या अधिनियम की धारा 40 के तहत निहित प्रावधानों के गैर–अनुपालन के याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क बन जाता है। मौजूदा मामले की परिस्थितियों में विचार के लिए अप्रासंगिक है।

24. हालांकि हाल के एक फैसले में देश की रक्षा की आवश्यकता पर अप्रत्यक्ष रूप से विचार किया गया है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीवानी याचिका सं 2018 का 10930, ग्रीन डून्स और अन्य के लिए नागरिक बनाम भारत संघ और अन्य, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 14 दिसंबर 2021 को विविध आवेदन सं. 2020 का 1925, उक्त सिविल अपील में दायर किया गया, हालांकि उक्त मामले में विवाद का पाठ उत्तराखंड राज्य में "चार धाम यात्रा" सड़क के निर्माण से संबंधित था।उपर्युक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग, जिसके साथ हम अधिक चिंतित होंगे, रक्षा आवश्यकता के पहलू से संबंधित होगा और विशेष रूप से, वह क्षेत्र जिसके साथ मौजूदा अधिसूचना का संबंध है i.e. पिथौरागढ़ जिला, जो चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है।इसलिए, इसके स्थलाकृतिक और पर्यावरणीय प्रभाव और इससे संबंधित मुद्दा का आकलन करते हुए, निष्कर्ष में इसके निष्कर्षों के

साथ–साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए विश्लेषण में, उक्त निर्णय में, यह इंगित किया गया था कि सड़कों का निर्माण और विशेष रूप से, उक्त मामले में चार धाम यात्रा सड़क, रक्षा आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्यों के लिए अधिक प्रासंगिक थी, क्योंकि यह देश के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और इसके संदर्भ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पैरा 45 में, जो यहां निकाला गया है, महत्व निर्धारित किया है और विचार किया है, कि क्यों अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ, समूह की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं को विकसित करने के उद्देश्यों के लिए सामरिक और रणनीतिक रूप से प्रासंगिक होंगी, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक पूरक मार्ग के रूप में भी कार्य करती हैं।वास्तव में, यह मुद्दा जो मौजूदा रिट याचिका में निहित है, भी टिप्पणियों की उक्त उत्पत्ति से संबंधित होगा, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में की गई थी।उसी का पैरा **45** नीचे निकाला गया है:–

> "विचार के लिए जो मुद्दा उठता है, वह तीन रणनीतिक सीमा सड़कों के लिए अपनाई जाने वाली सड़क–चौड़ाई के बारे में है, जैसा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर 2020 के एमए नंबर 2180 में संकेत दिया गया है, अर्थात्:ऋषिकेश से गंगोत्री (एनएच–94 और एनएच–108), ऋषिकेश से माना (एनएच–**58**) और टनकपुर से पिथौरागढ़ (एनएच–125)।मोटे तौर पर,

अपीलार्थियों ने तर्क दिया है कि मौजूदा सड़क अवसंरचना भारतीय समूह की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।यह आग्रह किया गया है कि आगे किसी भी विकास को हिमालय की नाजुकता, पर्यावरण को होने वाले अत्यधिक नुकसान और आपदा–प्रतिरोधी सड़कों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संतुलित किया जाना चाहिए।दूसरी ओर, यूओआई ने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इन फीडर सड़कों को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।यूओआई के अनुसार, भारत–चीन सीमा की सड़कों की निकटता और भारतीय समूह के ट्रकों, मशीनों, उपकरणों और कर्मियों के परिवहन के लिए मुक्त आवाजाही की आवश्यकता को देखते हुए, डबल लेन विन्यास की अनुमति दी जानी चाहिए। इस मुद्दे का विश्लेषण करने के लिए, हम पहले एचपीसी के परिणाम का विज्ञापन करेंगे।

25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में अभिलिखित किया है कि सड़कों को बिछाने के प्रयोजनों के लिए भूमि का चयन, इसका चौड़ीकरण हालांकि यह भू–भाग वर्गीकरण, भू–मीट्रिक डिजाइन, गति के डिजाइन, दृष्टि दूरी या दृश्यता से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित है, विभिन्न पहलू हैं, जिन पर उच्च शक्ति समिति की रिपोर्ट के

अध्याय–II द्वारा विचार किया गया था, जो चार धाम यात्रा रोड के निर्माण से संबंधित था।पैरा 52 में उच्च शक्ति समिति के सदस्यों के बहुमत के दृष्टिकोण के आधार पर, इसने अपने पैरा 52 (iii) और (iv) में वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे सीमावर्ती सड़कों की भेद्यता और संवेदनशील क्षेत्र के लिए इसकी आवश्यकता के बारे में समाधान किया था, और इसलिए, 2019 भारतीय सड़क कांग्रेस दिशानिर्देशों के संकल्प के अनुसार भी, इसने सैन्य और अर्धसैनिक बलों के लिए उपयुक्त रणनीतिक सीमा सड़कें प्रदान करने पर जोर दिया था।पैरा 52 (iii) का सुसंगत भाग और

(iv) उपर्युक्त सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सार नीचे दिया गया है:–

"52.

.....

(iii) परियोजना के कुछ राजमार्ग सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर जाने वाली महत्वपूर्ण फीडर सड़कें हैं।बी. आर. ओ. ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि सीमावर्ती क्षेत्रों का भूभाग बर्फ से घिरे क्षेत्र में है और हेलोंग–माना और बरेठी–गंगोत्री जैसे फीडर मार्गों को दोहरी लेन वाला होना चाहिए।इसके अलावा, जोशीमठ और उत्तरकाशी से आगे की सड़कें परिचालन के लिहाज से संवेदनशील हैं और इसके दायरे में आती हैं 100 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्ट

नियंत्रण करें।सर्दियों के मौसम में सिंगल–लेन सड़कें बंद हो जाती हैं क्योंकि बर्फ का संचय और भारतीय सेना को रसद और चिकित्सा सहायता की आवाजाही में बाधा;

(iv) 2019 आईआरसी दिशानिर्देशों में यह भी सुझाव दिया गया है कि सैन्य और अर्धसैनिक बलों के लिए रणनीतिक सीमा सड़कें पक्की कंधों के साथ दो लेन से कम न हों; और

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पैरा 60 में उक्त निर्णय में, जब वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निकटता और निकटता के पहलू के संबंध में विचार कर रहा था, क्योंकि यह गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा निपटा गया एक मुद्दा था, पिथौरागढ़ से लिपु लेख दर्रे तक सीमावर्ती क्षेत्रों की पहुंच से संबंधित अपने निष्कर्ष में, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा तक पहुंच के **धारा** के पैच में भी आता है, जिसके साथ हम चिंतित हैं, जिसके लिए अधिसूचना के तहत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि को भी देश की रक्षा की संभावना से ध्यान में रखा गया था।इसलिए, उक्त आवश्यकता का समापन करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 14.12.2021 के अपने निर्णय में, पैरा 63,64 और 65 में इसकी आवश्यकता के बारे में टिप्पणी की थी, जिसे यहां भी निकाला गया हैः

"63. शुरुआत में, इसलिए, हम पाते हैं कि रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर 2020 के एमए नंबर 2180 में कोई दुर्भावना नहीं है। यह आरोप कि रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर आवेदन मामले को फिर

से मुकदमा करने या इस न्यायालय के पिछले आदेश को पलटने का प्रयास करता है, निराधार है क्योंकि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के विशेष निकाय के रूप में, संचालन पर निर्णय लेने का हकदार है।

सशस्त्र बलों की आवश्यकताएँ।इन आवश्यकताओं में सैनिकों, उपकरणों और मशीनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा सहायता शामिल है।रक्षा मंत्रालय की ईमानदारी इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि एचपीसी की चर्चा के दौरान सुरक्षा चिंताओं का मुद्दा उठाया गया था और एचपीसी रिपोर्ट में इसका उल्लेख मिलता है।इस प्रकार, रक्षा मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा चिंताओं को पूरा करने के लिए दो लेन वाली सड़कों की आवश्यकता को बनाए रखा है।

64 अपीलकर्ताओं ने सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही के लिए बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता के संबंध में 2019 में एक मीडिया साक्षात्कार में समूह प्रमुख द्वारा दिए गए एक बयान का उल्लेख किया है। एचपीसी और इस अदालत के समक्ष विचार–विमर्श के दौरान रक्षा मंत्रालय के निरंतर रुख को देखते हुए हमें मीडिया को दिए गए बयान पर भरोसा करना आवश्यक नहीं लगता है।रक्षा मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन की गई सुरक्षा चिंताएं समय के साथ बदल सकती हैं।हाल के दिनों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियों को

जन्म दिया है।सशस्त्र बलों को 2019 में एक मीडिया बातचीत के दौरान दिए गए एक बयान के लिए नहीं रोका जा सकता है जैसे कि यह पत्थर में एक डिक्री रिट था।इसी तरह, अपीलकर्ताओं ने 2020 के एम. ओ. आर. टी. एच. परिपत्र को भी चुनौती दी है और एक निर्देश की मांग की है कि इस बौद्धिक प्रयोज्यता आधार पर निरस्त किया जाए कि यह बिना सोचे समझे डी. एल.–पी. एस. मानक की सिफारिश करता है।

65 यह न्यायालय, न्यायिक समीक्षा के अपने अभ्यास में, सशस्त्र बलों की अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं का अनुमान नहीं लगा सकता है।अपीलार्थी इस न्यायालय से यह अभिनिर्धारित कराएंगे कि समूह की आवश्यकता को एक छोटे आयाम की आपदा प्रतिरोधी सड़कों द्वारा बेहतर ढंग से पूरा किया जाएगा।द. अपीलार्थियों को प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय को देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए समूह और रक्षा मंत्रालय द्वारा तय किए गए तौर–तरीकों को ओवरराइड करने की आवश्यकता होती है (यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एमओआरटीएच ने रक्षा मंत्रालय से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर 2020 एमओआरटीएच परिपत्र जारी किया था)।अपीलार्थियों के प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय को उस प्रतिष्ठान की नीतिगत पसंद से

पूछताछ करने की आवश्यकता होती है जिसे कानून द्वारा राष्ट्र की रक्षा के लिए सौंपा गया है।यह अस्वीकार्य है।"

27. यह कि सैन्य कर्मियों के लिए सुलभ सड़कों या सुलभ मार्ग की आवश्यकता और महत्व, विचार के एक विशेष क्षेत्र के भीतर होगा, जिसे रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रभावी और निर्णायक रूप से किया जाना है और सशस्त्र बलों की उक्त सैन्य परिचालन आवश्यकता की न्यायिक समीक्षा, अदालतों द्वारा विचार के विषय के रूप में नहीं की जा सकती है, क्योंकि वे सैनिकों, उपकरणों, गोला–बारूद और भारी मशीनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए बुनियादी ढांचे की सहायता की आवश्यकता से निपटने के लिए कौशल से लैस नहीं हैं, जो विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय और सक्षम समूह अधिकारियों की चिंता है।इसलिए, फैसले के पैरा 65 में विशिष्ट अवलोकन किया गया है, जिसे ऊपर निकाला गया है, कि यह विशेष रूप से रक्षा कर्मियों और रक्षा मंत्रालय की नीतिगत पसंद है कि वे अपनी आवश्यकता का चयन करें, और जिस तरह से इसे सबसे अच्छा पूरा किया जा सकता है, और विशेष रूप से, 2019 के निर्णय का संदर्भ देते हुए, भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशानिर्देशों द्वारा लिया गया, विशेष रूप से **धारा** 6.2 के तहत निहित।2 (8) सैन्य और अर्धसैनिक सुरक्षा बलों, सैन्य अभियानों और आंदोलनों के लिए रणनीतिक और सीमा सड़क पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए ताकि देश का अस्तित्व

अपने आप ठीक होना सुरक्षित हो सके और पर्यावरण के मुद्दा के नाजुक संतुलन पर मामूली विचलन को सख्ती से समझा जा सके और इस अवलोकन के साथ देखा जाए कि वे मुद्दा विशेष रूप से रणनीतिक राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्र ठीक होना बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता को बाधित नहीं करेंगे, जो भारत और चीन के बीच साझा वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

28. जहाँ तक चीन से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ साझा किए जा रहे सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्र का संबंध है, इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एनएच–125 के दृष्टिकोण से निपटाया गया था, जो पिथौरागढ़ जिले से संबंधित है, जिससे हम संबंधित हैं।मौजूदा रिट याचिका में, जहां अधिग्रहण अधिसूचना को चुनौती दी गई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के पैरा 79 में कहा है कि टनकपुर से पिथौरागढ़ तक सड़क की पहुंच सैन्य प्रासंगिकता और देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी, और छोटे पर्यावरणीय मुद्दे होंगे, हालांकि कुछ नियंत्रण और संतुलन को रणनीतिक रूप से बनाए रखना होगा, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर समझौते के साथ नहीं।माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का पैरा 79 इस प्रकार हैः

"79. इस अदालत के दिनांक 8 सितंबर 2020 के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 2018 एमओआरटीएच इस बात

की परवाह किए बिना कि राजमार्ग पर काम पूरा हो गया था या चल रहा था, परिपत्र क्षेत्र को पकड़ेगा।इस आदेश के संशोधन के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर एमए को अनुमति देकर, हमने ऋषिकेश से माना, ऋषिकेश से गंगोत्री और टनकपुर से पिथौरागढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने की अनुमति दी है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए रणनीतिक फीडर रोड हैं।इस हद तक, 8 सितंबर 2020 के आदेश को संशोधित किया जाएगा। हालांकि, हम प्रतिवादीओं को उचित कानूनी कार्यवाही करने और पूरी परियोजना के लिए डीएल–पीएस मानक को लागू करने के लिए आवश्यक होने की स्थिति में राहत पाने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।"

29. इसलिए, मेरा विचार है कि किसी आपत्ति की सुनवाई के लिए **धारा 15** का मूल आशय, विशेष रूप से सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के प्रभाव पर सीमित है, जैसा कि 2013 के अधिनियम के अध्याय–II के तहत परिकल्पित है, यह किसी व्यक्ति के अधिकारों की आत्यन्तिक रूप से रक्षा नहीं करता है, जैसे कि भूमि के मालिक को प्रतिरक्षा दी गई है, विशेष रूप से जब यह वास्तविक तात्कालिकता को कम करता है और देश की रक्षा की आवश्यकता से संबंधित है, जिसके लिए समूह या अर्ध–सशस्त्र बलों की रक्षा आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिग्रहित

की गई भूमि का तत्काल कब्जा आवश्यक है।**धारा** 15 के तहत जांच को समाप्त करने या अवसर प्रदान करने की यह छूट एक पहलू था, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले में विचार किया गया था जैसा कि **(2013) 3** एससीसी **764,** लक्ष्मण लाल बनाम राजस्थान राज्य में रिपोर्ट किया गया था, जिसने केवल वास्तविक तात्कालिकता के योग्य मामलों में जांच को समाप्त करने के लिए पैरामीटर निर्धारित किए थे और उक्त द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निर्णय, जिसके प्रासंगिक पैराग्राफ यहाँ निकाले गए हैं।

30. लक्ष्मण लाल (सुप्रा) के उक्त मामले में, प्रारंभिक मुद्दा, जिसे इसमें चुनौती दी गई थी, 1 सितंबर, 1980 की अधिसूचना के लिए था, [जिसे] तब तत्कालीन भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत **धारा** 4 के तहत जारी किया गया था, जहां बस स्टैंड के निर्माण के लिए सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए विषय भूमि की आवश्यकता थी।इसके परिणामस्वरूप, **धारा** 6 के तहत एक अधिसूचना 19 मार्च, 1987 को जारी की गई [थी,] जिसके द्वारा, **धारा** 17 के तहत तात्कालिक **धारा** को उपयोग करना किया गया था, जिसमें जांच की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था, जो उक्त अधिनियम की **धारा** 5 (ए) के तहत निहित और विचार किया गया था।

31. लक्ष्मण लाल (सुप्रा) के उक्त निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "प्रतिष्ठित क्षेत्र" के सिद्धांत के संदर्भ में सार्वजनिक अनिवार्यता को पूरा करने के राज्य के अधिकार पर विचार करते हुए कहा है कि यह हमेशा अधिकार और शक्ति है, जो विशेष रूप से राज्य के संप्रभु क्षेत्र में निहित है कि वह जनता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भूमि प्राप्त करने की क्षेत्रीय संप्रभुता की अपनी शक्ति के दायरे में अपनी अनन्य शक्ति का प्रयोग करे और प्रतिष्ठित क्षेत्र को संप्रभुता की विशेषता और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए संप्रभु सरकार का एक आवश्यक तत्व माना गया है, और इसलिए, प्रतिष्ठित क्षेत्र का सिद्धांत, सार्वजनिक हित, जनता के लिए सामान्य कल्याण और विशेष रूप से मौजूदा मामले के संदर्भ में पड़ता है, जिसमें आवश्यकता होती है। किसी भी संभावित भविष्य या मौजूदा दुश्मन के खतरों को दूर करने के लिए अर्धसैनिक बल के कर्मी, जिसके लिए पूर्व तैयारी भी महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, जिसे रक्षा कर्मियों के लिए भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्यों के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्राधिकारी में उक्त निर्णय के पैरा 15,16 और 21 में "प्रमुख क्षेत्र" के उपरोक्त सिद्धांत के संबंध में प्रासंगिक टिप्पणियां की गई थीं, जो यहां निकाली गई हैंः

> "15. 1953 के अधिनियम में निहित अनिवार्य अधिग्रहण के वैधानिक प्रावधान 1894 के अधिनियम से भौतिक रूप से

अलग नहीं हैं। इस न्यायालय ने मामलों की श्रृंखला में प्रतिष्ठित क्षेत्र के सिद्धांत की व्याख्या की है।प्रमुख क्षेत्र एक संप्रभु राज्य का अधिकार या शक्ति है जो क्षेत्रीय संप्रभुता के भीतर निजी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग या उद्देश्यों के लिए उपयुक्त बनाता है।यह संप्रभुता की विशेषता है और संप्रभु सरकार के लिए आवश्यक है। प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्ति, सरकार में निहित होने के कारण, सार्वजनिक हित, सामान्य कल्याण और सार्वजनिक उद्देश्य के लिए प्रयोग की जा सकती है।संप्रभु को राज्य की भूमि के किसी भी हिस्से पर अपने प्रभुत्व को फिर से स्थापित करने का अधिकार है, जिसमें उसके मालिक की सहमति के बिना निजी संपत्ति भी शामिल है, बशर्ते कि ऐसा दावा सार्वजनिक आवश्यकता के कारण और सार्वजनिक भलाई के लिए हो।

16. संविधान का अनुच्छेद 300–ए आदेश देता है किः

"300–ए। कानून के अधिकार के अलावा संपत्ति से वंचित नहीं होने वाले व्यक्ति।कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।"

हालाँकि संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन संवैधानिक संरक्षण जारी है क्योंकि कानून के अधिकार के बिना, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है।तदनुसार, यदि राज्य अनिवार्य अधिग्रहण के लिए वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्य करके मालिकों की सहमति के

बिना निजी संपत्ति का उपयोग करने का इरादा रखता है, तो कानून द्वारा अधिकृत प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से और अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए।तात्कालिकता की शक्ति जो आपत्तियां दायर करने के अधिकार को छीन लेती है, उसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा केवल वास्तविक तात्कालिकता के ऐसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है जो कुछ हफ्तों या कुछ महीनों की देरी को रोक नहीं सकता है।इस न्यायालय ने 1964 में ही कहा था कि **धारा** 5–क के अधीन आपत्ति दर्ज करने का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है जब किसी व्यक्ति की संपत्ति को अधिग्रहण के द्वारा खतरे में डाला जा रहा है; ऐसा अधिकार इस प्रकार नहीं लिया जा सकता है जैसे कि एक साइड विंड द्वारा (नंदीश्वर प्रसाद बनाम U.P. राज्य)। 21. आनंद सिंह को बाद के मामलों में संदर्भित किया गया है, ऐसे निर्णयों में से एक राधेश्याम बनाम U.P. राज्य है। जहां इस न्यायालय ने रिपोर्ट के पैरा 77 (v) से (ix) में निम्नलिखित कथन किया है:(राधेश्याम मामला, एस. सी. सी. पृष्ठ 603) "77. (v) **धारा** 17 (4) के साथ पठित **धारा** 17 (1) राज्य को **धारा** 5–क के अधिदेश का अनुपालन किए बिना निजी संपत्ति अर्जित करने की असाधारण शक्ति प्रदान करती है। इन प्रावधानों को केवल तभी उपयोग करना किया जा सकता है जब अधिग्रहण का उद्देश्य कुछ हफ्तों या महीनों की देरी को रोक नहीं सकता है।इसलिए, **धारा** 5–क के आवेदन को हटाने से पहले, संबंधित प्राधिकारी को पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि **धारा** 5–क के तहत जांच करने में लिए जाने वाले कुछ हफ्तों या महीनों का समय, सभी संभावनाओं में, उस सार्वजनिक उद्देश्य को विफल कर देगा जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है।

(vi) तात्कालिकता के मुद्दे पर सरकार की संतुष्टि व्यक्तिपरक है, लेकिन **धारा** 17 (1) के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती है और इसे इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि जिस उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण किया जाना है वह बिल्कुल भी सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है या कि शक्ति का प्रयोग दुर्भावना के कारण दूषित किया जाता है या कि संबंधित अधिकारियों ने प्रासंगिक कारकों और अभिलेखों पर अपना दिमाग नहीं लगाया।

(vii) **धारा** 17 (1) के तहत सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से अधिनियम की **धारा** 5–ए का अपवर्जन नहीं होता है, जिसके संदर्भ में भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति आपत्ति दर्ज कर सकता है और अपनी आपत्ति के समर्थन में सुनवाई का हकदार है।**धारा** 17 की उप**धारा** (4) में 'मे' शब्द का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि यह केवल सरकार को यह निदेश देने में समर्थ बनाता है कि **धारा** 5–क के उपबंध **धारा** 17 की उप**धारा** (1) या (2) के अधीन आने वाले मामलों पर लागू नहीं होंगे।दूसरे शब्दों में, **धारा** 17 (4) का आह्वान **धारा** 17 (1) के तहत शक्ति के प्रयोग का एक आवश्यक सहवर्ती नहीं है।

(viii) आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण को **धारा** 4 के अर्थ के भीतर सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अधिग्रहण के रूप में माना जा सकता है, लेकिन यह अपने आप में **धारा** 17 (1) और/या 17 (4) के तहत सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग को उचित नहीं ठहराता है। न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकता है कि आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत क्षेत्रों के विकास से संबंधित योजनाओं की योजना, निष्पादन और कार्यान्वयन में आमतौर पर कुछ साल लगते हैं।इसलिए, **धारा** 17 (1) में निहित तात्कालिक प्रावधान को लागू करके ऐसे उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है।किसी भी मामले में, ऐसे मामलों में धारा 5–क (1) और (2) में सन्निहित ऑडी

अल्टेराम दूसरे पक्ष को भी सुनो नियम का अपवर्जन बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है।

(ix) यदि भूमि का अधिग्रहण निजी व्यक्तियों के लाभ के लिए किया जाता है, तो न्यायालय को धारा 17 (1) और/या 17 (4) के आह्वान को संदेह के साथ देखना चाहिए और ऐसे अधिग्रहण की वैधता पर निर्णय लेने से पहले प्रासंगिक रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए।"" ""

32. अपने पैरा 21 में उक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2011 (5) एससीसी 553, राधेश्याम बनाम यू. पी. राज्य में दिए गए निर्णय में प्रतिपादित अनुपात पर विचार किया गया है, जहां यह देखा गया है कि भूमि अधिग्रहण की **धारा** 17 के तहत तात्कालिकता **धारा** के प्रावधान **धारा** 5 (क) के अधीन परिकलित जांच का वितरण करने वाला अधिनियम, राज्य के साथ शक्ति के असाधारण प्रयोग के अधिकार क्षेत्र में आएगा; एक निजी संपत्ति का अधिग्रहण करना, जहां किसी सार्वजनिक उद्देश्य को विफल करने के लिए देरी नहीं की जा सकती है और विशेष रूप से, जब यह राष्ट्र की रक्षा के संदर्भ में हो।

33. इस न्यायालय का यह मत है कि जो अधिकार 2013 के अधिनियम की **धारा** 15 के अधीन यथा परिकल्पित या संरक्षित किए जाने के लिए अभिप्रेत हैं या अभिप्रेत हैं, जो किसी निजी व्यक्ति द्वारा संरक्षित किए जाने हैं, वे आत्यन्तिक अधिकार नहीं हैं, जिन्हें जनता के अधिकारों की

कीमत पर या राष्ट्र की रक्षा के हित की कीमत पर एक रिट अधिकार क्षेत्र में लागू किया जा सकता है और **धारा** 15 के अधीन सुनवाई के उक्त उन्मूलन को दी गई परिस्थितियों में बहुत अच्छी तरह से अपनाया जा सकता है और पहले से दिए गए कारणों को केवल प्रकृति में निर्देश माना जा सकता है और अनिवार्य नहीं किया जा सकता है, जैसा कि तत्काल मामले में होता है, हालांकि यहां विशेष रूप से तत्काल मामले में निहित तथ्यों के तहत जब अधिसूचना स्वयं, जब यह 2013 के अधिनियम की **धारा** 9 को आकर्षित करती है,

34. एक अन्य परिप्रेक्ष्य, जिसे याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 01.08.2015 की अधिसूचना को चुनौती देने के लिए तर्क देने के लिए आकर्षित किया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के निहितार्थ के दृष्टिकोण से है; संविधान अनुसूचित जनजाति U.P. 1967 का आदेश, जिसठीक होना "भोटिया" जनजातियों के होने का दावा किया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत आने वाली अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित और इसलिए, उन्हें 2013 के अधिनियम की **धारा** 41 के तहत प्रदान की गई शर्तों को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमि के अधिग्रहण से संरक्षित किया जाएगा।2013 के अधिनियम की **धारा** 41 को इसके नीचे निकाला गया हैः–

"41. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान।–

(1) जहां तक संभव हो, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का कोई अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।

(2)जहां ऐसा अधिग्रहण होता है, वह केवल एक प्रदर्शन योग्य अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा।

(3)अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भूमि के अधिग्रहण या परिनियोजन के मामले में, संविधान की पांचवीं अनुसूची के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों में उपयुक्त स्तर पर, यथास्थिति, संबंधित ग्राम सभा या पंचायतों या स्वायत्त जिला परिषदों की पूर्व सहमति, ऐसे क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के सभी मामलों में, जिसमें तात्कालिकता की स्थिति में अधिग्रहण भी शामिल है, इस अधिनियम या किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले प्राप्त की जाएगी।

बशर्ते कि पंचायतों या स्वायत्त जिला परिषदों की सहमति उन मामलों में प्राप्त की जाएगी जहां ग्राम सभा मौजूद नहीं है या इसका गठन नहीं किया गया है।

(4)एक आवश्यक निकाय की ओर से भूमि अधिग्रहण से जुड़ी परियोजना के मामले में जिसमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन शामिल है, एक विकास योजना देय भूमि अधिकारों के निपटान के वचन देना प्रक्रिया का विवरण देते हुए, जो विहित किया जाए, ऐसे प्रपत्र में तैयार किया जाएगा, लेकिन उनका निपटान नहीं किया जाएगा और भूमि अधिग्रहण के साथ एक

विशेष अभियान चलाकर पृथक्कृत भूमि पर अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के अधिकारों को बहाल किया जाएगा।

(5)विकास योजना में पांच वर्षों की अवधि के भीतर गैर–वन भूमि पर वैकल्पिक ईंधन, चारा और गैर–लकड़ी वन उपज संसाधनों के विकास के लिए एक कार्यक्रम भी शामिल होगा, जो जनजातीय समुदायों के साथ–साथ अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।

(6)अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से अधिग्रहित की जा रही भूमि के मामले में, देय मुआवजे की राशि का कम से कम एक तिहाई हिस्सा प्रभावित परिवारों को शुरू में पहली किस्त के रूप में दिया जाएगा और शेष का भुगतान भूमि का कब्जा लेने के बाद किया जाएगा।

(7)अनुसूचित जनजातियों के प्रभावित परिवारों को अधिमानतः उसी अनुसूचित क्षेत्र में एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक में पुनर्स्थापित किया जाएगा ताकि वे अपनी जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रख सकें।

(8)मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा बसे पुनर्वास क्षेत्रों को उस सीमा तक भूमि मिलेगी, जो उपयुक्त सरकार द्वारा सामुदायिक और सामाजिक समारोहों के लिए निःशुल्क तय की जा सकती है।

(9)कुछ समय के लिए कानूनों और विनियमों की अवहेलना में अनुसूचित जातियों के सदस्यों की जनजातीय भूमि या भूमि का कोई अलगाव लागू को शून्य माना जाएगा और ऐसी भूमि के अधिग्रहण के मामले में पुनर्वास और पुनर्वास लाभ मूल आदिवासी भूमि मालिकों या अनुसूचित जातियों से संबंधित भूमि मालिकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

(10)प्रभावित क्षेत्र में नदी या तालाब या बांध में मछली पकड़ने का अधिकार रखने वाली प्रभावित अनुसूचित जनजातियों, अन्य पारंपरिक वनवासियों और अनुसूचित जातियों को सिंचाई या पनबिजली परियोजनाओं के जलाशय क्षेत्र में मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाएगा।

(11)जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रभावित परिवारों को जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाता है, तो उन्हें अतिरिक्त पच्चीस प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।पुनर्वास और पुनर्वास लाभ जिनके लिए वे पचास हजार रुपये की एकमुश्त पात्रता के साथ मौद्रिक शर्तों में हकदार हैं।"

35. उपर्युक्त उपबंधों और 2013 के अधिनियम की **धारा** 41 के विधायी आशय को समग्र रूप से पढ़ने पर, यदि उस पर विचार किया जाए, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विधायिका ने अपनी पूरी विवेक और चेतना में, अपनी उप**धारा** (1) में जहां वह अनुसूचित

जनजातियों और अनुसूचित जाति को सुरक्षा का एक निश्चित कवच प्रदान करने का इरादा रखती थी, 'जहां तक संभव हो' भाषा का उपयोग किया था।धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन इस शब्द का प्रयोग स्वयं धारा 41 के उपबंधों और उसके अधीन प्रदत्त संरक्षण को ऐसा आत्यन्तिक अधिकार नहीं बनाता है जो सृजित किया गया है या जो विहित जाति या जनजातियों को आकस्मिक परिस्थितियों के बावजूद दिया जा सकता है, बशर्ते कि विशेष रूप से, जब अनुसूचित क्षेत्रों में अधिग्रहण करने के लिए कहा जाता है, जो याचिकाकर्ताओं के रुख के अनुसार U.P. द्वारा कवर किया जाता है। 1967 का आदेश।

36. रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अधिग्रहण से प्रतिरक्षा के अपने अधिकारों की घोषणा की थी, क्योंकि उन्होंने अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा किया था, और इसलिए अधिनियम की धारा 41 के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में संरक्षण की मांग की गई थी। अधिनियम की धारा 41 के प्रावधान, इस तथ्य के अलावा कि यह प्रकृति में केवल निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है क्योंकि यह "जहां तक संभव हो" शब्द के साथ शुरू होता है, लेकिन फिर इसकी प्रयोज्यता को केवल "अनुसूचित क्षेत्र" पर लागू करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।"अनुसूचित क्षेत्र" शब्द को धारा 3 (जेड डी) के तहत परिभाषित किया गया है जिसे यहां निकाला गया है:

"(जेड डी)" "अनुसूचित क्षेत्र" "से पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के प्रावधानों की **धारा** 2 में परिभाषित अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत हैं"

37. इसका मतलब है कि एक अनुसूचित क्षेत्र को एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए, जिसे **धारा** के तहत घोषित और परिभाषित किया गया है पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंध।

38. **वास्तव में, रिट अभिलेखों या रिट याचिका में उठाए गए अभिवचनों के अनुसार, एक गंजे दावे को छोड़कर, कि चूंकि याचिकाकर्ता अनुसूचित जनजाति हैं, उन्हें प्रदान किया जाएगा** **धारा** 41 के तहत ढाल के साथ, जिसे मैं पहले ही ऊपर देख चुका हूं, कि यह प्रकृति में निर्देशिका है और राष्ट्र की रक्षा आवश्यकता की तुलना में अनिवार्य नहीं है।याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता के लिए यह और भी आवश्यक था कि वह अपने बहस को साबित करे, जो उसने की अनुपस्थिति में किया है; कोई सामग्री या तर्क को रिकॉर्ड पर रखते हुए, कि कैसे और किस तरीके से, गाँव मिलम, जहाँ भूमि, जिसे प्रस्तावित किया गया है और जिसे अधिग्रहित करने की मांग की गई है, अधिनियम के तहत परिभाषित अनुसूचित क्षेत्रों के दायरे में आती है। इसलिए

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क को तब तक स्वीकार की अनुपस्थिति में किया जा सकता है जब तक कि याचिकाकर्ता दस्तावेजों पर यह तथ्य स्थापित करने में समर्थ की अनुपस्थिति में हो जाता है कि गाँव मिलम 2013 के अधिनियम के अनुसार और भारत के संविधान की 5 वीं अनुसूची के अनुसार भी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। भारत के संविधान की 5 वीं अनुसूची का भाग–सी "अनुसूचित क्षेत्र" से संबंधित है, जिसे राष्ट्रपति एक "अनुसूचित क्षेत्र" घोषित करने के आदेश द्वारा एक क्षेत्र के रूप में देख सकते हैं, लेकिन इस न्यायालय को लगता है कि याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलों की सराहना करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने बहस को साबित करना के लिए रिकॉर्ड पर कोई विश्वसनीय सामग्री रखी जा की अनुपस्थिति में है, कि भूमि अनुसूचित क्षेत्र में आती है, जैसा कि 2013 के अधिनियम की **धारा** 3 (जेडडी) के तहत प्रदान किया गया है, जिसे भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के भाग–सी के साथ पढ़ा जाना है, इसलिए इस तर्क को भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के भाग–सी द्वारा बढ़ाया गया है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता कि मिलम एक अनुसूचित क्षेत्र है, की सराहना नहीं की जा सकती है। वही यहाँ उद्धृत किया गया हैः–

"अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान।

....

6. अनुसूचित क्षेत्र।– (1) इस संविधान में, "अनुसूचित क्षेत्र" पद का अर्थ है ऐसे क्षेत्र जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है।

(2) **राष्ट्रपति किसी भी समय आदेश द्वारा –**

(a)यह निदेश देना कि किसी अनुसूचित क्षेत्र का संपूर्ण या कोई विनिर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा;

(aa) उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद किसी राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ाएँ;]

(b)किसी अनुसूचित क्षेत्र में परिवर्तन, लेकिन केवल सीमाओं के सुधार के माध्यम से;

(c)किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर या संघ में प्रवेश करने या किसी नए राज्य की स्थापना पर, किसी ऐसे क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करें जो पहले किसी राज्य में शामिल नहीं था;

(d) किसी राज्य या राज्यों के संबंध में इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी आदेश या आदेश को निरस्त करके और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से उन क्षेत्रों को पुनर्परिभाषित करते हुए नए आदेश करें जो अनुसूचित क्षेत्र हैं;] और ऐसे किसी आदेश में ऐसे आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान हो सकते हैं जो राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत होते हैं, लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस पैराग्राफ के उप–पैराग्राफ (1) के तहत किए गए आदेश को किसी भी बाद के आदेश से बदला नहीं जाएगा।"

39. इस प्रकार 2013 के अधिनियम की **धारा** 41 का प्रतिबंध अनुसूचित जनजातियों को उनकी भूमि का अधिग्रहण करने के आत्यन्तिक अधिकार और संरक्षण से मुक्त नहीं करता है; क्योंकि **धारा** 41 की उप–**धारा** (2) के तहत, यदि इसे अधिग्रहण के उद्देश्य के अनुसार पढ़ा जाता है, तो इस मामले में, तत्काल मामले में अधिग्रहण को 'अंतिम उपाय' के रूप में माना जाएगा जो राज्य को स्थलाकृतिक, जलवायु सीमाओं और रणनीतिक प्रतिबंधों के कारण देश की रक्षा आवश्यकता को पूरा करने के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए उपलब्ध था, क्योंकि क्षेत्र की आकृति और इसके स्थलाकृतिक स्थान को देखते हुए, विशेष रूप से, जब यह लगभग 12,000 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।, जो अंततः 14000 एफटीएस से ऊपर तक पहुंच जाता है।

यह समुद्र तल से ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित है और हिमालय की गहरी ऊंचाइयों में स्थित है और विशेष रूप से जब, सम्बंधित भूमि, जिसे अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है, एक मोटर योग्य मार्ग नहीं है, तो यह सशस्त्र बलों के लिए और राष्ट्र की रक्षा आवश्यकता में रणनीतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, और चूंकि अधिग्रहण किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी भी आसपास के क्षेत्र में कोई अन्य वैकल्पिक, उपयुक्त और सुरक्षित भूमि उपलब्ध नहीं है, इसलिए पुष्टि जाएगा कि यह केवल अंतिम उपाय के माध्यम से था, जो भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य के पास उपलब्ध था और इन परिस्थितियों में, मेरी राय है कि चाहे जो भी व्यक्तिगत अधिकार हों, याचिकाकर्ता नीचे दिए गए प्रावधानों के प्रभाव के आधार पर (हालांकि कानून के अनुसार स्थापित नहीं) निहित होने का दावा कर सकते हैं या कर सकते हैं। & L.R. एक्ट करें। लेकिन, फिर भी, **धारा** 41 की उप–**धारा** (1) और उप–**धारा** (2) के तहत प्रदान की गई छूटों को व्यक्तिगत अधिकारों और विशेष रूप से देश के अधिकारों और रक्षा की आवश्यकता पर प्राथमिकता दी जाएगी और जब राष्ट्र, हमारी मातृभूमि, जो एक प्रमुख चिंता का विषय है, की रक्षा की आवश्यकता को पूरा करने की बात आती है, तो इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकृति का कोई समझौता या शिथिलता नहीं बढ़ाई जा सकती है या स्वीकार्य होगी, क्योंकि हम भारतीय या हमारे इस महान देश के नागरिक, उनका शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व है, केवल तभी जब उपयुक्त

सरकार, अपने किसी भी स्तर पर, पर्याप्त और उपयुक्त की स्थापना करके हमारी संवेदनशील और महत्वपूर्ण रणनीतिक सीमाओं की रक्षा के लिए रक्षा बलों को पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करने में समर्थ और समर्थ हो।

40. संविधान की प्रस्तावना, जो हमारे देश का मूल कशेरुका और हमारे संविधान की नींव है, निम्नानुसार हैः–

"हम, भारत के लोग,भारत को एक में गठित करने का गंभीरता से संकल्प [सोवियत समाजवादी सेक्युलर लोकतांत्रिक गणराज्य] और अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिएः न्यायाधीश, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता; स्थिति और अवसर की समानता; और उन सभी के बीच बढ़ावा देना व्यक्ति की गरिमा और [राष्ट्र की एकता और अखंडता] का आश्वासन देने वाली बंधुत्व; हमारे संविधान में यहनवंबर, 1949 के छत्तीसवें दिन, इस संविधान को स्वीकार करें, स्थापित करें और हमें दें।

41. भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआती पंक्तियाँ, एक प्रस्ताव को व्यक्त करती हैं, जिसे भारत के लोगों द्वारा सर्वसम्मति से विस्तारित और हल किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से अनुसूचित जनजातियाँ भी शामिल होंगी, जिन्होंने एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष,

लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में "भारत का गठन" करने के लिए देश की एकजुटता पर अधिक जोर दिया था, जो संविधान की अन्य बुनियादी आवश्यक संरचना और स्तंभ हैं।इसके बाद ही देश का मजबूत संविधान बनता है, जब इसके तहत प्रदान किए गए अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों की ताकत के तहत, इसे प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, जो भारत के संविधान द्वारा निर्धारित किया गया था, यह तभी संभव है, जब देश के सभी नागरिक, हम अपने देश को मजबूत रूप से एकीकृत करने ठीक होना समर्थ हों, ताकि अन्य उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, जो उसठीक होना दिए गए थे, प्रस्तावना के तहत।इसका तब ही, कि हम देश के व्यापक हित को प्राप्त करने में समर्थ होंगे और एक मजबूत देश के 'संविधान' के प्रयोजनों के लिए, जो भारत के संविधान का प्रमुख उद्देश्य और उद्देश्य है, और इस मोड़ पर, मेरी राय के अनुसार, कि देश की रक्षा, एक प्रमुख चिंता का विषय भी बन जाती है और वास्तव में एक सुरक्षित और मजबूत राष्ट्र के गठन के लिए उक्त बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, इस न्यायालय की पुष्टि गई राय है कि यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होगी, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, यह व्यक्तिगत अधिकारों या किसी अन्य वैधानिक प्रकृति के अधिकारों को भी ओवरराइड करना होगा, जो कानून के तहत प्रदान किया जाता है या यहां तक कि कानून के तहत

संरक्षित है, खासकर जब और जहां स्वतंत्र और अच्छी तरह से संरक्षित देश का अस्तित्व है।

42. हमारा संविधान इरादे से अपना अधिकार प्राप्त करता है, जिसे भारत के लोगों द्वारा व्यक्त किया गया था, i.e. भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत निहित नागरिक।प्रस्तावना में उल्लिखित 'लोग' शब्द इंगित करता है कि संविधान राज्य या राज्य एजेंसियों द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि यह भारत के लोगों द्वारा मापदंडों को निर्धारित करने के लिए उनकी ठोस क्षमता में बनाया गया है, जो भविष्य के भारत को नियंत्रित करेंगे।यही कारण है कि केशवानंद भारती के मामले में, यह और विस्तार से बताया गया है कि प्रस्तावना में दी गई अभिव्यक्ति, जो हम भारत के लोगों के साथ शुरू होती है, जो अपने वादे पर प्रकाश डालती है, जो देश के नागरिकों द्वारा स्वयं किया गया है, भारतीय संविधान के तहत सभी शक्तियों को निहित करते हुए, लोगों के लिए और उनके द्वारा अपनी संप्रभुता प्राप्त करने के लिए, जो संसद में भी नहीं है।अर्थात्, यह भारत के संविधान के लिए अपने "संविधान" की अनन्य सर्वोच्चता है, जो नागरिकों द्वारा व्यक्त किए गए इरादे से है।जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, यदि प्रस्तावना पर विचार किया जाता है, यदि यह नागरिकों का इरादा था, जैसा कि ऊपर बताया गया है, तो इस न्यायालय द्वारा यह दोहराया जाता है कि देश के नागरिकों द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय का मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित और

सुरक्षित भारत का गठन करना था, और इसलिए, प्रस्तावना ठीक होना विशेष रूप से "गठित" शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होगा, देश को उसके मजबूत गठन ठीक होना एकीकृत करना, ताकि अन्य उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, जो संविधान की प्रस्तावना ठीक होना दिए गए हैं।प्रस्तावना का एकमात्र उद्देश्य सामान्य उद्देश्य और उद्देश्य को दिखाना था, जिसके लिए संविधान के लेखकों ने संविधान में ही कई प्रावधान किए थे, लेकिन यह नहीं हो सका किसी भी मूल शक्ति या निषेध के एक स्वतंत्र स्रोत के रूप में माना जाता है, जो केवल संविधान के मूल भाग में व्यक्त प्रावधानों से या व्यावहारिक दिन–प्रतिदिन के जीवन में इसकी प्रयोज्यता में इसके तर्कसंगत निहितार्थ के माध्यम से लिया जा सकता है।प्रस्तावना और इसकी विषयवस्तु राज्य और उसके विधानमंडल के लिए किसी नागरिक को कोई कार्य करने या किसी अधिकार का दावा करने से निषेधित करने का निषेध नहीं है, जो भले ही कानून के तहत किसी व्यक्ति या व्यक्ति के वर्ग के लिए स्पष्ट रूप से आरक्षित नहीं है, और यहां जब प्रस्तावना अपने व्यापक अर्थों में 'नागरिक' शब्द का उपयोग करती है, तो नागरिकों के किसी भी वर्ग को बाहर नहीं किया जाएगा, जो आरक्षित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में आते हैं।

43. प्रस्तावना का एकमात्र उपयोग और इरादा संविधान की व्याख्या करने ठीक होना किया जा सकता है, जहां संविधान और संविधान ठीक होना निहित अनुच्छेदों ठीक होना उपयोग किए गए शब्द, जहां वे अस्पष्ट हैं या दो व्याख्याओं और अर्थों ठीक होना सक्षम हैं, उस स्थिति ठीक होना, देश की आवश्यकता को व्यापक रूप से पूरा करने के लिए इसके तहत बनाए गए अस्पष्ट प्रावधानों या कानून को अधिक यथार्थवादी अर्थ दिया जाना चाहिए, ताकि इसे किसी भी बाहरी शक्तियों द्वारा प्रभावित या प्रभुत्व से मुक्त एक मजबूत लोकतांत्रिक गणराज्य ठीक होना एकीकृत किया जा सके।यह कहने के लिए अवास्तविक नहीं है कि एक संवैधानिक विधानसभा द्वारा से एक संविधान को लागू करने वाले लोग, इस शब्द की आवश्यकता शायद ही कभी होती है, बल्कि यह लोग हैं जिन्हें अपने नाम पर अधिनियमित संविधान को मंजूरी देने के लिए भी कहा जाता है, इसके अलावा, एक बार संविधान लागू होने के बाद भी, जब इसे लोगों को इसकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो यह उसके बाद न केवल उन संस्थानों को बाध्य करता है, जो इसके तहत आते हैं। संविधान.लेकिन उन तरीकों से भी, जिनके द्वारा संविधान अपने आप ठीक होना देश के आंतरिक और बाहरी मामलों को विनियमित करने के लिए प्रदान करता है।अर्थात्, संविधान की प्रस्तावना में लचीलापन हमेशा व्यापक रूप से बाहरी श्रेष्ठ शक्तियों के प्रभाव से मुक्त एक मजबूत देश को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है और

इस प्रकार संवैधानिक जनादेश की इस योग्यता से, यदि आक्षेपित अधिग्रहण अधिसूचना को ध्यान में रखा जाए, तो यह अपनी सीमा सीमाओं को पड़ोसी दुश्मन देश से बचाने के बहुत ही बुनियादी इरादे और उद्देश्य को पूरा करने के लिए आता है, जिसके साथ इस देश ने ऐतिहासिक रूप से समूह आक्रामकता और विद्रोह का सामना किया है।

44. इस प्रकार, 2013 के अधिनियम की **धारा** 41, जिसके निहितार्थों को याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा प्रचारित किया गया है, यदि **धारा** 41 को इसकी समग्रता में पढ़ा जाता है, तो यह कानून के तहत अनुसूचित जनजातियों को समझौता करके उनकी भूमि का अधिग्रहण करने से आत्यन्तिक प्रतिरक्षा प्रदान करने का इरादा नहीं रखता है; देश की आवश्यकता के लिए अब तक यह अपनी संवेदनशील और रणनीतिक सीमाओं की रक्षा से संबंधित है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के करीब है, जो भारत द्वारा चीन के साथ साझा की जा रही है, जो हमारी 'मातृभूमि भारत' के लिए लगातार सैन्य खतरा पैदा कर रही है।

45. एक और कोण हो सकता है; जिससे इस मुद्दे पर भी गौर किया जा सकता है, कि याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका में तर्क देना है, कि वे

खतौनी में दर्ज हैं, उनके साथ भूमि के निहित होने के बाद, U.P. के प्रावधानों का प्रवर्तन। Z.A. और L.R. अधिनियम, संबंधित खतौनी की प्रति, जिसे उन्होंने रिट याचिका के अभिलेखों के साथ संलग्न किया है, जिसके आधार पर वे स्वयं को सम्बंधित भूमि पर अभिलिखित कर रहे हैं, लेकिन भूमि अभिलेख नियमावली के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में भूमि पर उनके स्वामित्व की प्रकृति या कार्यकाल के आदेश को राजस्व अभिलेखों में आदेशीकृत नहीं किया गया है, कि उनके द्वारा दावा की गई भूमि पर उनके कार्यकाल–जहाज की प्रकृति क्या है, अध्याय ए VIII के पैरा ए 124 के प्रावधानों के अनुसार, जो कार्यकाल जहाज को आदेशीकृत करता है, जेडए भूमि पर, जो अधिग्रहण का विषय है, इस तथ्य के साथ कि कोई राजस्व प्रविष्टियां नहीं हैं, जो कॉलम 7 से 12 में की गई थीं।

46. यद्यपि इस स्तर पर इस न्यायालय की आवश्यकता नहीं है या वह उस विवाद में प्रवेश कर रहा है, इसका कारण यह है कि यह आत्यन्तिक रूप से एक अलग मुद्दा होगा जिस पर चर्चा की जानी चाहिए, फिर भी एक अन्य न्यायिक और कानूनी मंच पर जो प्रासंगिक राजस्व कानूनों के तहत उपलब्ध हो सकता है, जहां याचिकाकर्ताओं का उस भूमि के संबंध में व्यक्तिगत अधिकार, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि यह 1880 से कथित रूप से उनके पास निहित है।जिनका दावा है कि

वे इस पर अपनी कृषि गतिविधियाँ कर रहे हैं।जो कि उन्होंने दावा किया कि उन्हें राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।इन सभी पहलुओं को सक्षम राजस्व न्यायालयों द्वारा स्वतंत्र रूप से तय किया जाना चाहिए, कि क्या, अधिकारों को निहित करने के प्रचलित राजस्व कानून के तहत, के प्रावधानों के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप U.P.Z.A. & L.R. अधिनियम, क्या कोई विशिष्ट अधिकार याचिकाकर्ताओं के पास निहित होगा?केवल इस अप्रमाणित तथ्य के कारण कि वे कानून के अनुसार भूमि के कब्जे में थे और उन्होंने एक वर्ष में कुछ महीनों की सीमित अवधि के लिए कृषि गतिविधियों का प्रदर्शन करने का दावा किया था।

47. जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ ठीक होना पहले ही कहा जा चुका है कि याचिकाकर्ता भूमि पर अपने अनन्य अधिकारों को साबित करना ठीक होना पूरी सम्बंधित विफल रहे हैं, और विशेष रूप से केवल इस तथ्य के कारण कि याचिकाकर्ताओं और उनके पूर्ववर्तियों के पास भूमि का कब्जा था, इसलिए निहित होने का लाभ उन्हें दिया जाएगा ताकि भूमि की मिट्टी को जोतने का उनका अधिकार पैदा किया जा सके, जिसे अधिग्रहित करने की मांग की जा रही है।उपरोक्त तर्क से निपटने ठीक होना, हालांकि फिर से याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी कानूनी या दस्तावेजी सामग्री को रिकॉर्ड पर रखे बिना, लेकिन यह न्यायालय उस पहलू में उद्यम करना आवश्यक समझता है।जैसा कि पहले ही देखा गया है, जब

U.P. के प्रावधान। जमींदारी उत्सादन और भूमि सुधार अधिनियम, 24 जनवरी, 1951 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा पेश किया गया था, और उत्तराखंड राज्य के निर्माण के साथ, अधिनियम को राजपत्र अधिसूचना सं. 2241/राजस्व/2001 दिनांक 16 जुलाई, 2001.उस अधिकार को निहित करना जिसके आधार पर याचिकाकर्ता अपने अधिकार का दावा करते हैं उसी पर कब्जा करने के आधार पर भूमि, और वही अधिनियम की **धारा** 6 के निहितार्थ के परिणामस्वरूप है। **धारा** 6, यदि इसे जमींदारी उत्सादन अधिनियम की **धारा** 4 के अनुरूप पढ़ा जाता है, तो अधिनियम के प्रवर्तन के साथ कथित रूप से कब्जे में होने का दावा की गई भूमि पर सभी अधिकारों और स्वामित्व और हित का निहित होना, यह एक निरंतरता का अधिकार है जो U.P. के प्रवर्तन के साथ उत्तराखंड राज्य के साथ बनाया गया है। Z.A. & L.R. अधिनियम, जैसा कि 16 जुलाई, 2001 से प्रभावी किया गया है, अधिकार राज्य के पास निहित हैं न कि किसी व्यक्ति के पास।अधिनियम की **धारा 4** के अधीन किसी व्यक्ति का अधिकार निहित करना, वास्तव में, यह [2004 (97) आर. डी. 677, वशिष्ठ कुमार जयस्वाल बनाम राज्य **U.P.** और अन्य।प्रासंगिक पैरा 3 और 4 को नीचे निकाला गया है:–

> "3. प्रतिवादीओं नं। 5 और 6 को तीन वर्षों के लिए खनन पट्टा दिया गया था जो 28 अप्रैल, 2000 से शुरू हुआ और इसलिए यह 27–4–2003 को समाप्त हो गया।हम अपने समक्ष आग्रह किए गए विभिन्न बिंदुओं में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी राय है कि इस

याचिका को इस संक्षिप्त बिंदु पर अनुमति दी जानी चाहिए कि एक बार पट्टे की अवधि प्रतिवादीओं के पक्ष में नं। 5 और 6 की अवधि 27-4-2003 को समाप्त हो गई पट्टा के विस्तार का कोई प्रश्न ही नहीं है और इसके स्थान पर व्यापक प्रसार वाले प्रसिद्ध समाचार पत्रों में इसका विज्ञापन करने के पश्चात् एक नई सार्वजनिक नीलामी/सार्वजनिक निविदा की जानी चाहिए थी।यह प्रक्रिया आवश्यक है, अन्यथा अनुच्छेद 14 संविधान का उल्लंघन होगा।लोक प्रशासन में पारदर्शिता के लिए यह भी आवश्यक है कि जब भी कोई सार्वजनिक अनुबंध दिया जाए तो ऐसी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।यह उल्लेख किया जा सकता है कि U.P.Z.A के तहत भूमि का मालिक राज्य सरकार और भूमिधर है। और **L.R.** अधिनियम भूमि का मालिक नहीं है, लेकिन वह केवल किरायेदार है, मालिक राज्य है क्योंकि भूमि **U.P.Z.A** की **धारा 4** के तहत निहित है। और **L.R.** एक्ट करें। इसीलिये यह यह कहना सही नहीं है कि भूमि भूमिधर की है।

4. प्रतिवादीओं के लिए विद्वान वकील ने सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया बेग राज सिंह बनाम. U.P. की स्थिति.., 2003 (1) सीआरसी 362.हमारी राय में यह निर्णय पूरी तरह से अलग है अनुच्छेद 14 संविधान पर उसमें बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।"

48. कि **धारा** 4 के अधीन निहित होने का प्रभाव **धारा** 6 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, यह केवल जुताई का अधिकार है, जो निहित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व अभी भी राज्य के पास निहित है और अधिनियम के तहत भूमिधर मालिक नहीं है, बल्कि वह केवल भूमि का किरायेदार है। इसलिए, भूमि पर राज्य के अधिकार के प्रभाव को ओवरराइड करने के

लिए भूमि पर अधिकार और अधिकार की कोई स्थिरता नहीं है, जिसका अधिकार अधिनियम की **धारा** 6 के साथ पढ़ने के लिए **धारा** 4 के तहत निहित होने के माध्यम से बनाया गया है, और इसलिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत अधिकार के रूप में दावा किया गया अधिकार, केवल मिट्टी की जुताई के लिए किरायेदार के अधिकार का निहित होना है, बल्कि कानून के तहत, स्वामित्व अभी भी अधिनियम के प्रवर्तन के साथ राज्य के पास निहित है। अधिकार का विकलन, स्वयं को भूमिधार होने के लिए कार्यकाल धारकों का वर्ग होने का तर्क देकर, फिर से एक संभावना है, जो इस कारण से इस न्यायालय द्वारा स्वीकार्य नहीं है, कि याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा की गई राजस्व प्रविष्टि से निपटने के दौरान, यह पहले ही देखा जा चुका है कि याचिकाकर्ता के कार्यकाल धारक का वर्ग, उनके द्वारा भरोसा किए गए राजस्व दस्तावेजों के तहत परिभाषित या वर्गीकृत नहीं किया गया है, और इसलिए वे कार्यकाल धारक के किसी भी वर्ग के भीतर नहीं आएंगे, जो U.P. के अध्याय 8, **धारा** 129 के तहत प्रदान किया गया था। जमींदारी उत्सादन अधिनियम, जो अभी तक विशेष रूप से सक्षम राजस्व द्वारा तय किया जाना है न्यायालय, जैसा कि जमींदई उत्सादन अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित किया गया है। चूँकि इस अधिनियम का अपना विशेष संवैधानिक अस्तित्व है, क्योंकि इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया है, इसकी प्रविष्टि 11 देखें।

49. यह न्यायालय फिर भी याचिकाकर्ताओं या उनके पूर्ववर्तियों के 1880 से भूमि के कब्जे में होने के अभिकथित दावे के संबंध में एक पुष्ट राय प्राप्त करने में असमर्थ है, क्योंकि, खतौनी प्रविष्टियां, जिन पर याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वयं अपने कॉलम '3' में पुष्टि गया है और रिकॉर्ड पर रखा गया है, यह दर्शाता है कि उनका कब्जा 1374 फसली से शुरू हुआ है, जिसका अर्थ है कि राजस्व कानून के तहत **W.E.F** होगा। **1967** में।भले ही यह माना जाता है कि, कॉलम '3' में की गई प्रविष्टियों के अनुसार, यदि स्वामित्व अधिकार, यदि कोई हो, तो 1967 से शुरू हो रहे थे, और वास्तव में, यह वास्तव में U.P.Z.A के प्रावधानों के प्रवर्तन के बाद था। & L.R. अधिनियम, जिसे 24.01.1951 को राष्ट्रपति का उच्चारण प्राप्त करने के पश्चात् वर्ष 1951 में प्रवर्तित किए जाने के लिए अधिसूचित किया गया था।यदि ऐसी स्थिति है, यदि अधिनियम स्वयं दिनांक 24.01.1951 की राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा प्रवर्तित किया गया था और राजस्व अभिलेखों ठीक होना उनके कब्जे की प्रविष्टियों ने उनके कब्जे को W.E.F. 1374 fasli i.e. 1967 *A.D.,* उस स्थिति ठीक होना, सामान्य प्रचलित राजस्व कानूनों के तहत, स्पष्ट रूप से, सक्षम राजस्व अधिकारियों के आदेशों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड ठीक होना उनके नामों की रिकॉर्डिंग का स्रोत, होना चाहिए था या यह खतौनी के कॉलम 7 से 12

की प्रविष्टियों ठीक होना परिलक्षित होना चाहिए था, जो हो सकता था, केवल सक्षम राजस्व प्राधिकरण के आदेश से संभव है, ताकि एक कानूनी और वैधानिक निश्चितता प्रदान की जा सके उनके अधिकार और भूमि का हक, जिसकी अनुपस्थिति में में और विशेष रूप से फसली वर्ष की प्रविष्टियों की अनुपस्थिति में में, जिसके संबंध में खतौनी संबंधित है, जो तैयार किया गया है, U.P.Z.A के प्रावधानों के प्रवर्तन के साथ निहित करके अभिकथित दावे के प्रभाव के परिणामस्वरूप सम्बंधित भूमि पर याचिकाकर्ताओं के आत्यन्तिक अधिकार और अधिकार के निर्माण का कोई व्यापक या कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था। & L.R. एक्ट करें।

50. जब रिट याचिका पर प्रारंभ में बहस की गई थी, तो इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने प्रतिवादी को अपना जवाबी शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए अपने दिनांक 12.10.2015 के आदेश द्वारा अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।बीच की अवधि के दौरान, जब इस मामले को 11 दिसंबर, 2019 को इस न्यायालय की एक अन्य समन्वय पीठ के समक्ष फिर से लिया गया था, तो इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने जिला मजिस्ट्रेट को उस क्षेत्र का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था, जिसे I.T.B.P के लिए सीमा चौकी की स्थापना के लिए अधिग्रहित करने का प्रस्ताव था। और सीमा चौकियों की स्थापना का स्थान दिनांक

11.12.2019 के अपने आदेश द्वारा।उक्त तिथि पर निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थेः–

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क होगा कि याचिकाकर्ताओं की भूमि का अधिग्रहण मामले में कोई उचित सर्वेक्षण या जांच किए बिना किया जा रहा है, जबकि भारत संघ की आवश्यकता को अन्य भूमि के अधिग्रहण द्वारा समान रूप से पूरा किया जा सकता है।याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा है कि अन्य भूमि उपलब्ध हैं जो कर सकते हैं "चौकी" की स्थापना के प्रयोजनों के लिए आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और मौजूदा अधिग्रहण वास्तव में आवश्यक नहीं है।

4. पिथौरागढ़ के जिला मजिस्ट्रेट को क्षेत्र का निरीक्षण करने दें और एक शपथ पत्र दायर करने दें कि क्या कोई अन्य भूमि है जिसे "चौकी" की स्थापना के लिए आईटीबीपी को उपयुक्त रूप से दिया जा सकता है और यदि ऐसा नहीं है, तो वह उसमें कारण बताएगा, जिसके लिए चार सप्ताह और अधिक समय नहीं दिया जाता है।

51. यद्यपि इस न्यायालय ने पहले ही सामाजिक प्रभाव निर्धारण और सार्वजनिक प्रयोजनों के निर्धारण के लिए 2013 के अधिनियम के अध्याय–II के तहत निहित प्रावधानों के आलोक ठीक होना याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता के तर्क को पूरा करने के लिए रक्षा आवश्यकता की आवश्यकता के संबंध ठीक होना भारत सरकार के

रुख पर आंशिक रूप से विचार किया है, हालांकि यह 2013 के अधिनियम की **धारा** 9 के तहत निहित प्रावधानों के आलोक ठीक होना आक्षेपित अधिग्रहण अधिसूचना पर लागू नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी, दस्तावेज़ के आधार पर, जिसे प्रतिवादीओं द्वारा उनके जवाबी शपथ पत्र के आधार पर रिकॉर्ड पर रखा गया है, यह तर्क देना गया है कि गांव मिलम ठीक होना सीमा चौकी पहली बार 1962 के समूह आक्रमण के बाद बनाई गई थी। i.e. 1968 से "विशेष सुरक्षा बल" की एक बटालियन तैनात करके भारत–चीन युद्ध।बाद में, समूह सर्वेक्षण मूल्यांकन के बाद, जो रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की समन्वित कार्रवाई द्वारा किया गया है, एक निर्णय सक्षम वरिष्ठ समूह अधिकारियों द्वारा लिया गया था, जिसके तहत उन्होंने एक निर्णय लिया है, कि लगातार युद्ध के खतरे की धारणा के कारण और तब से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे रणनीतिक और संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र, जिन्हें चीन के साथ साझा किया जा रहा है, और जिन्हें वास्तविक नियंत्रण रेखा द्वारा सीमांकित किया गया है, यह तब भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा अपने जीओ नं। II–27012/20/2006–PF दिनांक 11 दिसम्बर, 2007, कि किसी भी अभूतपूर्व या अचानक गंभीर समूह विद्रोहों से निपटने के लिए, तैनात विशेष सुरक्षा बल देश की रणनीतिक सीमा की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवहार्य और पर्याप्त नहीं हो सकता है, और इसलिए, देश के सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा के लिए, I.T.B.P. की 14 वीं बटालियन को तैनात

करने का निर्णय लिया गया था, और इसलिए, गृह मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय ठीक होना, संयुक्त रूप से महसूस किया और स्टॉक पर लिया राष्ट्र के हित ठीक होना एक रणनीतिक निर्णय, कि चीन की सीमा से सटे सीमा चौकियों ठीक होना रक्षा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त समूह परिचालन बलों की आवश्यकता थी।वास्तव में, प्रतिरक्षा के उक्त उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से, जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ ने राजस्व बोर्ड के आयुक्त/सचिव से अपने पत्र सं. 49 दिनांक 18 सितंबर, 2013, व्यवहार्यता रिपोर्ट और किसी अन्य वैकल्पिक भूमि की उपलब्धता के बारे में।राजस्व बोर्ड ने पत्र सं. 5856 दिनांक 30 सितंबर, 2013 को एक रिपोर्ट और व्यवहार्यता रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसे पत्र सं. **24** दिनांक **5** फरवरी, **2014,** जिसमें 16 दिसंबर, 2013 को वास्तविक स्थल निरीक्षण के बाद एस. डी. एम. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं:–

I. स्थल पर कोई अन्य भूमि उपलब्ध नहीं थी, जो सशस्त्र बलों के उद्देश्य के लिए सबसे अच्छी और प्रभावी रूप से मुकदमा हो।

II. सामरिक रूप से, यह भूमि अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट होने और पहले से मौजूद बंकरों के स्थान के कारण उपयुक्त थी, जो दुश्मनों की गोलीबारी सीमा के बाहर बनाए जाने के लिए स्थित हैं।

III. इसलिए, भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, और इसके परिणामस्वरूप, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिग्रहण के

लिए एक जोर देना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 3829–30 दिनांक 28 अप्रैल, 2014, जिसे राजस्व बोर्ड द्वारा पत्र सं. 31 दिनांक 6 अप्रैल, 2015, और इसके परिणामस्वरूप, इसके अनुपालन में, धारा के तहत अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए देय राशि का अपेक्षित जमा 41 पहले ही 3 सितंबर, 2015 को एसएचक्यू बरेली द्वारा उपलब्ध कराया जा चुका है।

52. जवाबी शपथ पत्र में प्रतिवादी ने विशेष रूप से प्रस्तुत किया है कि यदि राजस्व प्राधिकरणों की रिपोर्टों को ध्यान में रखा जाता है, तो वास्तव में, याचिकाकर्ताओं द्वारा ली गई भूमि को कृषि भूमि होने का दावा करने का पूरा मुद्दा तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि 1990 के बाद से राजस्व प्राधिकरणों की रिपोर्ट के अनुसार, अर्धसैनिक बलों अपने आप में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर कभी भी कोई कृषि गतिविधि नहीं की गई थी, बल्कि भूमि बंजर पड़ी थी और रिपोर्ट के अनुसार, यह रणनीतिक और सामरिक रूप से अधिक महत्व और आवश्यक था सीमा चौकी की स्थापना और रक्षा कर्मियों का विश्वास बढ़ाने के लिए सशस्त्र बलों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अधिक उपयुक्त, गोला–बारूद की स्थिति के लिए सैन्य सहायता, और किसी भी तत्काल सैन्य आपातकाल से निपटने के लिए बलों द्वारा स्टैंड की दूसरी पंक्ति प्रदान करने के लिए, जो संयोग हो सकता है, और स्पष्ट रूप से युद्ध की तैयारी का एक हिस्सा होगा, जिसका सामना वे आम तौर पर खतरे की

धारणा के कारण कर रहे हैं।भारत सरकार के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का सामरिक स्थल पैच, वास्तव में, ऐसे भौगोलिक स्थान पर स्थित है, कि इसमें भारतीय क्षेत्र के लिए दो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण अर्थात् "लसर गड" और "अंतर्राष्ट्रीय दर्रा" सम्बंधित हैं, जो दुश्मनों द्वारा आसान पहुंच के मार्ग हैं और उक्त सुलभ क्षेत्र पर लगातार सतर्कता और नियंत्रण हमारे देश के सशस्त्र बलों द्वारा सीमा चौकी की तैनाती के बाद विचाराधीन भूमि से आसानी से बनाए रखा जा सकता है, जो केवल लगभग 20 से 25 किमी से जुड़ा हुआ है।इसलिए वास्तविक नियंत्रण रेखा का अधिक महत्व है और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है, जिसे चीन के साथ साझा किया जा रहा है।

53. इसके अलावा, भारत सरकार के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया था कि अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि, इस सम्बंधित से स्थित है कि वास्तव में विचाराधीन भूमि के ठीक पीछे, पहाड़ों की एक श्रृंखला है, जो उच्च हिमालय का हिस्सा है, जो एक ढाल के रूप में कार्य करेगा और समूह की चौकी और उसके बंकरों को दुश्मन देश की फायरिंग रेंज के भीतर लाने से दूर कर देगा, क्योंकि कोई अन्य आसपास की भूमि या खुला क्षेत्र। यदि यह "लेसर गड" और "इंटरनेशनल पास" की फायरिंग रेंज के भीतर आता है, तो यह रक्षा उद्देश्यों के लिए समूह की

आवश्यकता के लिए उपयुक्त नहीं होगा, और इसलिए, बाद में, यह देखा गया और जैसा कि पहले ही निकाला जा चुका है, कि कोई अन्य वैकल्पिक रणनीतिक स्थान नहीं है, जिसे उच्च हिमालय में उपलब्ध कराया जा सकता है, जो रक्षा कर्मियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रणनीतिक रूप से व्यवहार्य हो सकता है।

54. रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित किए गए उपरोक्त अंतर्वर्ती आदेश के अनुपालन में, प्रतिवादी ने 22 सितंबर, 2015 को अपना जवाबी शपथ पत्र दायर किया था।इस प्रकार I.T.B.P. के कमांडेंट द्वारा दायर जवाबी शपथ पत्र में, उन्होंने तर्क दिया है; कि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि रणनीतिक रूप से देश की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय महत्व की थी, I.T.B.P. की 14 वीं बटालियन की तैनाती के उद्देश्यों के लिए, एक कोय ताकत के साथ, अपने रणनीतिक स्थान के कारण, क्योंकि यह वास्तविक नियंत्रण रेखा, i.e. के साथ आसन्न और आसानी से सुलभ था। पड़ोसी देश चीन के साथ सीमा रेखा, जो लगभग केवल 20 से 25 किलोमीटर है।अधिग्रहण की जाने वाली प्रस्तावित भूमि से।प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, आईटीबीपी कर्मियों के निर्देशों के आधार पर, जो अदालत की कार्यवाही में मौजूदा थे, ने मामले की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील की उपस्थिति में स्थान पर सटीक स्थिति के

बारे में बताया था, जो इस समय मौके पर मौजूदा है, जिसे इस अदालत को निम्नलिखित मानचित्र के समर्थन से स्थिति का स्थलाकृतिक रूप से विश्लेषण करना था, जैसा कि प्रतिवादी द्वारा अदालत को समझाया गया था, जो निम्नानुसार हैः–

55. उन्होंने तर्क

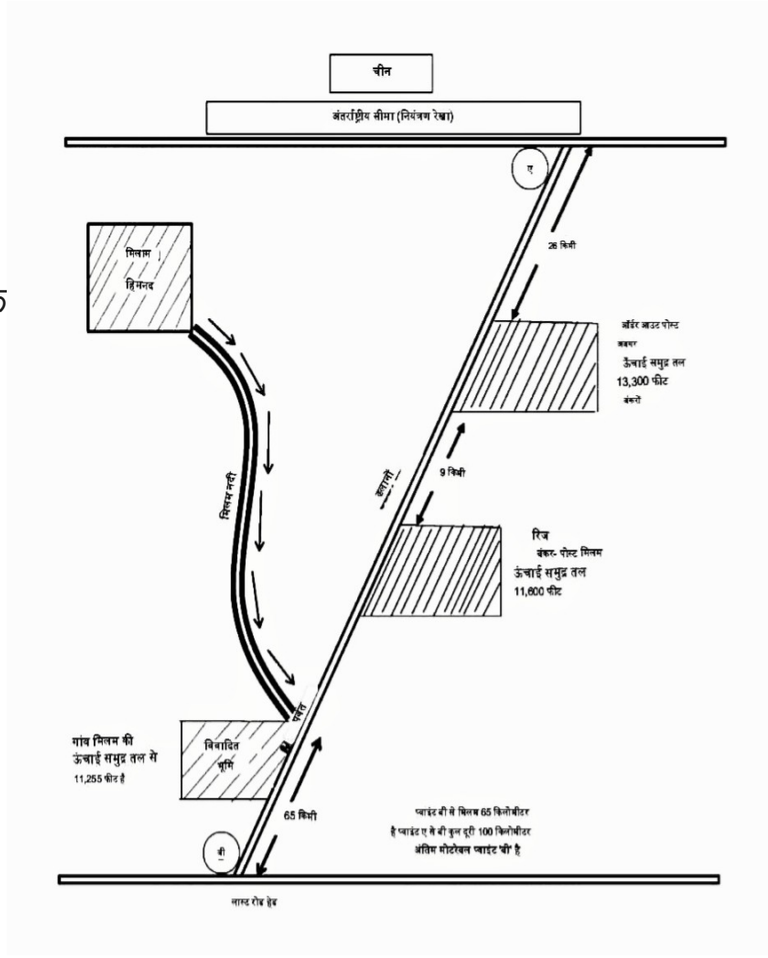

देना है कि निरंतर खतरे की धारणा के कारण जो आम तौर पर सभी को पता है और हमारे राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के मुद्दे की संवेदनशीलता, जो अधिक महत्वपूर्ण थी, इस मामले की रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के परामर्श से भारत सरकार को गृह मंत्रालय (एमओएचए) के स्तर पर लगातार समीक्षा की गई थी, और इसके बाद ही, सामरिक अंतराल रिपोर्ट के कारण, जो रक्षा मंत्रालय के सक्षम तकनीकी प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई थी, यह महसूस किया गया था कि

सम्बंधित भूमि, देश के अर्धसैनिक बलों की सीमा रेखा चौकी के रक्षा ढांचे को बढ़ाने के लिए प्रमुख रक्षा आवश्यकता थी, और तदनुसार उक्त प्रभाव की रिपोर्ट पत्राचार जनरल ज्ञापन नं। III/40012/1/BOPs अगस्त 1/2001/VOL-III-Ops दिनांक 17.12.2012, जो निम्नानुसार हैः-

"2. सभी सीमाओं से प्राप्त सिफारिशों और समूह की पूर्वी कमान और तीसरी इन्फैंट्री डिवीजन द्वारा दिए गए सुझावों का डीटीई जनरल में विस्तार से मूल्यांकन किया गया 32 बटालियनों की बटालियन-वार तैनाती जो सीमा सुरक्षा कर्तव्यों पर होंगी (वर्ष 2015-16 तक) को अंतिम रूप दिया गया है और अनुलग्नक-I, II और III के रूप में संलग्न किया गया है। संबंधित एफटीआर से अनुरोध है कि वे संबंधित सेक्टर और बीएन में तैनाती का प्रसार करें और निर्धारित समय के भीतर इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

3. कार्यान्वयन से पहले, अंतिम तैनाती की एक प्रति स्थानीय समूह के गठन को दी जा सकती है उनकी जानकारी।सीमा सुरक्षा कर्तव्यों के लिए अतिरिक्त बटालियनों को शामिल करने की योजना और दिनांक 13/06/2012 के जनरल ज्ञापन संख्या-3034 के माध्यम से पहले से ही प्रसारित निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।जब तक नई बीएन बीओपी को

संभालती हैं, तब तक बाहर निकलने वाली बीएन सौंपे गए संचालन कार्य को जारी रखेगी और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करेगी।

4. जिन स्थानों पर नए बी. ओ. पी. खोले जाने हैं और निर्धारित एस. एच. क्यू./बी. एन. को अभी तक खड़ा नहीं किया गया है, संबंधित एफ. टी. आर. आई. एस. जी. एफ. टी. आर. के भीतर उपयुक्त बी. एन. को रेकी करने, बी. ओ. पी. के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रस्तावों को स्थानांतरित करने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने आदि की जिम्मेदारी सौंप सकता है ताकि नई बी. एन. को तुरंत शामिल किया जा सके और इसके संचालन की पेशकश की जा सके।

5. एफ. टी. आर. को सौंपे गए परिचालन कार्यों को निष्पादित करने के लिए समय पर समर्थन के लिए प्रावधान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा शाखाएं आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई कर सकती हैं।"

56. शपथ पत्र में प्रतिवादी ने आगे प्रस्तुत किया था कि यह अभ्यास और प्रतिरक्षा आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयुक्तता और उद्देश्य का आकलन करने के लिए, जैसा कि 17.12.2012 (जैसा कि ऊपर निकाला गया है) की रिपोर्ट से परिलक्षित होता है, जैसा कि शपथ पत्र के पैरा (II) में निर्दिष्ट किया गया है, जिस पर प्रतिवादी सं. 3, 4 और 5,

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है, कि 2,4980 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव, i.e। रक्षा आवश्यकता को पूरा करने के लिए 6.007 एकड़ भूमि के बराबर एक प्रस्ताव था, जिसे शुरू में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ द्वारा उनके कार्यालय पत्र नं। **4077–78** दिनांकित **11.05.2009** और तदनुसार, भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के बदले, प्रत्यर्थियों/भारत सरकार ने अपने रक्षा मंत्रालय द्वारा से पहले ही निर्धारित राशि जमा कर दी थी, जो जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून के समक्ष उनके पत्र सं. 1054 दिनांक 11.12.2013, जो वास्तव में 2013 के अधिनियम की **धारा** 41 की उप**धारा** (6) के उपबंधों के अनुपालन के लिए उपबंधों के आलोक में होगा।

57. विलम्ब के उस पहलू को, जो किया जा रहा था और समयावधि को, जिसे संभवतः भूमि अधिग्रहण ठीक होना नियोजित किया जा रहा था, राज्य द्वारा निजी भूमि स्वामियों की भूमि (जैसा कि उनके द्वारा दावा किया गया था) को निजी वार्ताओं द्वारा से अधिग्रहित करने के प्रयास और प्रयास भी किए गए थे, लेकिन वह अमल निहित नहीं आ सका और इसलिए, तदनुसार, उप भूमि अधिग्रहण अधिकारी के कार्यालय से 17.04.2013 को किए गए पत्राचार संख्या. 21 के अनुसार, भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव उप भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जिला पिथौरागढ़ द्वारा भेजा गया था, और यदि उक्त पत्र (सीए III पृष्ठ 69) निहित दिए

गए संदर्भ को ध्यान निहित रखा जाता है, तो यह पत्र सं. 2760–61, जैसा कि द्वारा प्रस्तुत किया गया था I.T.B.P. 15.04.2013 को, सशस्त्र बलों की सीमा चौकी की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की आकस्मिक आवश्यकता के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हुए, जो महत्वपूर्ण था और जो देश की एक आकस्मिक रक्षा आवश्यकता थी।

58. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सं। 3, 4 और 5, वास्तव में, भी खींचा है इस न्यायालय का ध्यान, I.T.B.P. के कमांडेंट द्वारा किए गए पत्राचार पर। 11.05.2009 को जिला मजिस्ट्रेट को (सीए 1 पृष्ठ 66), जो निर्धारित आकस्मिक आवश्यकता पर आधारित था, जिसे गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार और उसके रक्षा मंत्रालय को भी व्यक्त किया गया था। गृह मंत्रालय यूओ संख्या II–27012/20/2006–पीएफ दिनांक 11 दिसंबर, 2007, जिसमें कमांडेंट ने निम्नलिखित तरीके से गांव मिलम में भूमि की आवश्यकता की आपात आवश्यकता व्यक्त की थी:–"चूँकि यह स्थान अन्तराष्टीय सीमा के निकट है जहॉ पर बल की समुचित तैनाती राष्टं हित में हर समय अपेक्षित है, जिस कारण इस भूमि का शीध्रातिशीध्र हस्तान्तरण कर वहॉ पर रहने वाले जवानों के लिए बैरेक आदि बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु शीध्र निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना है। प्रस्तावित भूमि को विभाग द्वारा संबन्धितभू–स्वामियों से आपसी समझौते से क्रय किया जाना सम्भव नहीं है। "

59. इसलिए, याचिकाकर्ताओं का दलील है कि अधिग्रहण **धारा** 15 के गैर–अनुपालन के दोषों से ग्रस्त है, जिसे अधिनियम की **धारा** 40 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, हालांकि पहले ही निपटा दिया गया था और ऊपर सिद्ध गया था, यह प्रतिवादीओं द्वारा अपने जवाबी शपथ पत्र ठीक होना, उनके अभिवचनों ठीक होना और विभिन्न संचारों द्वारा लिया गया रुख से भी स्पष्ट है, जो रिकॉर्ड पर रखा गया है, कि जब देश की आपातकालीन रक्षा आवश्यकता को पूरा करने के लिए भूमि पर कब्जा करने के लिए निजी बातचीत के सभी प्रयास विफल हो गए, तो 2013 के अधिनियम की **धारा** 11 (1) के तहत आक्षेपित अधिसूचना जारी करके अधिग्रहण अपरिहार्य हो गया और तदनुसार, जिला कार्यालय मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ ने अपने पत्र सं. **49/Hkw0v0/vkbZVhchih & feye/2012-13** दिनांक **18.09.2013** ने भूमि अधिग्रहण के लिए अधिग्रहण । को राजस्व बोर्ड के आयुक्त/सचिव को उत्तराखंड सरकार को भेज दिया था। I.T.B.P बॉर्डर आउट पोस्ट चीन की सीमा से सटे।

60. 18.09.2013 को जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय द्वारा राजस्व आयुक्त/सचिव बोर्ड के कार्यालय को किए गए उपरोक्त संचार के जवाब ठीक होना, आयुक्त ने **धारा** 41 की उप–**धारा** (2) की विधायी भावना के अनुसार आकस्मिक सैन्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जिसे **धारा** 40 के साथ पढ़ा जाना था, एक कार्यालय आदेश सं। 5856 दिनांक

30.09.2013, जिसठीक होना उत्तराखंड राज्य के राजस्व बोर्ड के सचिव ने अधिग्रहण के प्रयोजनों के लिए भूमि की व्यवहार्यता के बारे ठीक होना भारत सरकार, उसके रक्षा मंत्रालय और उसके गृह मंत्रालय से टिप्पणियां मांगी थीं और क्या कोई अन्य भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है या अर्धसैनिक बलों के लिए अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है।30.09.2013 के उक्त संचार के बाद जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय द्वारा जारी आदेश जारी किया गया, जिसने आरोप लगाया है और तर्क देना है कि उसने अभ्यास किया था और पत्र नं। 24 दिनांक 25 फरवरी, 2014, जिसमें, उपरोक्त संचार में, जिला मजिस्ट्रेट ने कहा था कि विभिन्न क्वार्टरों और अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद; अधिग्रहित [की] जाने वाली प्रस्तावित भूमि, उन्होंने इसद्वारा से एक जांच की थी उपमंडलीय मजिस्ट्रेट, और उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसका प्रासंगिक हिस्सा यहां निकाला गया है:–

"प्रकरण के सम्बन्ध में सेनानी, 14 वीं वाहिनी, भा0ति0सी0पु0 बलके पत्र संख्या–अभि0/2011–567–69 दिनांक 27.012014 (छायाप्रति संलग्नक–2) के द्वारा अवगत कराया गया है कि सीमा चौकी की स्थापना हेतु 3.410 हे0 का मानक निर्धारित है। वर्तमान समय में भा0ति0सी0पु0 के कब्जे में केवल एस0पी0एफ0 के नाम दर्ज 0.903 हे0 भूमि है। भूमि की कमी के कारण सीमा चौकी में कार्यरत जवानों के निवास आदि के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा है जिसका जवानों के मनोबल पर विपरीत असर पड रहा है। तथा पूर्व में चौकी की स्थापना हेतु प्रषित ग्राम मिलम की 2.4980 है0 भूमि कोभा0ति0सी0पु0 के नाम अधिग्रहण करने का अनुरोध किया गया है।

इस प्रकार सीमान्त क्षेत्र में भा0ति0सी0पु0 की मिम चौकी की स्थापना हेतु सार्वजनिक भूमि, राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि, सिविल सोयम एवं विभाग की भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण राष्टीय सुरक्षा के हित को दृष्टिगत रखते हुए भूमिधरों की नाप भूमि को ही अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि राष्टीय सुरक्षा के हत को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में अधिग्रहण हेतु प्रेषित ग्राम मिलम की 2.4980 है0 भूमिधरों की नाप भूमि को भू–अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भा0ति0सी0पु0 के नाम अधिग्रहण के प्रस्ताव में परिषद स्तर पर विचार करने उपरान्त धारा–4 (1/17) के अन्तर्गत शासकीय विज्ञप्ति निर्गत करने हेतु शासन के प्रशासकीय विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें। "

61. उप भूमि अधिग्रहण अधिकारी के कार्यालय के पत्राचार के अनुसार भी ऐसा नहीं है, जो पत्र सं. 29 दिनांक 12.03.2014 को एक शुद्धिपत्र द्वारा से यह सूचित किया गया था कि अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के लिए नया अनुमान बढ़े हुए मुआवजे का आकलन रु। 45,29,224/– और परिणामस्वरूप, उक्त पत्राचार के अनुपालन में, और भूमि की नवीनतम दर के आधार पर जिसका मूल्यांकन सक्षम राजस्व अधिकारियों द्वारा किया गया था, रु। 93,32,021/– को एसएचक्यू, बरेली द्वारा पत्र नं। 8732 दिनांक 03.09.2015, अधिनियम 2013 की **धारा** 41 की उप**धारा** (6) के आशय के अनुसार, अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के मुआवजे के लिए भूमि के बढ़े हुए अनुमानित मूल्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

62. जब इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 11.12.2019 को पारित अंतर्वर्ती आदेश, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांगी गई थी, का

अनुपालन नहीं किया गया था, तो इस न्यायालय ने दिनांक 18.08.2021 के अपने आदेश के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को I.T.B.P. की सीमा चौकी (BOP) की स्थापना की वास्तविक आवश्यकता के बारे में एक जांच करने और रिपोर्ट के साथ एक पूरक जवाबी शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। 1279/XVIII (II)/03 (35)/2021 दिनांक 25.09.2021, जिसमें, I.T.B.P को वैकल्पिक भूमि की पेशकश के लिए राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार प्रस्ताव दिया गया है। सहायक सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तावित सीमा चौकी के रणनीतिक स्थान के आधार पर आपत्ति जताई गई थी, जिसका निर्माण I.T.B.P. के लिए किया जाना था, और इसलिए, उप महाधिवक्ता को प्रस्तावित सरकारी आदेश दिनांक 25.09.2021 पर अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए समय दिया गया था।

63. भारत सरकार के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा पारित पिछले आदेश के अनुमुकदमा ठीक होना 04.10.2021 को एक पूरक जवाबी शपथ पत्र दायर किया है, और उसके अनुमुकदमा ठीक होना, इस प्रकार प्रतिवादी सं। 04.10.2021 को 3,4 और 5, उन्होंने कई दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जिसठीक होना तर्क दिया गया था कि प्रस्ताव, जिसे राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया गया था, सशस्त्र बलों की रक्षा आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, जो 2009 से निर्धारित किया गया था, (जैसा कि ऊपर निकाले गए मानचित्र द्वारा समझाया गया है), और

इसके समर्थन ठीक होना, उन्होंने I.T.B.P. के मिलम पोस्ट के Google मानचित्र को भी रिकॉर्ड पर रखा है। उनके रुख को साबित करना के लिए, और यह कि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि रणनीतिक रूप से रक्षा कर्मियों के लिए और देश की रक्षा के लिए, सील स्तर से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर उच्च ऊंचाई पर युद्ध के लिए, हिमालय के उच्च क्षेत्र ठीक होना, भारत और चीन के बीच साझा की गई वास्तविक नियंत्रण रेखा के लिए अधिक महत्वपूर्ण है।

64. तथ्यात्मक पहलू की उपरोक्त जांच के आधार पर, जैसा कि पार्टियों के वकील द्वारा बहस दिया गया है, समग्र विवाद पर, जिसका बहस याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया है, (i) निहित होने का प्रभाव; (ii) 2013 के अधिनियम की **धारा** 15,21,40 और 41 का प्रभाव, और (iii) अधिनियम की **धारा** 41 के दृष्टिकोण से सीमित था। याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यापक रूप से और बेतहाशा किए गए ये पहलू और बहस केवल मौखिक प्रकृति के थे, बिना किसी विश्वसनीय सामग्री या रिकॉर्ड पर रखे गए किसी भी दस्तावेज के बिना, जो याचिकाकर्ताओं के पक्ष में थे। जिन दलीलों के आधार पर याचिकाकर्ता यह साबित करना के लिए अपने तर्क का आधार बना सकते थे कि किस तरीके से उनके व्यक्तिगत अधिकार का दावा किया गया था, वे 2013 के अधिनियम की **धारा** 11 (1) के तहत जारी

अधिसूचना को चुनौती दे सकते हैं, और वह भी जब इसका उद्देश्य विशेष रूप से देश की रक्षा आवश्यकता को पूरा करना है, जो सर्वोपरि है और सभी व्यक्तिगत या सार्वजनिक उद्देश्यों से ऊपर होगा, किसी व्यक्ति या यहां तक कि एक समुदाय या समुदाय के एक वर्ग की, देश की रक्षा आवश्यकता पर पसंद की प्राथमिकता नहीं हो सकती है।

65. एक पुनरावृत्ति के रूप में, हालांकि निहित होने के प्रभाव के संबंध में इस निर्णय के उपरोक्त पैरा में इस न्यायालय द्वारा उत्तर पहले ही दिया जा चुका है, क्योंकि इस न्यायालय की राय के अनुसार, विशेष रूप से जमींदारी उत्सादन अधिनियम की **धारा** 4 और 6 के तहत निहित होना, किसी भूमि पर अधिकार या स्वामित्व का निहित होना नहीं होगा, और सक्षम न्यायालयों द्वारा पारित कोई न्यायिक आदेश होने की अनुपस्थिति में में, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में, जो राजस्व कानून के तहत बनाया गया था क्योंकि निहित होना किसी व्यक्तिगत निष्कर्ष के रूप में नहीं हो सकता है।धारा 4 और 6 के तहत निहित होना, U.P. के प्रवर्तन के साथ स्वामित्व का निहित होना है। Z.A. & L.R. अधिनियम, राज्य के पास है, जो भूमि पर अपने "प्रमुख क्षेत्र" का प्रयोग करता है और यह केवल मिट्टी की जुताई का अधिकार है, जिसे भूमि के कानूनी रूप से स्थापित अधिभोगियों को दिया जा सकता है, जिसे भी याचिकाकर्ताओं द्वारा राजस्व प्रविष्टियों के आधार पर भी प्रमाणित नहीं किया गया है,

क्योंकि याचिकाकर्ताओं के कब्जे को W.E.F दिखाया गया है। 1374 फसली, i.e. 1976 A.D. और यह U.P. के प्रवर्तन से पहले नहीं है। Z.A. & L.R. अधिनियम, जो 1951 में था, और इसके अलावा, और अधिक क्योंकि यह जमींदारी उत्सादन अधिनियम की **धारा** 129 के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में याचिकाकर्ताओं के कार्यकाल जहाज के स्वामित्व की प्रकृति के बारे में वर्गीकृत नहीं करता है, जिसे भूमि रिकॉर्ड मैनुअल के अध्याय–ए, VIII के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना है, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं को कभी भी सम्बंधित भूमि पर कोई अनन्य भूमिधारी अधिकार था, या कब्जाधारियों थे, क्योंकि यह प्रतिवादीओं का विशिष्ट अप्रकाशित मामला था कि 1990 से, भूमि बंजर पड़ी थी, जो एक तथ्य है जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा अभिवचन या किसी प्रमाणित दस्तावेज को रिकॉर्ड पर रखने के माध्यम से विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया गया था।

66. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क, हालांकि इसका पहले ही ऊपर सिद्ध जा चुका है, जो **धारा** 15 और 21 के गैर–अनुपालन के आरोप और **धारा** 40 और 41 के तहत अधिसूचना किए गए संरक्षण के प्रभाव से संबंधित है, मेरा विचार है कि अधिनियम के उद्देश्य और छूट के आलोक में, जिसे अधिनियम की **धारा** 2 (1) (ए) के तहत कायम रखने योग्य रूप से विचार आक्षेपित था, **धारा** 9 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, विशेष रूप से जब **धारा** 9 स्वयं **धारा** 40 की प्रयोज्यता को बाहर करती

है; जब अधिग्रहण 2013 के अधिनियम की **धारा** 2 (1) (ए) के तहत प्रदान किए गए रक्षा उद्देश्यों के लिए किए जाने पर विचार किया जाता है, और विशेष रूप से जब यह विशेष रूप से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए है, तो **धारा** 9 का आवेदन, जो स्वयं **धारा** 9 के साथ पढ़ा जाना चाहिए।क्योंकि, इस न्यायालय का विचार है कि एक बार छूट दी गई है 2013 के अधिनियम की **धारा** 9 के तहत आकर्षित किया गया है, और **धारा** 40 को लागू करने से बाहर रखा गया है और चूंकि **धारा** 40 स्वयं **धारा** 21 के उद्देश्य और इरादे की रक्षा करती है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में और यह आरोप लगाते हुए कि अधिसूचना उन प्रावधानों का उल्लंघन करती है, कायम रखने योग्य नहीं होगी, और इस न्यायालय द्वारा स्वीकार्य नहीं है, इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया जाता है।

67. याचिकाकर्ताओं ने इस दृष्टिकोण से अपने अधिकारों का दावा किया है कि वे "अनुसूचित जनजाति" हैं और "अनुसूचित क्षेत्र" के निवासी हैं, जिसे भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची में परिभाषित किया गया है, जैसा कि अनुच्छेद 244 के तहत बनाया गया है।यह केवल एक तर्क है। लेकिन, अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो याचिकाकर्ताओं द्वारा तर्क दिया गया हो या उन पर भरोसा किया गया हो ताकि वे यह दिखाने ठीक होना सक्षम हों कि भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के भाग–सी के अनुसार, कभी भी गाँव मिलम को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया

गया था, इसलिए उपरोक्त सामग्री को अभिलेख पर रखे जाने की अनुपस्थिति में ठीक होना या यहां तक कि U.P. 1967 का अनुसूचित जनजाति आदेश, जिसे याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा भारी रूप से संदर्भित किया गया था, जिसका संदर्भ याचिकाकर्ताओं द्वारा दिया गया है, संरक्षण, यदि कोई हो, तो केवल बढ़ाया जा सकता था या न्यायिक रूप से विचार किया जा सकता था, यदि याचिकाकर्ता यह दिखाने के लिए साक्ष्य दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखकर सफल होने में समर्थ होते कि भूमि एक अनुसूचित क्षेत्र है, जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जैसा कि भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के भाग–सी के साथ पढ़ने के लिए **धारा** 3 (जेडडी) के तहत परिभाषित किया गया है।इसकी अनुपस्थिति में में याचिकाकर्ताओं को कोई लाभ नहीं दिया जा सका।**धारा** 3 (जेडडी) को परिभाषित करना 2013 के अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र को इसके तहत निकाला गया है:–

> "(जेड डी)" "अनुसूचित क्षेत्र" "से पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के प्रावधानों की **धारा** 2 में परिभाषित अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत हैं;"

68. लेकिन, यहां तत्काल मामले में, इस न्यायालय की राय है कि और जैसा कि पहले ही निर्णय के मुख्य भाग में निपटा गया है, कि एक बार संविधान का मूल कशेरुका था i.e. इसकी प्रस्तावना का उद्देश्य "एक राष्ट्र का निर्माण" करना है, मेरा विचार है कि एक राष्ट्र का निर्माण केवल

पड़ोसी दुश्मन देशों के साथ अपनी सीमावर्ती सीमाओं की प्रभावी सुरक्षा के माध्यम से हो सकता है, जो रक्षा की आवश्यकता को किसी भी अन्य निजी और सार्वजनिक अधिकारों की तुलना में और भी अधिक प्रतिष्ठित और श्रेष्ठ बनाता है, जहां किसी भी समूह आक्रमण की निरंतर खतरे की धारणा मौजूद है।इस न्यायालय का विचार है कि इस तथ्य के बावजूद कि अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को कुछ व्यक्तिगत अधिकार हो सकते हैं, जो संविधान द्वारा या इसके तहत बनाए गए कानूनों द्वारा संरक्षित किए गए हैं या जिन्हें संरक्षित किया गया है, लेकिन किसी व्यक्ति या समाज के एक वर्ग के उक्त वैधानिक संरक्षण को एक आत्यन्तिक अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है, यहां तक कि संविधान के मूल इरादे को ओवरराइड करने के लिए एक एकीकृत और मजबूत देश का गठन करने के लिए, जैसा कि सभी भारतीयों द्वारा हल किया गया था और किया गया है, देश को प्रदान करने के लिए जो अपने दुश्मनों से अच्छी तरह से संरक्षित है। इसलिए, अनुच्छेद 5 के तहत प्रदान की गई नागरिकों की परिभाषा, किसी विशेष नागरिक के व्यक्तिगत अधिकार (जो अभी तक स्थापित नहीं हुआ है) के संरक्षण को बाहर नहीं करेगी। समाज का वर्ग जब भी देश की रक्षा करने और रक्षा कर्मियों की आवश्यकता को पूरा करने का आह्वान करता है, क्योंकि व्यक्तिगत हित और कोई भी परिस्थिति राष्ट्र की रक्षा के सार्वजनिक हित या हित पर हावी नहीं होगी, जब यह देश

की रक्षा से सीधे संबंधित होगा, तो यह सभी माध्यमिक और कार्मिक संरक्षित अधिकारों को कमजोर और दूर रखेगा।

69. जनहित या सार्वजनिक उद्देश्य की धारणा, जो अक्सर विभिन्न कार्यवाहियों में दलील का विषय रही है, जो देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आयोजित की गई थी, जहां अधिग्रहण कार्यवाहियों को चुनौती दी जाती है, इसने अपनी चुनौती के लिए विभिन्न पहलू प्रदान किए थे।सार्वजनिक प्रयोजन के उन पहलुओं पर मुख्य रूप से विभिन्न न्यायालयों द्वारा निम्नलिखित प्राधिकरणों में इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया है कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और तथ्यों के दिए गए सेट के तहत सार्वजनिक उद्देश्य से कैसे और किस तरीके से निपटा जाना है।हालांकि, किसी भी प्राधिकरण में, भूमि अधिग्रहण के संबंध में कर्मियों या सार्वजनिक उद्देश्यों से निपटने के दौरान, राष्ट्र की संप्रभुता या रक्षा आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया गया है।

70. एक निर्णय में, जैसा कि AIR 1996 **SC** 1051 में बताया गया है, चमेली सिंह और अन्य बनाम **U.P.** राज्य। और अन्य, यह एक मामला था, जो अधिग्रहण की कार्यवाही से उत्पन्न हो रहा था, जिसे U.P. राज्य द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण ठीक होना में बनाया गया था। दलितों के

लिए एक सार्वजनिक आवास योजना के प्रवर्तन के लिए उक्त मामले में निहित विचार ठीक होना में सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए।द. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समाज की अनुसूची जातियों की आवास आवश्यकता को पूरा करने के लिए सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता की उपरोक्त पृष्ठभूमि में, इसे सार्वजनिक आवश्यकता के दायरे में लाया है और समाज के उत्पीड़ित वर्ग के लिए आवास योजना निर्धारित करने के लिए अधिग्रहण के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए 'प्रतिष्ठित डोमेन' की शक्तियों के प्रयोग की अवधारणा को बरकरार रखा है, लेकिन हालांकि, शक्तियों के प्रयोग की सीमा, जैसा कि उक्त निर्णय के पैरा 16 और 17 में देखा गया है, जो कि इसके तहत निकाला गया है, केवल न्यायसंगत हो सकता है और न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होगा, जब तक कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, मालिकों के व्यक्तिगत अधिकारों को भूमि खोने वालों को पर्याप्त मुआवजे का अधिनिर्णय प्रदान करके संरक्षित किया जाता है।पैरा 16 और 17 को नीचे उद्धृत किया गया हैः–

> "16. यह सच है कि अधिसूचना को अंतिम रूप देने और प्रकाशित करने में अधिकारियों की ओर से पूर्व–अधिसूचना और अधिसूचना के बाद देरी हुई थी।लेकिन वे तथ्य सरकार के समक्ष मौजूदा थे जब उसने तात्कालिकता खंड को उपयोग करना किया और **धारा** 5–ए के तहत जांच को समाप्त कर दिया। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, विलम्ब अपने आप में

तात्कालिकता को तेज करता हैःजितनी अधिक देरी होगी, उतनी ही अधिक तात्कालिकता होगी।जब तक दलितों, जनजातियों और गरीबों की अस्वास्थ्यकर स्थितियों और दयनीय आवास आवश्यकताओं को हल या पूरा नहीं किया जाता है, तब तक तात्कालिकता बनी रहती है।जब सरकार भौतिक, संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के आधार पर, तात्कालिकता की अपनी राय बनाती है, तो न्यायालय, एक अपीलीय मंच नहीं होने के नाते, मामले को बाधित नहीं करेगा। निष्कर्ष निकालना जब तक कि अदालत निर्णायक रूप से शक्ति के प्रयोग को दुर्भावपूर्ण न पाए। दलितों, जनजातियों और गरीबों को मकान उपलब्ध कराना अपने आप में एक राष्ट्रीय समस्या और एक संवैधानिक दायित्व है।जब तक समस्या का समाधान नहीं होता है और आवश्यकता पूरी नहीं होती है, तब तक तात्कालिकता बनी रहती है।राज्य बेहतर स्वच्छता स्थितियों के साथ सभ्य आवास प्रदान करके दयनीय आवास स्थिति को दूर करने के लिए धन खर्च कर रहा है।अधिसूचना से पहले और बाद में देरी के लिए अधिकारियों की ओर से सुस्ती तात्कालिकता खंड को लागू करने की शक्ति के प्रयोग को उस कारण से अमान्य नहीं कर देगी।

17. सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अपनी अनिवार्य प्रकृति के प्रत्येक अधिग्रहण में, मालिक को अपनी आजीविका के साधन, भूमि से वंचित किया जा सकता है।राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए प्रतिष्ठित क्षेत्र की अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और भूमि का अधिग्रहण करता है।जब तक शक्ति का प्रयोग सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है, तब तक मालिक के व्यक्ति के अधिकार को व्यापक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए स्थान मिलना चाहिए।अधिग्रहण की

अनिवार्य प्रकृति के लिए, **धारा** 23 की उप–**धारा** (2) उस मालिक को ऋण राशि का भुगतान प्रदान करती है जो स्वेच्छा से भूमि के कब्जे के साथ भाग लेने से इनकार करता है।प्रक्रिया के अनुसार अधिग्रहण शक्ति का एक वैध प्रयोग है।इसलिए यह आजीविका के अधिकार से वंचित करने के बराबर नहीं होगा।**धारा** 23 (1) में अधिग्रहित भूमि के लिए **धारा** 4 (1) अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रचलित कीमतों पर मुआवजे का प्रावधान किया गया है, जिसे कार्यवाही के बाद के चरणों में मापा जाएगा।वितरण या विस्थापन के लिए, **धारा** 23 (1–ए) के तहत **धारा** 31 और 28 के तहत अतिरिक्त राशि और ब्याज के रूप में ब्याज का भुगतान किया जाता है, ताकि **धारा** 23 (1–ए) के तहत अधिसूचना की तारीख से और कब्जे की तारीख से मुआवजा जमा होने तक संपत्ति के आनंद के अधिकार के नुकसान की भरपाई की जा सके।इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका के अधिकार से वंचित करने की दलील अस्थिर है।"

71. उक्त निर्णय में निर्धारित उपरोक्त सिद्धांत की जांच करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि दलितों की आवास आवश्यकता की आवश्यकता निम्नलिखित के दायरे में होनी चाहिएः सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है, कि मौजूदा मामले में आवश्यकता जिसके लिए, भूमि को तत्काल मामले में अधिग्रहित किया जाना चाहिए, i.e। देश की रक्षा के लिए, जो सभी जरूरतों के लिए सर्वोच्च है,

निश्चित रूप से देश के प्रत्येक नागरिक के व्यापक लोक हित को पूरा करना होगा और एक अधिसूचना जारी करके शक्तियों का प्रयोग भी निश्चित रूप से 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' के सिद्धांत के तहत शक्तियों के सही अभ्यास के भीतर होगा और वह भी जब हिमालय की उच्च सीमा में दुश्मन देश, चीन की फायरिंग रेंज के बाहर आने वाले स्थानों पर सैन्य चौकी के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की सिफारिश करने से पहले, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा अपनी सामरिक रिपोर्ट के आधार पर एक ठोस और ठोस निर्णय लेने की आदेशिका के साथ समर्थित किया जाता है, जो आसानी से और लगातार आकलन योग्य नहीं है, और जो लगभग 65 किलोमीटर तक संलग्न है।ट्रैक के लिए, अंतिम मोटर योग्य बिंदु से, यह वह जगह है जहाँ पूर्व तैयारी बहुत राष्ट्रीय महत्व और चिंता का विषय है।

72. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी अधिग्रहण को न्यायोचित ठहराने के लिए संतुष्ट किए जाने और विचार किए जाने के लिए अपेक्षित तत्वों का उत्तर देने के प्रयोजनों के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय का संदर्भ, जैसा कि **(1995) 5 SCC 587, U.P.** राज्य में सूचित किया गया है। और एक अन्य बनाम केशव प्रसाद सिंह प्रासंगिक हो जाता है, यह एक मामला था जहां U.P. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की मुकदमा 4/6 के तहत अधिसूचना जारी करके,

जैसा कि तब लागू था, जिसका उद्देश्य निजी मालिकों की भूमि पर दीवार के निर्माण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना था, जो उक्त मामले में प्रतिवादी थे और मुद्दा अनुदान के लिए एक दीवानी मुकदमे से उत्पन्न हो रहा था स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री।उक्त निर्णय का पैरा 4 यहाँ निकाला गया हैः–

"4. संबंधित दलीलों पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अवैध था। यह देखा गया है कि अधिग्रहित भूमि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए थी।मान लीजिए, वही भूमि वर्ष 1963 में पीडब्ल्यूडी कार्यालय के निर्माण के लिए स्वीकृत रूप से गई थी और निर्माण के बाद भवन की सुरक्षा के लिए एक सुलह की दीवार का भी निर्माण किया गया था।मुकदमा कि दीवानी अदालत ने पाया, एक वाद में साक्ष्य प्रस्तुत करने पर कि विभाग ने प्रतिवादी की भूमि पर अतिक्रमण किया था जिसे ध्वस्त करने और कब्जा देने का निर्देश दिया गया था।यह देखा गया है कि जब उस भूमि को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक था, i.e., सार्वजनिक कार्यालय के हिस्से के रूप में, राज्य प्रतिष्ठित डोमेन की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का हकदार है और कानून के अनुसार भूमि का अधिग्रहण करने के लिए उचित होगा।इसलिए, विवादग्रस्त भूमि का अधिग्रहण करने के लिए **धारा** 4 (1) को सही ढंग से उपयोग करना किया गया

था।यह सच है कि राज्य ने यह स्वीकार नहीं किया था कि उसके अधिकारियों ने प्रतिवादी की भूमि पर अतिक्रमण किया था और मामले को अपील में रखा था।दीवानी अदालत का निष्कर्ष था कि संपत्ति प्रतिवादी की है।अधिनियम के तहत कार्रवाई के तथ्य का तात्पर्य है कि दीवानी अदालत द्वारा अतिक्रमण के रूप में पाई गई भूमि की सीमा तक प्रतिवादी का अधिकार स्वीकार किया गया है। हालाँकि राज्य ने अपील दायर करने का विकल्प चुना जो लंबित होना था, ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय से गुण–दोष पर निर्णय लेने के बजाय राज्य को प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्ति का सहारा लेने के लिए बेहतर निर्णय मिला है। को ध्यान में रखते हुए तथ्य यह है कि पीडब्ल्यूडी कार्यालय भवन का निर्माण पहले से ही किया जा चुका था और भवन को सुरक्षित बनाने के लिए एक सुलह की दीवार की आवश्यकता थी और निर्माण पहले से ही किया जा चुका था, जो कि एक सार्वजनिक उद्देश्य है, कानून के तहत प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्ति का प्रयोग पूरी तरह से आवश्यक है। इसे न तो शक्ति का रंगीन प्रयोग कहा जा सकता है और न ही शक्ति का मनमाना प्रयोग।"

73. इसके बजाय उन परिस्थितियों में भी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि भूमि को सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए राज्य के सार्वजनिक कार्यालय का भाग बनाने की आवश्यकता है, यदि उसे सार्वजनिक प्रयोजन के दायरे में लाया गया है, तो उसमें निर्धारित अनुपात के अनुसार, सार्वजनिक आवश्यकता के संबंध में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है, जैसा कि मौजूदा अधिग्रहण कार्यवाही में व्यक्त किया गया है, जिसे आक्षेपित अधिसूचना द्वारा रक्षा आवश्यकताओं के प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए किया जा रहा है।यहाँ, मौजूदा परिस्थितियों में, मेरी राय के अनुसार, या उपरोक्त निर्णय में निर्धारित किए गए मापदंड, सार्वजनिक उद्देश्य की आवश्यकता के पहलू के संबंध में थे, जिसे 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' के सिद्धांत के तहत राज्य द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करने से पहले संतुष्ट किया जाना है, कि जब भारत सरकार संतुष्ट थी, तो मौजूदा मामले की परिस्थितियों में देश की रक्षा आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

74. इसलिए, मेरा विचार है कि सार्वजनिक उद्देश्य की अवधारणा के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के लिए देश की रक्षा की आवश्यकता से अधिक बेहतर विषय कुछ भी नहीं हो सकता है। भूमि का स्वामी है, उसे संपत्ति पर वरीयता का कोई अधिकार नहीं होगा, केवल इसलिए कि यह एक समाज के वर्ग से सम्बंधित है, जो संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकों की परिभाषा के दायरे में आता है, और उस स्थिति में भी, अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित भूमि का अधिग्रहण, जो एक

अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है (जो याचिकाकर्ता के हाथों तत्काल मामले में स्थापित नहीं है), उत्तरदाताओं/राज्य द्वारा किया गया अधिग्रहण दोनों तत्वों को संतुष्ट करता है और इसे न्यायिक जांच के लिए नहीं रखा जा सकता है, जिसके लिए उसकी राय के लिए तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता थी, और जो रिकॉर्ड के अनुसार काफी स्पष्ट है, कि विभिन्न रिपोर्ट, जो सक्षम वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और राज्य राजस्व विभाग के साथ–साथ भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। संभावित सैन्य संकट, जो देश के संविधान द्वारा अभिप्रेत है।

75. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय में, जैसा कि 1995 में सूचित किया गया था, सप.**(1)** एस. सी. सी. **596,** जिलुभाई नानभाई खचर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य, उक्त निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्र राज्य में लागू किरायेदारी विधि और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति से वंचित होने के इसके सह–संबंधित निहितार्थों के बारे में विचार कर रहा था, जैसा कि राज्य विधानमंडल या संसद द्वारा अधिनियमित विधि के तहत या किसी अन्य वैकल्पिक या प्रतिस्थापित विधान के तहत, सार्वजनिक उद्देश्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।अपने पैरा 30 से 36 में उक्त निर्णय ने एक बार फिर व्यापक मापदंडों के बारे में चर्चा की है कि सार्वजनिक आवश्यकता को पूरा

करने के लिए 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' के सिद्धांत की शक्ति के प्रयोग के तहत संपत्ति पर कब्जा करने के लिए किसी राज्य के अधिकार की धारणा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए के तहत संरक्षित अधिकारों के साथ संयुक्त रूप से और सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जा सकता है।राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि पर प्रभुत्व की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए और अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हुए, 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' का सिद्धांत राज्य के पास निहित संपत्ति का सर्वोच्च और सबसे परोपकारी विचार है, क्योंकि यह राज्य को संविधान और उसके तहत बनाए गए कानूनों द्वारा निर्देशित तरीके से सार्वजनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए संपत्ति का कब्जा फिर से शुरू करने का अधिकार देता है।जब भी जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शक्तियों का प्रयोग किया जाना है।लेकिन, यह रक्षा के बहाने नहीं था देश की जरूरत।उक्त निर्णय के पैरा 30 से 36 को नीचे निकाला गया हैः–

"30. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 300–ए के तहत संपत्ति का अधिकार संविधान की मूल विशेषता या संरचना नहीं है।यह केवल एक संवैधानिक अधिकार है।संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 31–बी के तहत नौवीं अनुसूची के निवास स्थान का सुरक्षात्मक छत्र होने के कारण, इसकी अयोग्यता को अनुच्छेद 31–ए के संचालन द्वारा हमले से सुरक्षित किया गया है। अन्यथा भी यह अनुच्छेद 39 *(ख)* और (ग) के अधीन आएगा जैसा कि

अपीलार्थियों द्वारा तर्क देना गया है।इसे अनुच्छेद 31–सी द्वारा संरक्षित किया गया है। हालांकि पहले मिनर्वा मिल्स मामले में, बहुमत के अनुसार, अनुच्छेद 14 को एक बुनियादी संरचना माना गया था, पहले मिनर्वा मिल्स मामले के पूर्व और अन्य पूर्ववर्ती और बाद के मामले में लगातार यह माना गया कि अनुच्छेद 14 एक बुनियादी संरचना नहीं है।संविधान का अनुच्छेद 14 संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में एक बुनियादी विशेषता या बुनियादी संरचना नहीं है।संविधान की नौवीं अनुसूची के अंतर्गत 1982 के संशोधन अधिनियम 8 को लाने वाला संविधान 66 वां संशोधन अधिनियम, 1990 संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं करता है।

31. यहां तक कि इस दलील से सहमति जताते हुए भी कि संविधान के 44 वें संशोधन अधिनियम, 1978 के पश्चात्, जो 19–6–1979 से प्रवृत्त हुआ था, संपत्ति का अधिकार अध्याय 4, भाग 17, अर्थात् अनुच्छेद 300–क में अभिलिखित है कि अपीलार्थी इसके संरक्षण के हकदार हैं, क्या **धारा** 69–क असंवैधानिक है?सीमांत ध्यान दें के साथ "संपत्ति का अधिकार" शीर्षक इस प्रकार हैः

> "300–ए। व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, कानून के अधिकार के अलावा।कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।"

जो संविधान के अनुच्छेद 31 (1) का पुनर्स्थापन है।

32. सुबोध गोपाल मामले में पतंजलि शास्त्री, C.J. ने कहा कि अनुच्छेद 31 के **धारा** (1) में 'वंचित' शब्द का संकीर्ण रूप से अर्थ नहीं लगाया जा सकता है।इस बारे में कोई कट एंड ड्राई टेस्ट तैयार नहीं किया जा सकता है कि क्या किसी दिए गए मामले में मालिक अनुच्छेद 31 के अर्थ के भीतर अपनी संपत्ति से वंचित है; प्रत्येक मामले का निर्णय

अपने स्वयं के तथ्यों पर किया जाना चाहिए।मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक न्यूनन इतनी महत्वपूर्ण होगी कि अनुच्छेद 31 के अर्थ के भीतर एक वंचितता के बराबर होगी, यदि, वास्तव में, यह संपत्ति को उसके द्वारा कब्जे और आनंद से रोकता है या भौतिक रूप से इसके मूल्य को कम कर दिया।S.R. न्यायमूर्ति दास, जैसा कि तब वे थे, ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 31 के धारा (1) और (2) "प्रतिष्ठित क्षेत्र" के विषय से संबंधित हैं, धारा (2) के अनुसार "कब्जा की गई" या "अर्जित" अभिव्यक्तियों का वही अर्थ है जो धारा (1) में 'वंचित' शब्द का प्रयोग किया गया है।दूसरे शब्दों में, दोनों धारा संपत्ति के वंचित होने से संबंधित हैं; धारा (2) में प्रयुक्त संपत्ति का कब्जा या अधिग्रहण करना धारा (1) में संपत्ति के वंचित होने के लिए संदर्भित है।कब्जा या अधिग्रहण करना सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संपत्ति के अधिग्रहण या अधिग्रहण के अर्थ में होना चाहिए।विशेष रूप से अधिग्रहण या मांग के लिए संदर्भित अभाव और किसी भी और हर प्रकार के अभाव के लिए नहीं।बॉम्बे के द्वारकादास श्रीनिवास बनाम शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड मामले में न्यायमूर्ति महाजन ने, जैसा कि तब वे थे, इसी प्रकार यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 31 के धारा (1) में 'वंचित' शब्द और धारा में अधिग्रहण और कब्जा (2) प्रतिष्ठित क्षेत्र के क्षेत्र का परिसीमन करने का एक ही अर्थ है, अर्थात्, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण और राज्य की कार्रवाई के खिलाफ निजी मालिकों को संरक्षण दिया गया है।S.R. जे. दास ने सुबोध गोपाल मामले में अपने विचार को दोहराया।न्यायमूर्ति विवियन बोस ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 31 (2) में 'कब्जा किए गए' या 'अर्जित' शब्दों को धारा (1) में 'वंचित' शब्द के साथ पढ़ा जाना चाहिए।कब्जा या अधिग्रहण लेना धारा (1) के अर्थ के भीतर वंचित करने के बराबर है।कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए।अनुच्छेद 300–ए में प्रयुक्त 'विधि' शब्द संसद या राज्य विधानमंडल का एक अधिनियम होना चाहिए, एक नियम या वैधानिक आदेश जिसमें विधि का बल हो।

संपत्ति से वंचित करना केवल कानून के अधिकार से होगा, चाहे वह संसद या राज्य विधानमंडल का अधिनियम हो, लेकिन कार्यकारी आदेश या आदेश से नहीं।संपत्ति से वंचित होना किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण या अधिग्रहण या कब्जा लेने से होता है।

33. यह सच है जैसा कि श्री झवेरी ने तर्क देना है कि **धारा** अनुच्छेद 31 का (2) अनुच्छेद 300–क में उपयुक्त रूप से शामिल नहीं किया गया था, लेकिन उसकी संपत्ति के वंचित मालिक को मुआवजा देने की बाध्यता का आदेश दिया गया था क्योंकि कानून के तहत अधिग्रहण की एक निहित घटना निम्नलिखित कारणों से समान रूप से असमर्थनीय है।रामनाथ अय्यर की द लॉ लेक्सिकन रिप्रिंट एड। **1987,**पी. **385,** "प्रख्यात क्षेत्र" को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

> **"राज्य या संप्रभु का अपनी संपत्ति पर अधिकार आत्यन्तिक है, जबकि प्रजा या नागरिक का अपनी संपत्ति पर अधिकार सर्वोपरि है।नागरिक अपनी संपत्ति को हमेशा संप्रभु के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए लेने के अधिकार के अधीन रखता है।इस अधिकार को 'प्रख्यात क्षेत्र' कहा जाता है।"**
>
> पी.386 यह आगे कहा गया था किः
>
> "सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी संपत्ति लेने की संप्रभु शक्ति राज्य में निहित है, जिसके लिए पहले न्यायसंगत मुआवजा प्रदान किया जाता है।सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी संपत्ति को लागू करने का एक बेहतर अधिकार।समाज में निहित एक उच्चतर अधिकार, और संप्रभु शक्ति द्वारा या उससे प्रत्यायोजन पर प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकारों का विषय मालिक से लिया जा सकता है

और सामान्य कल्याण के लिए विनियोजित किया जा सकता है।समाज या संप्रभु से संबंधित अधिकार, आवश्यकता के मामलों में निपटान, और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए, राज्य में निहित सभी धन को प्रतिष्ठित क्षेत्र कहा जाता है।प्रत्येक सरकार का कराधान और उसके पुलिस प्राधिकरण के अलावा, सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार।न केवल सार्वजनिक संपत्ति बल्कि क्षेत्रीय संप्रभुता के भीतर सभी नागरिकों की निजी संपत्ति को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की संप्रभु शक्ति का अंतिम अधिकार।प्रख्यात क्षेत्र सार्वजनिक उपयोग के लिए आवेदन करने के उद्देश्य से नागरिक की संपत्ति की अनिवार्य खरीद की प्रकृति में है।"

ब्लैक लॉ डिक्शनरी में, 6 वीं संस्करण, पी।523 "प्रख्यात क्षेत्र" को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

"राज्य, नगरपालिकाओं और सार्वजनिक चरित्र के कार्यों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत निजी व्यक्तियों या निगमों द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी संपत्ति लेने की शक्ति...।संयुक्त राज्य अमेरिका में, प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्ति संघीय (पाँचवाँ संशोधन) और राज्य संविधान दोनों में स्थापित है।संविधान सार्वजनिक उद्देश्य के लिए लेने की शक्ति को सीमित करता है और ली गई संपत्ति के मालिकों को उचित मुआवजे के बिना प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्ति के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है।प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्ति का प्रयोग करने की आदेशिका को आमतौर पर 'निंदा' या 'ज़ब्त' के रूप में जाना जाता है।"

34. प्रतिष्ठित क्षेत्र का अधिकार संप्रभु राज्य का, अपनी नियमित एजेंसियों द्वारा से, सार्वजनिक आवश्यकता के कारण और सार्वजनिक भलाई के लिए अपने मालिक की सहमति के बिना निजी संपत्ति सहित राज्य की भूमि के किसी भी हिस्से पर **अपने प्रभुत्व** को अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से फिर से स्थापित करने का अधिकार है।प्रतिष्ठित क्षेत्र सरकार में या लोगों के समग्र निकाय में उनकी संप्रभु क्षमता में शेष संपत्ति का सर्वोच्च और सबसे सटीक विचार है।यह संविधान और राज्य के कानूनों द्वारा निर्देशित तरीके से संपत्ति के कब्जे को फिर से शुरू करने का अधिकार देता है, जब भी सार्वजनिक हित की आवश्यकता होती है।'ज़ब्ती' शब्द व्यावहारिक रूप से 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' शब्द का पर्याय है।

35. इस न्यायालय ने चिरनजीत लाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिष्ठित क्षेत्र प्रत्येक संप्रभु में निहित अधिकार है कि वह व्यक्तिगत नागरिकों की निजी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए ले सकता है और उसे उपयुक्त बना सकता है।निजी संपत्ति के अधिग्रहण या कब्जा लेने पर लगाई गई सीमा जो अनुच्छेद 31 के **धारा** (2) में निहित है, वह यह है कि ऐसा लेना सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए।दूसरी शर्त यह है कि कोई भी संपत्ति तब तक नहीं ली जा सकती जब तक कि इस तरह के विनियोग को अधिकृत करने वाली कानून में खंड में निर्धारित तरीके से मुआवजे के भुगतान का प्रावधान न हो।बिहार राज्य बनाम परमेश्वर सिंह में, "प्रतिष्ठित क्षेत्र" को प्रत्येक संप्रभु में एक निहित अधिकार माना गया था जो मालिक की सहमति के बिना सार्वजनिक उपयोग के लिए व्यक्तिगत नागरिकों की निजी संपत्ति को लेने और उपयुक्त बनाने के लिए था।निजी संपत्ति के अधिग्रहण या कब्जा लेने पर लगाई गई सीमा जो अनुच्छेद 31 के **धारा** (2) में निहित है, वह यह है कि ऐसा लेना सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए।दूसरी शर्त यह है कि कोई भी संपत्ति तब तक नहीं ली जा सकती जब तक कि इस तरह के विनियोग को अधिकृत करने वाली कानून में खंड में निर्धारित तरीके से मुआवजे के भुगतान का प्रावधान न हो।महाजन,

जे., जैसा कि वे तब संवैधानिक कानून पर थायर के मामलों से उद्धृत कर रहे थे, ने कहा किः(एस. सी. आर. पृष्ठ 929)

"इसकी सभी घटनाओं से अलग, अनिवार्य रूप से अधिग्रहण करने की शक्ति या 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' शब्द की सरल परिभाषा स्वामी की सहमति के बिना सार्वजनिक उपयोग के लिए संपत्ति लेने की संप्रभु की शक्ति है।अपने अपरिवर्तनीय शब्दों में शक्ति का अर्थ है, (ए) लेने की शक्ति, (बी) मालिक की सहमति के बिना, (सी) सार्वजनिक उपयोग के लिए।द. सार्वजनिक उपयोग की अवधारणा शक्ति के उचित प्रयोग से अटूट रूप से संबंधित रही है और इसके अर्थ के किसी भी कथन में इसे आवश्यक माना जाता है।क्षतिपूर्ति का भुगतान, हालांकि इस शब्द के अर्थ का एक आवश्यक घटक नहीं है, इस तरह की शक्ति के वैध प्रयोग का एक आवश्यक तत्व है।"

36. बिशंभर दयाल चंद्र मोहन बनाम U.P. राज्य में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि राज्य सरकार। अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति का सहारा लेते हुए, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है।इस तरह की शक्ति का प्रयोग केवल कानून के अधिकार द्वारा किया जा सकता है न कि केवल कार्यकारी आदेश या आदेश द्वारा।इसलिए यह अनिवार्य रूप से अनुच्छेद 300–ए के बशर्ते है। इसलिए, प्रख्यात क्षेत्र प्रत्येक संप्रभु राज्य में अपने मालिक की सहमति के बिना सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति को जब्त करने का एक निहित अधिकार है, जो अनुच्छेद 300–ए में निहित है और इसका प्रयोग कानून के अधिकार द्वारा किया जाएगा, न कि कार्यकारी आदेश या व्यवस्था द्वारा।"

76. किरायेदारी कानूनों के आलोक में याचिकाकर्ताओं ठीक होना विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए बहस का उत्तर देने ठीक होना, तत्काल मामले

में, जहां याचिकाकर्ताओं द्वारा संपत्ति पर 'निहित होने का अधिकार' का दावा किया गया है, सम्बंधित, हालांकि कानून के किसी अधिकार के बिना, उक्त संदर्भ में सिद्धांत को उक्त निर्णय के पैरा 42 में निपटाया गया है जो यहां निकाला गया हैः–

> "42. कानूनी अर्थ में संपत्ति का अर्थ है अधिकारों का एक समूह जो कानून द्वारा गारंटीकृत और संरक्षित हैं।यह मूल्यवान अधिकार और हित की प्रत्येक प्रजाति, विशेष रूप से, किसी चीज़ के स्वामित्व और अनन्य अधिकार, हर कानूनी तरीके से चीज़ के निपटान का अधिकार, इसे रखने, इसका उपयोग करने और हर किसी को इसमें हस्तक्षेप करने से बाहर करने के अधिकार तक फैला हुआ है।उपयोग या स्वभाव का प्रभुत्व या अनिश्चित अधिकार जो कोई कानूनी रूप से कर सकता है विशेष वस्तुओं या विषयों पर व्यायाम को संपत्ति कहा जाता है।किसी वस्तु को रखने, आनंद लेने और निपटाने का अनन्य अधिकार कानूनी मापदंडों में संपत्ति है।इसलिए, 'संपत्ति' शब्द उन सभी चीजों को संदर्भित करता है जो स्वामित्व के अधीन हैं, भौतिक या अमूर्त, मूर्त या अमूर्त, दृश्य या अदृश्य, वास्तविक या व्यक्तिगत; वह सब कुछ जिसका विनिमय योग्य मूल्य है या जो धन या संपत्ति या स्थिति बनाने के लिए जाता है।इसलिए,

संवैधानिक संरक्षण के भीतर संपत्ति, कानून के अनुसार इसे रखने, उपयोग करने और निपटाने के अधिकार के रूप में, भौतिक चीज़ के साथ नागरिक के संबंध को विरासत में प्राप्त करने वाले अधिकारों के समूह को दर्शाती है।रामनाथ अय्यर की द लॉ लेक्सिकन में, रिप्रिंट एडन, 1987, पी।1031, यह कहा गया है कि संपत्ति उन सभी शब्दों में सबसे व्यापक है जिनका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह प्रत्येक संभावित हित का संकेत और वर्णनात्मक है जो पक्ष के पास हो सकता है।संपत्ति शब्द का सबसे व्यापक अर्थ है, और इसकी कानूनी परिभाषा के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा अपने सभी अधिग्रहणों का मुफ्त उपयोग, आनंद और स्वभाव, बिना किसी नियंत्रण या ह्रास के, केवल भूमि के कानूनों के अलावा शामिल है।द्वारकादास श्रीनिवास के मामले में इस न्यायालय ने संपत्ति शब्द को विस्तारित अर्थ दिया।खान, खनिज और खदानें अनुच्छेद 300–ए को आकर्षित करने वाली संपत्ति हैं।

77. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ अधिग्रहण के पहलू और सार्वजनिक उद्देश्य पर इसके प्रभाव के बीच सह–संबंधित अध्ययन के पहलू पर भी विचार किया है।इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ एक फैसले में प्रासंगिक टिप्पणियां की हैं 2008 में रिपोर्ट (1)

यूपीएलबीईसी **211,** मंजू लता अग्रवाल (श्रीमती.) बनाम स्टेट ऑफ़ **U.P.** और अन्य**,** और विशेष रूप से, इसके संदर्भ के लिए, उक्त मामले में सार्वजनिक उद्देश्य पर उक्त निर्णय के पैरा 11 से 14 में व्यापक रूप से चर्चा की गई है, जिसे यहां निकाला गया हैः–

> "11. दौलत सिंह सुराना अन्य ओरस में। वी.सबसे पहले भूमि अधिग्रहण कलेक्टर और अन्य ..(2007) 1 एस. सी. सी. 641, माननीय उच्चतम न्यायालय ने "लोक प्रयोजन" अभिव्यक्ति के अर्थ और दायरे पर विचार करते हुए अपने पूर्व निर्णयों की बड़ी संख्या पर विचार किया, विशेष रूप से, बॉम्बे राज्य बनाम भंजी मुंजी और एन. ;बॉम्बे राज्य बनाम अली गुलशन ;बॉम्बे राज्य v. R.S. नानजी ; बाबू बरक्या ठाकुर बनाम राज्य बॉम्बे अन्य ओआरएस। ; सोमवंती बनाम पंजाब राज्य अन्य ओआरएस। ; अन्य अर्नोल्ड रोड्रिक्स और एनर। वी.की स्थिति महाराष्ट्र और अन्य ..और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि "सार्वजनिक उद्देश्य" अभिव्यक्ति को सटीक रूप से परिभाषित करना संभव नहीं है क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।हालाँकि, सरकार यह तय करने के लिए सबसे अच्छी न्यायाधीश है कि क्या भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी करके सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। सार्वजनिक उद्देश्य में एक ऐसा उद्देश्य शामिल होना चाहिए जिसमें व्यक्ति के विशेष हित के विपरीत समुदाय का सामान्य हित प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण रूप से संबंधित हो।सार्वजनिक उद्देश्य समय और दिए गए क्षेत्र में प्रचलित परिस्थितियों के साथ बदलने के लिए

बाध्य है।इसलिए, इसे किसी विशेष ढांचे के भीतर परिभाषित नहीं किया जा सकता है।इस संबंध में सरकार द्वारा की गई घोषणा अंतिम है।न्यायालय के पास हस्तक्षेप करने के लिए न्यायिक समीक्षा की सीमित गुंजाइश केवल तभी है जब वह संतुष्ट हो कि व्यथित पक्ष द्वारा चुनौती दिए जाने पर यह शक्ति का एक रंगीन प्रयोग था।न्यायालय ने आगे निम्नलिखित निर्णय दिया:

> "सार्वजनिक उद्देश्य" स्थिर नहीं है।यह समय के साथ–साथ समुदाय की जरूरतों और आवश्यकताओं के साथ भी बदलता है।मोटे तौर पर, सार्वजनिक उद्देश्य का अर्थ है किसी व्यक्ति के हित के विपरीत समुदाय का सामान्य हित।
>
> अनिवार्य अधिग्रहण की शक्ति को "प्रतिष्ठित क्षेत्र" शब्द द्वारा वर्णित किया गया है जिसका उपयोग केवल लोगों के हित और कल्याण के लिए किया जा सकता है। सार्वजनिक उद्देश्य की अवधारणा में सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और समुदाय या बड़े पैमाने पर जनता की समृद्धि जैसे मामले शामिल होने चाहिए।
>
> "प्रतिष्ठित क्षेत्र" की अवधारणा प्रत्येक राज्य की एक अनिवार्य विशेषता है।यह अवधारणा इस मूल सिद्धांत पर आधारित है कि पूरे समुदाय का हित और दावा हमेशा किसी व्यक्ति के हित से बेहतर होता है।

12. अब तक यह भी तय हो गया है कि एक बार जब मूल अधिग्रहण वैध हो जाता है और स्वामित्व राज्य/प्राधिकरण में निहित हो जाता है तो वह अतिरिक्त भूमि का उपयोग कैसे करता है, यह मूल मालिक की चिंता का विषय नहीं है और इसे अधिग्रहण को अमान्य करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।एक वैध अधिग्रहण को रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि लंबे समय के

बाद, प्राधिकरण प्रारंभिक अधिग्रहण के समय दिखाए जाने के अलावा अपने सार्वजनिक उद्देश्य को बदल देता है।अतिरिक्त भूमि को सार्वजनिक नीलामी द्वारा भी बेचा जा सकता है, तत्कालीन मालिक भूमि के हिस्से की बहाली का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि यह राज्य में सभी बाधाओं से मुक्त है। वीडियो गुलाम मुस्तफाअन्य ओआरएस। वी.महाराष्ट्र राज्य अन्य ओआरएस। ; चंद्रगौड़ा रामगोंडा पाटिल और अन्र। वी.की स्थितिमहाराष्ट्र अन्य ओआरएस। ; ग. पद्मा अन्य अन्य। वी.डी. सरकार के सचिव। तमिलनाडु का अन्य ओआरएस। ; का स्लेटकेरल अन्य ओआरएस। वी.एम. भास्करन पिल्लई और अन्र ..; तुलसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, हैदराबाद आदि।

वी. आंध्र प्रदेश राज्य अन्य अन्य। अन्य A.P. की सरकार।और एन. वी.सैयद अकबर ..

13. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को इस बात की जांच करनी होगी, जैसा कि विशिष्ट मामले में है, कि क्या भूमि को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित करने की मांग की गई है।

14. U.P. राज्य में। वी.श्रीमती. पिस्ता देवी और ओआरएस..ए. आई. आर. 198 एफ अन्य सी. 2025, माननीय उच्चतम न्यायालय ने नारायण गोविंद गावटे आदि में अपने पहले के फैसले पर विचार किया। v. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। , जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि शहरी केंद्रों में आवासीय क्षेत्र के विकास से संबंधित योजना इतनी तात्कालिक नहीं थी कि जांच को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक था के तहत **धारा** 5ए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शहरीकरण के बाद तेजी से विकास के कारण, स्थिति पूरी तरह से बदल गई है और आवास की समस्या राष्ट्रीय तात्कालिकता का विषय बन गई है।इस तरह के विकास को न्यायिक रूप से ध्यान दें में रखते हुए, न्यायालय ने कहा कि

आवास स्थल प्रदान करने के लिए भूमि अधिग्रहण के तहत जांच का वितरण किया जा सकता है **धारा** 5 ए अधिनियम से। न्यायालय ने आगे कहा कि जहां भूमि के एक बड़े क्षेत्र का अधिग्रहण करने की मांग की जाती है, वहां नियोजित विकास की योजना को कुछ व्यक्तियों के इशारे पर न्यायिक हस्तक्षेप से हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।इस मुद्दे पर कि के तहत जारी अधिसूचना में एक चूक थी **धारा** 17 (1 –(a) अधिनियम का कृषि भूमि के संबंध में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह इस कारण से घातक नहीं था कि सरकार को अपशिष्ट और कृषि योग्य भूमि के अलावा अन्य भूमि का अधिग्रहण करने की शक्ति थी।"

78. हालांकि, वास्तव में उक्त मामले में, भूमि, जिसे अधिग्रहित करने की मांग की गई थी, मथुरा क्षेत्र में योजना विकास के उद्देश्यों के लिए थी, लेकिन जनसंख्या वृद्धि, स्थान के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए और जिसे सार्वजनिक उद्देश्य के दायरे में इस बहाने लाया गया है कि चूंकि सार्वजनिक उद्देश्य की अवधारणा को एक सख्त जालीदार सूत्र में सटीक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे सार्वजनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिग्रहण के प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर पता लगाया जाना चाहिए और उस स्थिति में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ का निर्णय, उपरोक्त निर्णय में, मौजूदा संदर्भ और अधिग्रहण के विषय में प्रासंगिक हो जाता है, यह देखा गया है कि सार्वजनिक उद्देश्य के पहलू के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए, तत्काल मामले में, जब यह अपनी

सीमावर्ती सीमा की रक्षा के लिए देश की रक्षा से संबंधित है, तो जाहिर है, यह भारत सरकार होगी, अपने रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा से, जो संयुक्त साथ मिलकर काम करना से सार्वजनिक आवश्यकता का सबसे अच्छा आकलन कर सकती है, और जिसका उपरोक्त सिद्धांतों का पालन करके तत्काल मामले में पालन किया गया है, जैसा कि भारत सरकार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए और संदर्भित विभिन्न दस्तावेजों से स्पष्ट होगा।

79. उस स्थिति में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां किसी विशेष मामले के तथ्यों के अधीन यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यह लोक प्रयोजन को संतुष्ट करता है, उस स्थिति में, अधिग्रहण को लोक प्रयोजन के प्रश्न पर न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा के विषय के रूप में नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब इसका निर्धारण पहले ही सक्षम तकनीकी प्राधिकरणों द्वारा किया जा चुका है, जिन्होंने अपनी सीमाओं के देश की रक्षा आवश्यकता के सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधिग्रहित की जाने वाली किसी विशेष भूमि की आवश्यकता पर अपनी ठोस राय व्यक्त की थी।कानूनी पूर्वस्थिति, जिसे व्युत्पन्न किया गया है, उस अवलोकन से भी निकाला जा सकता है, जो उक्त निर्णय के पैरा 39 और 40 में किया गया था, जिसे यहां निकाला गया हैः–

"39. यह एक व्यवस्थित कानूनी प्रस्ताव है कि न्यायिक समीक्षा का दायरा निर्णय लेने की प्रक्रिया तक सीमित है और प्राधिकरण के निर्णय के खिलाफ नहीं है। न्यायालय कानून की त्रुटियों या मौलिक प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को ठीक करने के लिए समीक्षा कर सकता है, जिससे प्रकट अन्याय हो सकता है और असाधारण परिस्थितियों में आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है।में। न्यायिक समीक्षा, न्यायालय सबूतों का आंकलन करना करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अधिकार क्षेत्र में खाई नहीं कर सकता है क्योंकि यह किसी निर्णय की अपील नहीं है।निर्णय की समीक्षा की अनुमति नहीं है जहां परिणाम कानूनी साक्ष्य के आधार पर एक प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए जाते हैं और उक्त परिणाम या तो इप्सी डिक्सिट या अनुमानों या अनुमानों पर आधारित नहीं हैं।न्यायालय इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि मामले में साक्ष्य के मूल्यांकन की आवश्यकता है।साक्ष्य के मूल्यांकन और साक्ष्य की पूर्ण कमी के बीच, एक सराहनीय अंतर है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

40. रिट न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति सीमित है, लेकिन यह जांचने की क्षमता है कि क्या ऐसी राय बनाने के लिए सामग्री थी जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है या संबंधित प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए परिणाम विकृत हैं।यह व्यवस्थित कानून है कि प्रासंगिक सामग्री पर विचार न करने से आदेश विकृत हो जाता है।एक निष्कर्ष को विकृत कहा जाता है जब उसे रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है या

वे कानून के के स्थान पर होते हैं या जहां वे प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के दुष्प्रभाव से पीड़ित होते हैं वीड पुरुषोत्तम चंद्र बनाम.U.P. की स्थिति ..अन्य ओआरएस। ; मोहर सिंह बनाम अध्यक्ष अधिसूचित क्षेत्र समिति, कर्नलगंज अन्य अन्य। 1956 एएलजे 759; गया दिन बनाम हनुमान प्रसाद ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 386; और विशेष संदर्भ सं. 1 का 2002 गुजरात विधानसभा चुनाव मामला।"

80. उपरोक्त निर्णय इस बात से संबंधित है कि सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 'न्यायिक समीक्षा' की शक्तियों के प्रयोग का विस्तार क्या होगा और यदि अधिग्रहण के लिए कोई द्वेष नहीं माना जाता है, और भूमि अधिग्रहण के लिए आपातकालीन स्थिति है और यह राष्ट्र के हित में है, तो इसे अदालतों के समक्ष न्यायिक जांच के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती है, और वह भी विशेष रूप से जब, सक्षम अधिकारियों द्वारा पहले ही परिस्थितियों का निर्धारण किया जा चुका है, और अंततः, खण्ड पीठ द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है। (ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, जैसा कि उक्त निर्णय के पैरा 71 में अंतर्विष्ट है, जो इसके अधीन निकाला गया है, कि किन परिस्थितियों में, सार्वजनिक प्रयोजन की अवधारणा को किसी सार्वजनिक अपेक्षा को पूरा करने के लिए आपात **धारा** के आह्वान के प्रयोजनों के लिए सर्वोत्तम रूप

से अवधारित किया जा सकता है.उक्त निर्णय का पैरा 71 नीचे दिया गया है:–

"*71.* उपर्युक्त तय किए गए कानूनी प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए, यह सामने आता है कि भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है; 'सार्वजनिक उद्देश्य' अभिव्यक्ति को एक विशिष्ट परिभाषा देकर परिभाषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे एक स्ट्रेटजैकेट सूत्र में फिट नहीं किया जा सकता है।प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच यह पता लगाने के लिए की जानी चाहिए कि क्या अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है।संपत्ति का अधिकार एक व्यक्ति का संवैधानिक/वैधानिक/मानव अधिकार है।इच्छुक व्यक्ति को इसके तहत आपत्तियां दर्ज करने का अधिकार है ***धारा*** *5–ए* यद्यपि ऐसा अधिकार यह इंगित करने के लिए सीमित है कि जिस प्रयोजन के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है वह सार्वजनिक प्रयोजन नहीं है या उक्त व्यक्ति की भूमि उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त नहीं है या अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का क्षेत्र उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए अत्यधिक होगा क्योंकि भूमि का अधिग्रहण किसी अन्य संपार्श्विक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।इस तरह की आपत्तियां एक जांच का आधार बनती हैं

धारा 5–ए अधिनियम से। असाधारण परिस्थितियों में जहां गंभीर तात्कालिकता या अप्रत्याशित आपातकाल है, सरकार निम्नलिखित में निहित तात्कालिक शक्तियों को लागू करने में सक्षम है अनुभाग *17.*अधिनियम का और बनाने से पहले कब्जा ले अधिनिर्णय.तात्कालिकता या आपात स्थिति के मामले ठीक होना सरकार यह निर्णय लेने के लिए भी सक्षम है कि आगे की देरी से बचने के लिए, निम्नलिखित जांच की परिकल्पना की गई हैः *धारा 5–ए* अधिनियम से छूट दी जानी चाहिए, लेकिन इस तरह का निर्णय लेने के लिए, सरकार के समक्ष मौजूदा और प्रासंगिक सामग्री होनी चाहिए और उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या वह तात्कालिकता ऐसी है कि इच्छुक व्यक्तियों को इसके तहत आपत्तियां दायर करने के उनके अधिकार से वंचित किया जाए *धारा 5–ए* अधिनियम से। के तहत प्रावधानों को लागू करना धारा *17 (1)* या अधिनियम के *17 (2)* स्वचालित रूप से के तहत जांच के साथ निपटान नहीं होगा *धारा 5–ए* ..इस तरह की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार द्वारा एक स्वतंत्र निर्णय लिया जाना चाहिए। *धारा 17 (4)* स्वयं इंगित करता है कि "सरकार निर्देश दे सकती है कि *धारा5–*ए लागू नहीं होगा "।आदेश में या अधिसूचना में इस तरह की राय का पाठ आवश्यक नहीं है।इस संबंध में आधिकारिक अभिलेखों में कारण

दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।यह सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि का मामला है और एक बार जब सरकार राय बनाती है और निम्नलिखित जांच को समाप्त कर देती है *धारा 5 –ए.* अधिनियम के अनुसार, न्यायालय, न्यायिक समीक्षा के अपने सीमित अधिकार क्षेत्र में, समबंध अधिग्रहण कार्यवाही को खराब घोषित नहीं कर सकता है।अधिसूचना से पहले या बाद में राज्य सरकार के अधिकारियों की ओर से देरी या सुस्ती अधिग्रहण की कार्यवाही के लिए घातक नहीं है।अक्सर अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति प्रस्तावित अधिग्रहण के खिलाफ संबंधित अधिकारियों को विभिन्न अभ्यावेदन देते हैं। आवश्यक परियोजनाओं के निष्पादन में देरी के लिए निरंतर संचार और चर्चाएँ अक्सर देरी समस्या को अधिक से अधिक तीव्र बनाती है और अधिग्रहण की आवश्यकता की तात्कालिकता को बढ़ाती है।सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कानून में कोई निषेध नहीं है, जो मास्टर प्लान में दिखाए गए भूमि उपयोग के अनुरूप नहीं है, क्योंकि मास्टर प्लान को सरकार द्वारा संशोधित/संशोधित किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा मास्टर प्लान के प्रस्तावित संशोधन/संशोधन के अनुमोदन की प्रत्याशा में मास्टर प्लान के अलावा अन्य उपयोग के लिए भूमि का अधिग्रहण शुरू किया जा

सकता है।प्रस्तावित नियोजित विकास को कुछ व्यथित व्यक्तियों के कहने पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए, जहां भूमि का एक बड़ा निहित बहुत बड़े व्यक्तियों का है। "

81. एक अन्य संविधान पीठ के निर्णय में, जैसा कि **2011 (8)** एस. सी. सी. **708,** राजीव सरीन और एक अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, पैरा 68,70,71,77 और 78 में सूचित किया गया है, जिसे यहाँ निकाला गया है:

"68. संविधान के अनुच्छेद 300–ए के अर्थ के भीतर संपत्ति से वंचित होने की घटना आमतौर पर सार्वजनिक उद्देश्य के संदर्भ में होती है।स्पष्ट रूप से, कोई भी कानून, जो किसी व्यक्ति को निजी हित के लिए उसकी निजी संपत्ति से वंचित करता है, न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।पिछले साठ वर्षों ठीक होना, हालांकि सार्वजनिक उद्देश्य की अवधारणा को काफी व्यापक व्याख्या दी गई है, फिर भी, संविधान के अनुच्छेद 300–ए को लागू करने के लिए "सार्वजनिक उद्देश्य" सबसे महत्वपूर्ण शर्त बनी हुई है।

70. भारतीय संविधान के तहत, मुआवजे के दावे को कवर करने वाले कानून का क्षेत्र संविधान की अनुसूची VII सूची III प्रविष्टि 42 में किसी की संपत्ति से वंचित होने का पता लगाया जा सकता है। संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 ने अनुसूची VII सूची I प्रविष्टि 33, सूची II प्रविष्टि 36 को हटा दिया और "संपत्ति के अधिग्रहण और अधिग्रहण" से संबंधित सूची III प्रविष्टि 42 को फिर से लिखा।संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं

रह गया है, संविधान के अनुच्छेद 300–ए में यथा उपबंधित विधि के प्राधिकार के अधीन अधिनियमित एक विधान केवल संविधान के भाग III के अभिकथित उल्लंघन के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए उत्तरदायी नहीं है।

71. जमींदारी उत्सादन कानूनों की रक्षा के लिए संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा अनुच्छेद 31–ए जोड़ा गया था। अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 31–ए (1) (ए) से (जी) के तहत गिने गए विषय–वस्तु के संबंध बताए गए कानूनों को चुनौती देने के अधिकार को भी संवैधानिक रूप से बाहर रखा गया था।इसके अलावा, संविधान की नौवीं अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 31–बी सभी कानूनों की रक्षा करता है, भले ही वे संविधान के भाग III का उल्लंघन करते हों।हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि I.R में संवैधानिक पीठ के फैसले में। कोएल्हो बनाम स्टेट ऑफ T.N.15 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संविधान की नौवीं अनुसूची में जोड़ी गई विधियां, 24–12–1973 के पश्चात् संवैधानिक संशोधनों का उल्लंघन करके, मूल संरचना सिद्धांत की तरह आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए उत्तरदायी होंगी।

77. संविधान के अनुच्छेद 31 (2) को संविधान (44 वां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।यह ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 300–ए को संविधान (44 वां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31 (1) को व्यावहारिक रूप से पुनः सम्मिलित करके जोड़ा गया था। इसलिए, संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि संविधान द्वारा परिकल्पित और प्रदत्त एक अधिकार है और वह भी संविधान के केवल अनुच्छेद 31 (1) को बनाए रखते हुए

और विशेष रूप से अनुच्छेद 31 (2) को हटाकर, जैसा कि यह था। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए संपत्ति के अधिकार की पूरी अवधारणा को उस मानसिकता से अलग मानसिकता के साथ देखा जाना चाहिए जो उस अवधि के दौरान प्रचलित थी जब प्रतिष्ठित क्षेत्र की अवधारणा मूल अधिकार का सन्निहित प्रावधान थी।लेकिन अब भी संविधान के अनुच्छेद 300–ए के तहत राज्य के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए आगे बढ़ सकता है विनिर्दिष्ट उपयोग लेकिन राज्य विधानमंडल द्वारा से या संसद द्वारा और कानून के बल वाले तरीके से एक कानून अधिनियमित करके।"

82. यह एक ऐसा मामला था, जो अधिग्रहण की कार्यवाही और उत्तराखंड राज्य में लागू किरायेदारी कानूनों से इसके सह–संबंधित निहितार्थ, विशेष रूप से कुमाऊं जमींदारी उत्सादन और भूमि सुधार अधिनियम 1960 की धारणा से उत्पन्न हुआ था।तर्क का एक प्रमुख भाग, जो किरायेदारी अधिकारों के निहित होने पर आधारित था, जिसे याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है, इस निर्णय के पहले भाग में इस न्यायालय द्वारा पहले ही निपटा दिया गया है, लेकिन उक्त मामला कुमाऊं जमींदारी उत्सादन और भूमि सुधार अधिनियम 1960 की धारा 12,4 और 19 के प्रभाव से संबंधित पहलू से संबंधित था, हालांकि जो यहां मामला नहीं है, जिसे वैध दस्तावेजी अधिकारों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी अनुरोध या तर्क दिया गया था क्योंकि यहां तर्क को सीमित कर दिया

गया है, याचिकाकर्ताओं द्वारा U.P. की धारा 4 और 6 के तहत निहित होने के अधिकारों के दावे द्वारा। Z.A. & L.R. अधिनियम, क्योंकि उन्होंने 1880 से सम्बंधित भूमि पर अपने अधिकार और अधिकार का दावा किया है, और उक्त प्रश्न और निहित करने के प्रभाव का सिद्ध इस न्यायालय द्वारा लक्ष्मण लाल (सुप्रा) में खण्ड पीठ के निर्णय के आलोक में पहले ही दिया जा चुका है, कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 क के तहत निहित संवैधानिक अधिदेश के आलोक में, भूमि पर अधिकार निहित करने का क्या प्रभाव होगा।

83. संविधान पीठ ने उपरोक्त निर्णय में कहा था कि संपत्ति की परिभाषा, जो केवल इस तथ्य के आलोक में न्यायिक अभ्यास किया जाना है कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पैरा 68 में यह निर्धारित किया है कि सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी संपत्ति के वंचित होने की घटना में अभी भी निजी संपत्ति के अधिग्रहण के अधिकार के आह्वान के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक होगा और इसे किस हद तक न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा, कानून के क्षेत्र के आलोक में, जो संविधान की सातवीं अनुसूची, सूची–III, प्रविष्टि–42 द्वारा कवर किया गया है, केवल संपत्ति के वंचित होने पर मुआवजे की पर्याप्तता के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए सीमित किया गया है।

84. संविधान पीठ ने अपने पैरा 77 के फैसले में, जिसे पहले ही ऊपर निकाला जा चुका है, अनुच्छेद 31 के प्रभावों और संविधान 44 वें संशोधन अधिनियम 1978 के आधार पर किए गए निरसन के प्रभाव और भारत के संविधान के अनुच्छेद 300–ए को शामिल करने के प्रभाव पर विचार करते हुए कहा था कि संपत्ति के अधिकार की पूरी अवधारणा को हालांकि कमजोर कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इसे एक अलग धारणा और परिस्थितियों से देखा जाना चाहिए, जो संपत्ति के अधिग्रहण के समय की स्थिति के दौरान प्रचलित है, विशेष रूप से जब राज्य अपनी अवधारणा के तहत प्राधिकरणों के सिद्धांत द्वारा प्रदान किए गए हैं। 'क्षेत्र' संपत्ति पर कब्जा करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन यह एकमात्र राइडर के साथ है, जिसे पैरा 77 में की गई टिप्पणियों के अनुसार संलग्न किया गया है, कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए को संरक्षित किया जाना है और राज्य एक कानून बनाकर या सार्वजनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिग्रहण की एक कानून को लागू करके विशिष्ट सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए आगे बढ़ सकता है, और इस न्यायालय का विचार है कि तत्काल मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, अधिग्रहण को आवश्यक बनाते हुए, उक्त पहलू को इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त पैराग्राफ में काफी विस्तार से निपटाया गया है, और

न्यायिक समीक्षा के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकृति के बशर्ते किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया गया है।

85. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने (2011) 9 एस. सी. सी. 1, के. टी. प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य में दिए गए एक अन्य निर्णय में इस अवधारणा पर विचार किया था कि किसी व्यक्ति की संपत्ति से वंचित होने के पहलुओं के संबंध में सह–संबंधित अध्ययन कैसे किया जा सकता है या किया जाना आवश्यक है। निजी व्यक्ति और कैसे और किस संदर्भ में, 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' के सिद्धांत को विस्तार योग्य बनाया जा सकता है और सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए जारी अधिसूचना की न्यायिक समीक्षा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्यों के लिए लागू किया जा सकता है।उक्त निर्णय में जिस प्रश्न पर विचार किया गया था, उसमें कहा गया था कि यद्यपि संपत्ति को अपने अधिकार में लेने का अधिकार राज्य को निहित किया गया है, 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' की अपनी निहित शक्ति के प्रयोग के तहत सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, लेकिन फिर उस अधिकार को आगे बढ़ाते हुए, जिसकी उसमें परिकल्पना की गई है, उन निजी व्यक्तियों के अधिकारों को छिपाता या प्रभावित नहीं करता है, जिनकी भूमि को कानून के अनुसार पर्याप्त मुआवजा प्राप्त करने के लिए लिया गया है, क्योंकि यह भारत के

संविधान के अनुच्छेद 300 ए के तहत संरक्षित है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ पढ़ा जाना है, जहां मुआवजे का अधिकार अधिग्रहित भूमि की प्रकृति, उसके अधिकार और कानून के अनुसार मुआवजा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की पात्रता के अनुसार निर्धारित किया जाना है, जिसकी भूमि के बारे में कहा गया है।

86. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधानसभा के उक्त निर्णय में, वास्तव में, कर्नाटक राज्य की विधान सभा ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके आधार पर उन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड संगठन के वृक्षारोपण के लिए भूमि और चल संपत्तियों के अधिग्रहण के प्रयोजनों के लिए 1996 के अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम को लागू किया था और वर्ष 1991 में पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत भूमि का एक हिस्सा खरीदा था, जो राज्य के पास था।उक्त मामले में, माननीय संविधान पीठ ने पैरा 119 में किए गए और अभिलिखित किए गए अपने अवलोकन में, जो यहां निकाला गया है, कहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए के तहत किसी व्यक्ति के अधिकार के तहत, न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए की कसौटी पर एक अधिग्रहण की वैधता की न्यायिक समीक्षा में उद्यम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अधिग्रहण एक अवधारणा है, जो राज्य के लिए उपलब्ध है, i.e। ऐसा अधिराज्य जिसके साथ संपत्ति अपने 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' की

शक्ति का प्रयोग करने के लिए निहित है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 300क के अधीन आरक्षित अधिकारों के संबंध में सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना है, जब भी किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति से वंचित किया जाता है।उक्त निर्णय का पैरा 119 यहाँ निकाला गया है:–

> "119. अब हम संविधान के अनुच्छेद 300–ए की कसौटी पर अधिग्रहण अधिअधिनियम की वैधता की जांच करेंगे और जांच करेंगे कि क्या प्रतिष्ठित क्षेत्र की अवधारणा को अनुच्छेद 300–ए और किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करने के लिए अधिअधिनियमित क़ानून में पढ़ा जाएगा।"

87. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पैरा 132 में भी संविधान पीठ के उक्त निर्णय में, 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' के सिद्धांत के तहत राज्यों द्वारा शक्तियों के प्रयोग की अवधारणा पर विचार करते हुए अपने सिद्धांत को निकाला है, जिसे एक प्राकृतिक और आत्यन्तिक अधिकार माना जाता है, जो कि समाज में अब एक परंपरा है, लेकिन किसी व्यक्ति के अधिकारों को लेने के लिए राज्य द्वारा प्राकृतिक और पारंपरिक अधिकारों का प्रयोग, यह मत व्यक्त किया था कि दर्शन, उन विचारकों के अनुसार, जिन्होंने सिद्धांतों और परिस्थितियों को निर्धारित किया था, जिनके तहत भूमि पर कब्जा किया जा सकता था, उन्होंने कहा था कि इसके मालिकों पर संपत्ति का अधिकार आत्यन्तिक है।लेकिन, इसके साथ–साथ निश्चित

रूप से एक निश्चित सामाजिक जिम्मेदारी भी शामिल है, अगर इसे पूरा करने की आवश्यकता है और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी सार्वजनिक की आवश्यकता को स्थापित करने के लिए या देश की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी निजी संपत्ति को अधिग्रहित किया जा सकता है और फिर उस स्थिति में, सार्वजनिक हित हमेशा नागरिक या व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रबल होगा, लेकिन यह किसी निजी व्यक्ति के मुआवजे को प्राप्त करने के प्राकृतिक अधिकार को बाधित नहीं करेगा, यदि अधिग्रहण के परिणामों के कारण संपत्ति का स्वामित्व उनसे विभाजित किया जाता है (बशर्ते उनके पास हो)।उक्त निर्णय का पैरा 132 नीचे दिया गया हैः–

> "132. ह्यूगो ग्रोटियस, पुफेंडॉर्फ, जॉन लॉक, रूसो और विलियम ब्लैकस्टोन जैसे प्रख्यात विचारकों ने संपत्ति के अधिकार पर अपने विचार व्यक्त किए थे।एक प्राकृतिक और आत्यन्तिक अधिकार के रूप में संपत्ति की लोकियन बयानबाजी लेकिन नागरिक समाज में पारंपरिक है, इसकी जड़ें अरस्तू और एक्विनास में हैं, क्योंकि ग्रोटियस और पुफेंडॉर्फ संपत्ति प्राकृतिक और पारंपरिक दोनों थी।ग्रोटियस की तरह, पुफेंड्रॉफ ने कभी यह नहीं माना कि उसके मालिकों पर संपत्ति का अधिकार आत्यन्तिक है, लेकिन इसमें निश्चित सामाजिक जिम्मेदारियां शामिल हैं, और यह भी विचार रखा कि निजी संपत्ति की

स्थापना केवल इस उद्देश्य के लिए नहीं की गई थी कि "एक व्यक्ति को दूसरों की सेवा में इसका उपयोग करने से बचने की अनुमति दी जाए, और अपने धन के भंडार पर एकांत में रहने की अनुमति दी जाए।"ग्रोटियस की तरह, पुफेंडॉर्फ ने माना कि अत्यधिक आवश्यकता वाले लोगों को दूसरों की संपत्ति पर अधिकार हो सकता है।रूसो के लिए, संपत्ति एक पारंपरिक नागरिक अधिकार था न कि एक प्राकृतिक अधिकार और निजी संपत्ति का अधिकार सार्वजनिक हित के अधीन था, लेकिन रूसो ने जोर देकर कहा कि उनका उल्लंघन करना कभी भी सार्वजनिक हित में नहीं होगा।"

88. इसकी निरंतरता ठीक होना, संविधान पीठ के उक्त निर्णय ठीक होना 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' के सिद्धांत पर प्रसिद्ध दार्शनिक ह्यूगो ग्रोटियस द्वारा निर्धारित दर्शन के आधार पर विचार किया गया था, जिसठीक होना उन्होंने कहा है कि 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' के सिद्धांत हालांकि उन कार्यों पर लागू होते हैं, जो सार्वजनिक अधिकारों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं, या जो किए जाने हैं, जिनका निजी अधिकारों पर अतिव्यापी प्रभाव और वरीयता हो सकती है, लेकिन 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' के सिद्धांत की शक्तियों के प्रयोग के प्रयोजनों के लिए कुछ बुनियादी पूर्व आवश्यकताएं हैं, जिन्हें पूरा करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है:–

a)कि 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' की शक्तियों का प्रयोग जनता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए है;

b) सार्वजनिक निधि से मुआवजे को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भूमि खोने वाले को देय किया जाए, जो अपना अधिकार खो देता है।

c)इसने यह निर्धारित किया है कि 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' का सिद्धांत पूरी तरह से अधिनियम का विषय है और यह हमेशा एक ऐसी स्थिति होगी जो विशेष देश के संवैधानिक जनादेश पर निर्भर करती है, जिस पर उक्त सिद्धांत को सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए संपत्ति प्राप्त करने के लिए लागू किया जा रहा है।

89. यह कहने सम्बंधित जरूरत नहीं है कि इस मामले में, भूमि को रक्षा आवश्यकता के लिए लिया जा रहा है और सामान्य मानवीय विवेक और राष्ट्र के प्रति, हमारे राष्ट्र के नागरिक सम्बंधित धारणा सम्बंधित संवेदनशीलता के तहत, रक्षा कर्मियों सम्बंधित आवश्यकता हमेशा सार्वजनिक उद्देश्य के दायरे में आएगी और यह सार्वजनिक अधिकार है, जिससम्बंधित रक्षा भी सम्बंधित जानी चाहिए और इसलिए, अधिग्रहण। उपरोक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत अधिकारों को ओवरलैप करेगा, जैसा कि तत्काल मामले में होता है।

90. उक्त निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त पैराग्राफ में की गई टिप्पणियों की पृष्ठभूमि के तहत 'प्रख्यात डोमेन' के सिद्धांत के अनुप्रयोग के प्रभाव की व्याख्या करते हुए, जो निकाला गया है, इस सिद्धांत के सैद्धांतिक पहलू पर भी विचार किया था कि 'प्रतिष्ठित डोमेन' का सिद्धांत जो अभी भी लागू रहेगा, भारत के संविधान के हटाए गए अनुच्छेद 31 के तहत, और भारत के संविधान के मौजूदा अनुच्छेद 30 (1ए) के तहत, जैसा कि संविधान (44 वां संशोधन अधिनियम 1978) W.E.F. द्वारा डाला गया है। 20.06.1979 और अनुच्छेद 31क के दूसरे परन्तुक के अधीन, जैसा कि स्पष्ट होगा, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 क के निहितार्थ से अपवर्जन मेंहै।

91. मौजूदा मामले में, चूंकि कोई आसन्न खतरा है और न ही याचिकाकर्ताओं द्वारा यह मामला प्रस्तावित किया गया है कि वे उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन्हें देय किए जाने वाले पर्याप्त मुआवजे से वंचित हो जाएंगे, इसलिए उपरोक्त सिद्धांत और उक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए सुरक्षा उपाय राज्य को 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' के सिद्धांत को लागू करने के लिए बचाव करेंगे, जब संपत्ति का अभाव होता है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए द्वारा बचाया गया है।

92. उक्त निर्णय में, इसके पैरा 166 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए के तहत संरक्षित अधिकारों के निहितार्थ को मापदंडों में निपटाया गया है,

जिसे पैरा 166 में निर्धारित किया गया है, जिसे यहाँ निकाला गया हैः–

> 166. अनुच्छेद 300–क, जब उन परिस्थितियों के आलोक में जांच की जाती है जिनके तहत इसे डाला गया था, तो निम्नलिखित परिवर्तन प्रकट होंगेः
>
> 1. भारत के संविधान के तहत संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है।
> 2. विधायिका किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल कानून के अधिकार से वंचित कर सकती है।
> 3. संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान का अधिकार संविधान की मूल विशेषता नहीं है, बल्कि केवल एक संवैधानिक अधिकार है।
> 4. संपत्ति का अधिकार, चूंकि अब मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को आम तौर पर उपयोग करना नहीं किया जा सकता है, व्यथित व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है।"

93. क्योंकि संविधान के अधीन किसी व्यक्ति के संपत्ति धारण करने के मौलिक अधिकार की समाप्ति को इस प्रकार संरक्षित किया गया है कि विधानमंडल किसी व्यक्ति को कानून सम्यक प्रक्रिया और देश की रक्षा की मूल संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए संपत्ति के

अधिग्रहण और निपटान के अधिकार के अलावा संपत्ति धारण करने से वंचित नहीं कर सकता है, जैसा कि यह तत्काल मामले में है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए का सख्त सिद्धांत है, क्योंकि यह संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा करता है, और अधिग्रहण पर मुआवजा प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पर्याप्त मुआवजे के भुगतान के साथ संगत किया जाए, जो हमेशा एक तथ्य रहा है जो ऊपर पहले ही अनुरोध किया गया है और साथ ही प्रतिवादीओं द्वारा उठाए गए अभिवचनों द्वारा, कि उचित मुआवजा भुगतान किया जाए देश की रक्षा के लिए अधिग्रहण की आवश्यकता को पूरा करना।माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उक्त निर्णय के अपने पैरा 180 में, सार्वजनिक प्रयोजन के पहलू पर विचार करते समय, जहां संपत्ति का अभाव है, यह केवल सार्वजनिक उद्देश्य या सार्वजनिक हित के लिए होना चाहिए।इसने यह भी निर्धारित किया है कि 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' का सिद्धांत, जो केवल तभी लागू होता है जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित होता है, जब इसे विशेष रूप से सार्वजनिक आवश्यकता और सार्वजनिक आवश्यकता को पूरा करने और सार्वजनिक हित में माना जाता है।इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि केवल एक आकस्मिक लाभ किसी संपत्ति का अधिग्रहण करके उसे वंचित करने का कारण नहीं हो सकता है, उसमें से वंचित होना वैध, निष्पक्ष और देश के हित में या सार्वजनिक हित में होना चाहिए और एक बार जब यह

उपरोक्त मापदंडों को संतुष्ट करता है, तो इसे न्यायिक समीक्षा के बशर्ते नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यह विधानमंडल है, जिसे उपरोक्त पहलुओं को निर्धारण करना है, और विशेष रूप से तत्काल मामले में, ऊपर उल्लिखित पत्राचार के अनुसार, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर, जिसके लिए 2009 से लगातार दुश्मन के आक्रमण के खतरे की धारणा को देखते हुए कदम उठाए गए थे, तत्काल मामले में अधिग्रहण निश्चित रूप से गिर जाएगा।यदि सार्वजनिक प्रयोजन की अवधारणा, जैसा कि उपरोक्त निर्णय में देखा गया है, यद्यपि इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया है, जब भी कोई अधिग्रहण किसी सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसा कि अधिग्रहण अधिसूचना में समझाया गया है, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए को लागू करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त, लागू किए जाने से इनकार कर दिया गया है और, जो तत्काल मामले में भी, विशेष रूप से संरक्षित किया गया है।

94. इसी प्रकार, संविधान पीठ के उपर्युक्त निर्णय में 'सार्वजनिक प्रयोजन' और 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' के सिद्धांत की उपरोक्त दो अवधारणाओं का उत्तर देते हुए, इसके तहत तैयार किए गए संदर्भों की परिकल्पना उक्त निर्णय के पैरा 221 के उप–पैरा (ई) के तहत की गई है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक उद्देश्य का अस्तित्व किसी व्यक्ति को

संपत्ति से वंचित करने के मौजूदा एक पूर्व शर्त है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए के तहत संरक्षित है और वंचितता के मौजूदा मुआवजे का दावा करने का अधिकार विधायी रूप से उस खंड के तहत एक अंतर्निहित आदेशिका होना चाहिए जिसके तहत किसी व्यक्ति को राज्य की आवश्यकता को पूरा करने के मौजूदा उसकी संपत्ति से वंचित करने के मौजूदा अधिग्रहण किया जाना है और जो विशेष रूप से निम्नलिखित योजनाओं पर निर्भर करेगाःपैरा 221 का उप–पैरा (ई) नीचे निकाला गया हैः–

> "221. हम, इसलिए, संदर्भ का उत्तर इस प्रकार देते हैं निम्नलिखित हैः
>
> (ए).....
>
> (ई) अनुच्छेद 300–ए के तहत किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करने के लिए सार्वजनिक उद्देश्य एक पूर्व शर्त है और क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार भी उस अनुच्छेद में अंतर्निहित है और जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित हो जाता है तो राज्य को दोनों आधारों को उचित ठहराना होगा जो अधिनियम की योजना, विधायी नीति, विधायिका के उद्देश्य और उद्देश्य और अन्य संबंधित कारकों पर निर्भर कर सकते हैं।"

95. एक अन्य पहलू, जो विवाद से निपटने के लिए भी प्रमुख महत्व का होगा, जबकि याचिकाकर्ताओं ने 2013 के अधिनियम की **धारा** 11 (2) के तहत अधिसूचना को चुनौती दी थी, "प्रख्यात क्षेत्र" के सिद्धांत के

दृष्टिकोण से होगा।"प्रतिष्ठित क्षेत्र" का सिद्धांत सरकार को एक अनन्य और निहित प्रमुख शक्ति प्रदान करता है, जो राष्ट्र के क्षेत्र के भीतर आने वाली किसी भी भूमि का सर्वोच्च मालिक है, भूमि और संपत्ति ठीक होना कब्जा करने के लिए, हालांकि दिए गए कानून के नियमों और शर्तों के तहत, किसी भी सैन्य आक्रमण के कारण, किसी भी अचानक दुश्मन विद्रोह, राष्ट्रीय आपदा या देश और देश की ऐसी आकस्मिक आवश्यकता के अन्य क्षेत्रों का सामना करने के लिए समूह की तैयारी, जहां समय हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जहां यह विशेष रूप से केवल देश की आवश्यकता है, जिस ठीक होना विचार किया जाना है। माननीय न्यायालयों द्वारा विभिन्न निर्णयों में प्रतिष्ठित क्षेत्र के पहलू पर विचार किया गया है, जिन पर विस्तृत रूप से विचार किया जा रहा है।

96. यद्यपि, यह न्यायालय पहले ही इस विषय पर विचार कर चुका है कि कौन से मूल तत्व हैं, जो 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' के सिद्धांत के तहत राज्य द्वारा शक्तियों के प्रयोग को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन मूल तत्व, जिन्हें सिद्धांत के व्यापक सिद्धांत को लागू करने के लिए संतुष्ट करने की आवश्यकता थी। ए. आई. आर. 1953 असम 84, महिंद्रा मोहन लाहिड़ी और अन्य बनाम में रिपोर्ट किए गए एक निर्णय में 'प्रमुख क्षेत्र' को वापस माना गया है। असम राज्य, जिसमें एक संपदा अधिनियम की संवैधानिक वैधता को सार्वजनिक उद्देश्य और राज्य

सरकार के प्रबंधन के लिए भूमि के हस्तांतरण के लिए चुनौती दी गई थी।उक्त निर्णय में, उसने अपने पैरा 13 और 15 में इस पहलू पर विचार किया था, जिसे यहाँ निकाला गया हैः–

"13. श्री घोष के दलील का जवाबअनुच्छेद 19 (1) (च) धारा (5) के साथ पढ़ें लेख 19. यह है।जब राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम 1935 के अधिनियम में मद 9 द्वारा कवर किया जाता है, तो यह राज्य द्वारा अपने प्रमुख अधिकार क्षेत्र की शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किया गया एक अधिनियम है, और इसलिए, निम्नलिखित प्रावधानों के बशर्ते नहीं है – अनुच्छेद 19 (1) (च)), भारत का संविधान, ठीक उसी तरह जब राज्य विधानमंडल द्वारा अपनी पुलिस शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत अक्षमता या विकलांगता के कारण या सार्वजनिक आदेश के हित में उसकी संपत्ति से वंचित करने वाला कोई अधिनियम पारित किया जाता है, तो वह निम्नलिखित प्रावधानों के बशर्ते नहीं है – लेख 19 (1) (च)। मामले के इस पहलू पर उनके सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप्स द्वारा दो मामलों में विचार किया गया है जिसमें व्याख्या शामिल है अनुच्छेद 21 , भारत का संविधान। अनुच्छेद 21 इन शब्दों में हैः

"21.कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 31 (1)), भारत का संविधान कहता हैः

"31.(1) किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के अलावा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

का उल्लेख करते हुए अनुच्छेद 21 और इसका प्रभाव लेख 19., कामा सी. जे. ने कहाः

"व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित (कुल हानि), जिसे अभिव्यक्ति 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' द्वारा संरक्षित करने की मांग की जाती है। अनुच्छेद 21 , काफी अलग है

स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार के प्रतिबंध (जो केवल एक आंशिक नियंत्रण है) से (जो एक नागरिक का अपेक्षाकृत एक छोटा अधिकार है) लेख 19. व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने का अर्थ भारत के क्षेत्र में मुक्त आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के समान नहीं है।इसलिए, लेख 19 (5) किसी नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने वाले मूल कानून पर लागू नहीं हो सकता है।यह दलील कि व्याख्या करते समय 'अभाव' शब्द के दायरे में 'प्रतिबंध' शामिल है अनुच्छेद 21 , स्वीकार्य नहीं है। "

ये अवलोकन की व्याख्या के लिए समान बल के साथ लागू होते हैं अनुच्छेद 31. जहां, इसलिए, एक व्यक्ति कानून के अधिकार द्वारा अपनी संपत्ति से वंचित है, द्वारा गारंटीकृत संपत्ति के मौलिक अधिकार के उल्लंघन का प्रश्न अनुच्छेद 19 (1) (च) जो व्यक्ति राज्य की पुलिस शक्ति के प्रयोग में या अपनी प्रतिष्ठित अधिकार क्षेत्र की शक्ति के

प्रयोग में अपनी संपत्ति से वंचित हो गया है, उसके लिए उस अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का सवाल ही नहीं उठता है।

15. तब हमारा निष्कर्ष यह है कि आक्षेपित अधिनियम एक वैध अधिनियम है और असम (विधानमंडल) के अधिकार क्षेत्र में है; कि द्वारा गारंटीकृत संपत्ति के मौलिक अधिकार के उल्लंघन का प्रश्न अनुच्छेद 19 (1) (च) यह अधिनियम राज्य की प्रतिष्ठित अधिकार क्षेत्र की शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है; कि सार्वजनिक उद्देश्य की उपस्थिति प्रदर्शित करने योग्य है।

97. 1953 का उपरोक्त प्राधिकरण है।यह देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकरण द्वारा उसकी संपत्ति से वंचित किया जाता है, जैसा कि तत्काल मामले में होता है, तो संपत्ति पर अधिकार के उल्लंघन का सवाल, भले ही, यह मौजूदा कानून के तहत एक संवैधानिक अधिकार के रूप में मौजूद नहीं है, यह विचार के लिए उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि व्यक्ति को राज्य की शक्तियों के प्रयोग से संपत्ति पर अपने अधिकार से वंचित कर दिया गया है कानून के अनुसार 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' का सिद्धांत, और इसलिए, यह बहुत उद्देश्य को पूरा करता है, और इसलिए, इस न्यायालय की राय के अनुसार, यह बहुत उद्देश्य को पूरा

करता है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 300 ए के तहत भूमि मालिक द्वारा प्रदान और संरक्षित किया गया है।

98. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2006) 2 एस. सी. सी., 545, बिहार राज्य और अन्य बनाम परियोजना उच्च विद्या, शिक्षक संघ और अन्य में दिए गए एक निर्णय में, 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' के सिद्धांत की अवधारणा को दोहराते हुए, और जिन सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है, उन्हें इसके पैरा 65 और 66 में निर्धारित किया गया है, जो यहां निकाला गया है, कि किन परिस्थितियों में, सरकार की आवश्यकता के लिए भूमि का अधिग्रहण 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' के सिद्धांत के सिद्धांत के भीतर लाया जा सकता है।उक्त निर्णय के पैरा 65 और 66 को नीचे उद्धृत किया गया हैः–

> "65. "अधिग्रहण" शब्द का अर्थ होगा कि सरकार ने शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों के साथ स्कूलों की संपत्तियों और परिसंपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेने के बारे में सोचा था।राज्य के नीतिगत निर्णय के संदर्भ में स्कूलों का अधिग्रहण स्कूल के प्रबंधन के पूर्ण अधिग्रहण के इरादे की अभिव्यक्ति नहीं प्रतीत होता है।पहले ऐसे स्कूलों का अधिग्रहण संविधान के अनुच्छेद 300–ए का उल्लंघन होगा।अनुच्छेद 300–ए में दो भाग शामिल हैं, (i) सार्वजनिक हित में संपत्ति का अधिग्रहण; और (ii) इसके लिए उचित मुआवजे का भुगतान।

66. जिलुभाई नानभाई खाचर में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः(एस. सी. सी. पृष्ठ 622, पैरा 34) "34. प्रतिष्ठित क्षेत्र का अधिकार संप्रभु राज्य का, अपनी नियमित एजेंसियों द्वारा से, राज्य की मिट्टी के किसी भी हिस्से पर अस्थायी या स्थायी रूप से अपने प्रभुत्व को फिर से स्थापित करने का अधिकार है। जिसमें सार्वजनिक आवश्यकता के कारण और सार्वजनिक भलाई के लिए अपने मालिक की सहमति के बिना निजी संपत्ति शामिल है।प्रतिष्ठित क्षेत्र सरकार में या लोगों के समग्र निकाय में उनकी संप्रभु क्षमता में शेष संपत्ति का सर्वोच्च और सबसे सटीक विचार है।यह संविधान और राज्य के कानूनों द्वारा निर्देशित तरीके से संपत्ति के कब्जे को फिर से शुरू करने का अधिकार देता है, जब भी सार्वजनिक हित की आवश्यकता होती है।'ज़ब्ती' शब्द व्यावहारिक रूप से 'प्रख्यात क्षेत्र' शब्द का पर्याय है।"" ""

99. ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 471, दौलत सिंह सुराना और अन्य बनाम प्रथम भूमि अधिग्रहण कलेक्टर और अन्य में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में, यह अधिग्रहण के एक मामले की परिस्थितियों से निपट रहा था, जो पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा किया जा रहा था, जहां मौलिक अंतर्निहित सिद्धांत समग्र रूप से समुदाय का हित और दावा था, जिसका हित व्यक्ति के हित से बेहतर माना गया है, क्योंकि उक्त मामले में, लोगों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया गया था।इसलिए, उक्त मामले में यह मत व्यक्त किया गया कि अनिवार्य अधिग्रहण की शक्ति का उपयोग हित में और लोगों के कल्याण के लिए और विशेष रूप से लोगों के कल्याण के लिए किया जा

सकता है, जो तत्काल मामले में, एक मजबूत एकीकृत देश का गठन करने के लिए संविधान की प्रस्तावना के साथ है, जहां इसमें रहने वाले व्यक्ति की सुरक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, i.e. उसका नागरिक और समग्र रूप से देश की समृद्धि सार्वजनिक प्रयोजन के क्षेत्र के अंतर्गत आएगी, जहां यह कहा जा सकता है कि 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' की शक्ति का प्रयोग राज्य द्वारा उचित रूप से किया गया था, जैसा कि पैरा 39,40,41 में उक्त निर्णय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, जबकि सार्वजनिक प्रयोजन की व्यापक अवधारणा से संबंधित और पैरा 73,74,75 और 76 में, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "सार्वजनिक उद्देश्य" और "प्रतिष्ठित क्षेत्र" को पूरा करने के लिए सामंजस्यपूर्ण निर्माण निर्धारित किया गया है।पैरा 39,40,41,73,74,75 और 76 यहाँ निकाले गए हैंः–

"39. भूमि अधिग्रहण अधिनियम में सार्वजनिक उद्देश्य को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

"3. (च) 'लोक प्रयोजन' पद में निम्नलिखित शामिल हैं –

(i) ग्राम स्थलों का प्रावधान, या मौजूदा ग्राम स्थलों का विस्तार, नियोजित विकास या सुधार;

(ii) नगर या ग्रामीण नियोजन के लिए भूमि का प्रावधान;

(iii) सरकार की किसी योजना या नीति के अनुसरण में सार्वजनिक निधियों से भूमि के नियोजित विकास के लिए भूमि का प्रावधान और योजना के अनुसार आगे विकास

सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पट्टा, समनुदेशन या एकमुश्त बिक्री द्वारा उसका पूर्ण या आंशिक रूप से बाद में निपटान;

(iv) राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम के लिए भूमि का प्रावधान;

(v) गरीबों या भूमिहीनों या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों या सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम द्वारा शुरू की गई किसी योजना के कार्यान्वयन के कारण विस्थापित या प्रभावित व्यक्तियों को आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि का प्रावधान;

(vi) ऐसी किसी योजना को चलाने के लिए सरकार द्वारा या सरकार द्वारा स्थापित किसी प्राधिकारी द्वारा प्रायोजित किसी शैक्षिक, आवास, स्वास्थ्य या झुग्गी निकासी योजना को चलाने के लिए भूमि का उपबंध, या उपयुक्त सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी स्थानीय प्राधिकारी या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन पंजीकृत सोसायटी द्वारा, या किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी संगत विधि के अधीन, या किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी समितियों से संबंधित किसी विधि के अर्थ के भीतर किसी सहकारी समिति द्वारा;

(vii) सरकार द्वारा प्रायोजित विकास की किसी अन्य योजना के लिए या उपयुक्त सरकार के पूर्व अनुमोदन से स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भूमि का प्रावधान;

(viii) सार्वजनिक कार्यालय का पता लगाने के लिए किसी परिसर या भवन का प्रावधान, लेकिन इसमें कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण शामिल नहीं है।"

40. सार्वजनिक उद्देश्य में एक ऐसा उद्देश्य निहित होगा जिसमें किसी व्यक्ति के हित के विपरीत समुदाय का सामान्य हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निहित हो।जहाँ तक भूमि अधिग्रहण के संबंध में सार्वजनिक उद्देश्य का संबंध है, व्यक्तिगत हित को सार्वजनिक हित के लिए रास्ता देना चाहिए।

41. भारत के संविधान में, जहां तक सार्वजनिक उद्देश्य का संबंध है, संविधान के अनुच्छेद 37 में कुछ दिशानिर्देशों का पता लगाया जा सकता है।इस भाग (राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत) में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, लेकिन उसमें निर्धारित सिद्धांत फिर भी देश के शासन में मौलिक हैं।इन सिद्धांतों को कानून बनाने में लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।

73. सार्वजनिक उद्देश्य को सटीक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए और जहां तक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण का संबंध है, इसका दायरा और दायरा सीमित होना चाहिए।सार्वजनिक उद्देश्य स्थिर नहीं है।यह समय के साथ–साथ समुदाय की जरूरतों और आवश्यकताओं के साथ भी बदलता है।मोटे तौर पर, सार्वजनिक उद्देश्य का अर्थ है किसी व्यक्ति के हित के विपरीत समुदाय का सामान्य हित।

74. "प्रतिष्ठित क्षेत्र" शब्द द्वारा वर्णित अनिवार्य अधिग्रहण की शक्ति का उपयोग केवल लोगों के हित और कल्याण के लिए किया जा सकता है।सार्वजनिक उद्देश्य की अवधारणा में सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और समुदाय या बड़े पैमाने पर जनता की समृद्धि जैसे मामले शामिल होने चाहिए।

75. "प्रतिष्ठित क्षेत्र" की अवधारणा प्रत्येक राज्य की एक अनिवार्य विशेषता है।यह अवधारणा इस मूल सिद्धांत पर आधारित है कि पूरे समुदाय का हित और दावा हमेशा किसी व्यक्ति के हित से बेहतर होता है।

76. जिस सार्वजनिक उद्देश्य के लिए तत्काल मामले में परिसर की आवश्यकता थी, उस पर गंभीरता से सवाल नहीं उठाया गया था। वास्तव में, पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस उपायुक्त (सुरक्षा नियंत्रण) का कार्यालय बनाकर लोगों सम्बंधित सुरक्षा के लिए छह दशकों से अधिक समय से इस परिसर का उपयोग कर रहा है।इसलिए, किसी भी कल्पना से, यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा लोगों के हित और कल्याण के लिए परिसर की आवश्यकता नहीं थी या विचाराधीन परिसर के अधिग्रहण में कोई सार्वजनिक उद्देश्य सम्बंधित नहीं था।"

100. एक मामले में, जो केरल उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न हो रहा था, जैसा कि (2009) 8 एस. सी. सी. **46,** केरल राज्य और अन्य बनाम में सूचित किया गया था। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, केरल राज्य इकाई और अन्य, यह उस मामले से निपट रहे थे, जहां केरल सरकार ने भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने और राज्य की अनुसूचित जनजातियों की अलग–थलग की गई भूमि की बहाली और गैर–जनजातीय निवासियों से जनजातीय भूमि की वसूली के उद्देश्यों के लिए एक कानून बनाया है।प्रारंभ में, इस मामले का निर्णय केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किया गया था, और बाद में, इसने केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष यात्रा की, और अंततः, अनुसूचित जनजातियों को दिए गए आरक्षण का अधिकार, अधिनियम 1999 की **धारा** 5 (1) और 5 (2) और **धारा** 6 और **धारा** 22 के तहत उनकी भूमि की बहाली के उद्देश्यों के लिए, जिसे केरल

उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक व्यक्ति भूमि पर एक अक्षम्य अधिकार प्राप्त करता है, लेकिन फिर भी, भूमि का मालिक, उसे प्रचलित कानून का सहारा लेने और 'प्रतिष्ठित डोमेन' के सिद्धांत के तहत इसकी शक्ति का प्रयोग करके ही इससे वंचित किया जा सकता है, और यही है इस बारे में निर्णय कि किस और किन परिस्थितियों में, 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' के सिद्धांत के तहत अवधारणा या शक्ति का प्रयोग राज्य द्वारा जनजातीय समुदाय की भूमि के अधिग्रहण के संबंध में भी किया जा सकता है।पैरा 87,88 और 89 को नीचे निकाला गया हैः

> 87. इसलिए वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में की जानी चाहिए।अतः इस न्यायालय के निर्णय स्पष्ट और असंदिग्ध हैं।अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से जुड़े मामले में सीमा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यह उस क्षेत्र के संबंध में अनुमत नहीं है जिसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है।
>
> **88.** जब कोई व्यक्ति एक अक्षम्य अधिकार प्राप्त करता है, तो उसे प्रतिष्ठित क्षेत्र के सिद्धांत का सहारा लेकर ही उससे वंचित किया जा सकता है।यदि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा अर्जित अक्षम्य अधिकार से वंचित करने की मांग की जाती है, तो उसे मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।इस प्रकार के मामले में, जहां वास्तव में मुआवजे की राशि नहीं दी गई है, भूमि के विक्रेताओं को बेदखल किए जाने के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।मामले के उस दृष्टिकोण में, ऐसे मामले के बीच अंतर किया जाना चाहिए जहां मुआवजे की राशि का भुगतान किया गया है और ऐसे मामले में जहां यह नहीं किया गया है।

89. यदि किसी निहित अधिकार को नहीं खोया गया है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के लागू होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 को इस आधार पर लागू करने के लिए आगे बढ़ाया कि 1999 के अधिनियम के प्रावधान स्पष्ट रूप से 1975 के अधिनियम 31 द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को दिए गए अधिकार को नष्ट करने का प्रयास करते हैं।उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही नहीं होने के कारण इसे स्थिर नहीं रखा जा सकता है।"

101. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2010) 10 एस. सी. सी. 43, अमरजीत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य में दिए गए एक अन्य निर्णय में इस अवधारणा पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि निम्नलिखित अधिकारों की परिकल्पना की गई है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 300ए, राज्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' के सिद्धांत पर आधारित है।इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक आवश्यकता के लिए 'प्रमुख क्षेत्र' के सिद्धांत के लिए शक्ति का प्रयोग, भूमि पर स्वामित्व के व्यक्तिगत अधिकारों को व्यापक सार्वजनिक आवश्यकता के लिए प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए और जहां अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है, विधानमंडल द्वारा निर्धारित मापदंडों के तहत उचित और उचित मुआवजे का भुगतान करने के बाद, तब सार्वजनिक आवश्यकता के लिए भूमि अधिग्रहण करने में कोई

गलती नहीं पाई जा सकती है।प्रासंगिक पैरा 31,36,47 और 48 यहाँ निकाले गए हैंः–

"31. अधिनियम की धारा 178 में "समीचीन" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।ब्लैक लॉ डिक्शनरी, हालांकि, अभिव्यक्ति "समीचीन "को निम्नलिखित अर्थ प्रदान करता हैः

"अंतिम दृष्टि से उपयुक्त और उपयुक्त–किसी निर्दिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के कारणों में जो भी उपयुक्त और उपयुक्त हो।"

36. पंजाब क्षेत्रीय और नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1995 की धारा 178 के तहत सरकार के पक्ष में आरक्षित छूट की शक्ति का उद्देश्य भी अधिनियम के संचालन से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करना है। इसका उद्देश्य सरकार को उन स्थितियों से निपटने में सक्षम बनाना है जिनमें कठिनाइयों के सवाल से स्वतंत्र परिस्थितियां छूट देकर ऐसा करना समीचीन बनाती हैं।इसलिए, धारा 178 (2) के प्रावधानों पर एक उदार निर्माण किया जाना चाहिए ताकि अच्छे और प्रामाणिक कारणों के लिए शक्ति का प्रयोग विफल न हो।

47. संविधान का अनुच्छेद 300–ए प्रतिष्ठित क्षेत्र के सिद्धांत पर आधारित है और कानून के अधिकार के अलावा संपत्ति से वंचित होने के खिलाफ संवैधानिक अधिकार की गारंटी देता है।यह अनिवार्य करता है कि वैध होने के लिए

संपत्ति से वंचित करना कानून के अधिकार से होना चाहिए।यह कि मौजूदा मामले में ऐसा वंचन विधि के प्राधिकार द्वारा किया गया है, विवादित नहीं था, क्योंकि यह सामान्य आधार है कि अपीलार्थियों के स्वामित्व वाली संपत्ति भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के संदर्भ में अर्जित की गई है, जो वैध रूप से अधिनियमित विधान है।

48. यह भी विवाद में नहीं है कि चुनौती के तहत अधिग्रहण के लिए राज्य द्वारा उपयोग करना भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों में अधिग्रहण की अनिवार्य प्रकृति के लिए मुआवजे, अतिरिक्त मुआवजे और ब्याज आदि जैसे अन्य लाभों के अलावा प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख को संपत्ति के बाजार मूल्य के बराबर मुआवजे का भुगतान करने का प्रावधान है। इन सभी राशियों का योग निस्संदेह ज़ब्त किए गए मालिकों से अधिग्रहित भूमि के लिए एक उचित मुआवजा है।न तो संविधान के अनुच्छेद 300–ए और न ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम में जब्त किए गए मालिकों के पुनर्वास के लिए कोई उपाय किया गया है, जो भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए एक शर्त है।अनुच्छेद 300–ए के तहत या किसी अन्य वैधानिक प्रावधान के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व की अनुपस्थिति में में, मालिकों के पुनर्वास को संपत्ति के वैध अधिग्रहण के लिए एक आवश्यक आवश्यकता के रूप में नहीं माना जा सकता है।"

102. (2011) 5 एस. सी. सी. 553 में दिए गए एक निर्णय में, राधेश्याम और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, फिर से एक मामला था, जहां धारा 4 (1) के तहत अधिग्रहण के लिए एक अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जहां ग्रेटर नोएडा के विकास प्राधिकरण द्वारा जिले में एक

नियोजित औद्योगिक विकास के उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की गई थी।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जहां अधिग्रहण की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, अपने पैरा 16,17 और 77 में, जिसे यहां निकाला गया है, व्यापक रूप से उन परिस्थितियों के बारे में चर्चा की है जिनके तहत, 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' के सिद्धांत के निहित अभ्यास की शक्तियां जो संप्रभु राज्य के पास निहित हैं। सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए एक निजी व्यक्ति की संपत्ति लेने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।उक्त निर्णय में कहा गया है कि सार्वजनिक उद्देश्य या सार्वजनिक हित की अवधारणा जिसका उपयोग निजी मालिक की भूमि को लेने के लिए ढाल के रूप में नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाना चाहिए।सक्षम प्राधिकारी संपत्ति का अधिग्रहण करने से पहले और एक तात्कालिक **धारा** का आह्वान करने से पहले गलती से बिना किसी वैध कारण के तत्काल **धारा** का आह्वान करके भूमि अधिग्रहण अधिनियम की तत्कालीन **धारा** 5 के तहत निहित प्रावधानों का पालन किए बिना संपत्ति का अधिग्रहण करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने से बच सकता है।

"16. शुरुआत में, हम उस अनौपचारिक तरीके से अपनी अस्वीकृति दर्ज करते हैं जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को जवाबी–हलफनामा दायर करने और प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहे बिना रिट याचिका का निपटारा किया।रिट याचिका के पैरा

11 और 16 और ग्राउंड ए और एफ में निहित अभिकथनों का पठन, जो ऊपर निकाले गए हैं, अपीलार्थियों के इस कथन के साथ कि उनकी भूमि का अधिग्रहण भेदभाव के कारण किया गया था क्योंकि प्रभावशाली व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहण से छूट गई थी, लेकिन राज्य सरकार की भूमि को छोड़ने की नीति की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिस पर आवास इकाइयों का निर्माण पहले ही किया जा चुका था, यह दर्शाता है कि वे रिट याचिका में उठाए गए मुद्दा की गहन जांच के लिए एक मजबूत मामला बनाने में सफल रहे थे और उच्च न्यायालय ने उन्हें संक्षेप में गैर–उपयुक्त करके गंभीर त्रुटि की थी।

17. भूमि अधिग्रहण विधानों के इतिहास से पता चलता है कि 19 वीं शताब्दी में, 1824 का बंगाल विनियमन 1,1850 का अधिनियम 1,1857 का अधिनियम 6,1863 का अधिनियम 21,1870 का अधिनियम 10,1839 का बॉम्बे अधिनियम 28,1850 का बॉम्बे अधिनियम 17,1852 का मद्रास अधिनियम 20 और 1854 का मद्रास अधिनियम 1 को मध्यस्थों द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करके सड़कों, नहरों और अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि और अन्य अचल संपत्तियों के अधिग्रहण की सुविधा के लिए अधिनियमित किया गया था।1870 में अधिग्रहित भूमि के उचित मूल्यांकन के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू किया गया था।उस अधिनियम की परिकल्पना की गई थी कि यदि भूमि में रुचि रखने वाला व्यक्ति उसे दी गई राशि को स्वीकार करके कब्जा देने के लिए सहमत नहीं है, तो कलेक्टर सिविल कोर्ट को संदर्भित कर सकता है।1870 के अधिनियम में सिविल न्यायालय की सहायता के लिए मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति

की भी परिकल्पना की गई थी।यदि अदालत और मूल्यांकनकर्ता राशि पर सहमत नहीं होते हैं तो उच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है।यह तंत्र अप्रभावी साबित हुआ क्योंकि मुकदमेबाजी में बहुत समय लग जाता था।इस समस्या को दूर करने के लिए, विधायिका ने अंग्रेजी भूमि खंड समेकन अधिनियम, 1845 की तर्ज पर अधिनियम अधिनियमित किया।हालांकि, भूमि मालिकों या भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का अधिग्रहण आदेशिका में या तो 1894 से पहले के विधानों के तहत या 1894 के अधिनियम (गैर–संशोधित) के तहत कोई योगदान नहीं था।वे केवल मुआवजे की राशि और उससे जुड़े मामलों पर आपत्ति उठा सकते थे।भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आपत्ति उठाने का अवसर न मिलने पर उन लोगों ने नाराजगी जताई जो अपनी भूमि की अनुपस्थिति में थे।इस कष्ट के निवारण के लिए 1923 के अधिनियम 38 में संशोधन करके अधिनियम में **धारा** 5–ए जोड़ी गई थी।

77. विभिन्न मामलों में इस न्यायालय द्वारा प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के विश्लेषण और उनकी व्याख्या से निम्नलिखित सिद्धांतों को निकाला जा सकता हैः

(i) प्रख्यात क्षेत्र प्रत्येक संप्रभु में निहित एक अधिकार है जो नागरिकों की संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है।दूसरे शब्दों में कहें तो संप्रभु को राज्य की भूमि के किसी भी हिस्से पर अपने प्रभुत्व को फिर से स्थापित करने का अधिकार है, जिसमें उसके मालिक की सहमति के बिना निजी संपत्ति भी शामिल है, बशर्ते कि ऐसा दावा सार्वजनिक आवश्यकता के कारण और सार्वजनिक भलाई के लिए हो– द्वारकादास श्रीनिवास बनाम शोलापुर एसपीजी। और डब्ल्यूवीजी।

कंपनी लिमिटेड, चरणजीत लाल चौधरी बनाम भारत संघ और जिलुभाई नानभाई खचर बनाम गुजरात राज्य।

*(ii)*राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्रावधान करने वाले कानून अनुचित कानून की श्रेणी में आते हैं और इस तरह के कानून का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए–*DLF* कुतुब एन्क्लेव कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल पूर्त न्यास बनाम हरियाणा राज्य; महाराष्ट्र राज्य बनाम *B.E*। बिलीमोरिया और देव शरण बनाम स्टेट ऑफ *U.P.*

(iii) हालांकि, प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्ति का प्रयोग करते हुए, सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, यह याद रखना चाहिए कि किसी की संपत्ति को अनिवार्य रूप से लेना एक गंभीर मामला है।यदि संपत्ति समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्ग या अन्य बाधाओं से पीड़ित लोगों की है, तो न्यायालय न केवल अधिक सतर्कता, देखभाल और चौकसी के साथ राज्य की कार्रवाई/निर्णय की जांच करने का हकदार है, बल्कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भूमि मालिक के भूमिहीन होने और अपनी आजीविका और/या आश्रय के एकमात्र स्रोत से वंचित होने की संभावना है।

(iv) अधिनियम की धारा 4,5–ए और 6 के अधिदेश का पालन किए बिना किसी नागरिक की संपत्ति राज्य और/या उसकी एजेंसियों/उपकरणों द्वारा अर्जित नहीं की जा सकती है। एक सार्वजनिक उद्देश्य, चाहे वह कितना भी प्रशंसनीय क्यों न हो, राज्य को तात्कालिक प्रावधानों को लागू करने का अधिकार नहीं देता है क्योंकि इसका प्रभाव मालिक को बिना सुने संपत्ति के अधिकार से वंचित करने का होता है।केवल वास्तविक तात्कालिकता के मामले में, राज्य तात्कालिक प्रावधानों को लागू कर सकता है और भूमि मालिक या अन्य इच्छुक व्यक्तियों को सुनने की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है।

(v)धारा 17 (4) के साथ पठित धारा 17 (1) राज्य को धारा 5–क के अधिदेश का अनुपालन किए बिना निजी संपत्ति अर्जित करने की असाधारण शक्ति प्रदान करती है। इन प्रावधानों को केवल तभी उपयोग करना किया जा सकता है जब अधिग्रहण का उद्देश्य कुछ हफ्तों या महीनों की देरी को रोक नहीं सकता है।इसलिए, धारा 5–ए के आवेदन को हटाने से पहले, संबंधित प्राधिकरण को पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि धारा 5–ए के तहत जांच करने में कुछ हफ्तों या महीनों का समय, सभी संभावनाओं में, सार्वजनिक उद्देश्य को विफल कर देगा, जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है।

(vi) तात्कालिकता के मुद्दे पर सरकार की संतुष्टि व्यक्तिपरक है, लेकिन धारा 17 (1) के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती है और इसे इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि जिस उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की मांग की गई है, वह बिल्कुल भी सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है या कि शक्ति का प्रयोग दुर्भावना के कारण दूषित है या संबंधित अधिकारियों ने प्रासंगिक कारकों और अभिलेखों पर अपना दिमाग नहीं लगाया है।

(vii) धारा 17 (1) के तहत सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से अधिनियम की धारा 5–ए का अपवर्जन नहीं होता है, जिसके संदर्भ में भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति आपत्ति दर्ज कर सकता है और अपनी आपत्ति के समर्थन में सुनवाई का हकदार है।धारा 17 की उपधारा (4) में "मे" शब्द का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि यह केवल सरकार को यह निदेश देने में समर्थ बनाता है कि धारा 5–क के उपबंध खंड 17 की उपधारा (1) या (2) के अधीन आने वाले मामलों पर लागू नहीं होंगे।दूसरे शब्दों में, धारा 17 (4) का आह्वान धारा 17 (1) के तहत शक्ति के प्रयोग का एक आवश्यक सहवर्ती नहीं है।

(viii) आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण को **धारा** 4 के अर्थ के भीतर सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अधिग्रहण के रूप में माना जा सकता है, लेकिन यह अपने आप में **धारा** 17 (1) और/या 17 (4) के तहत सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग को उचित नहीं ठहराता है। न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकता है कि आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत क्षेत्रों के विकास से संबंधित योजनाओं की योजना, निष्पादन और कार्यान्वयन में आमतौर पर कुछ साल लगते हैं।इसलिए, **धारा** 17 (1) में निहित तात्कालिक प्रावधान को लागू करके ऐसे उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है।किसी भी दशा में, ऐसे मामलों में धारा 5–क (1) और (2) में सन्निहित ऑडी अल्टेराम दूसरे पक्ष को भी सुनो नियम का अपवर्जन बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है।

(ix) यदि भूमि का अधिग्रहण निजी व्यक्तियों के लाभ के लिए किया जाता है, तो न्यायालय को धारा 17 (1) और/या 17 (4) के आह्वान को संदेह के साथ देखना चाहिए और ऐसे अधिग्रहण की वैधता पर निर्णय लेने से पहले प्रासंगिक रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए।"

103. उक्त निर्णय में यह प्रावधान किया गया है कि भूमि का अधिग्रहण करने वाले सक्षम अधिकारियों द्वारा यह हमेशा संतुष्ट किया जाना चाहिए, जब तात्कालिकता **धारा** का उपयोग करना जा रहा है कि भूमि पर कब्जा करना राज्य की वास्तविक आकस्मिक आवश्यकता है और यह वास्तविक आकस्मिक आवश्यकता के पहलू से संबंधित है, कि 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' के सिद्धांत की शक्तियों का प्रयोग केवल वास्तव में प्रयोग किया

जाएगा, जब देरी सार्वजनिक आवश्यकता के लिए अधिग्रहण के उद्देश्य को बाधित करेगी।

104. यदि उक्त सिद्धांत को मौजूदा मामले की परिस्थितियों में लागू किया गया है, तो जाहिर है कि अधिसूचना ने 2013 के अधिनियम की **धारा** 9 के तहत छूट **धारा** को आकर्षित किया है, जहां 2013 के अधिनियम की **धारा** 9 के आह्वान ने 2013 के अधिनियम की **धारा** 40 और 21 के आवेदन को समाप्त कर दिया है।इस न्यायालय की राय के अनुसार, आकस्मिक आवश्यकता या आकस्मिक आवश्यकता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए कि तत्काल आवश्यकता की आवश्यकता और उद्देश्य क्या है, जिसे भूमि अधिग्रहण के लिए व्यक्त किया गया है।सड़क की आवश्यकता को पूरा करने के लिए या एक आधिकारिक आवास के निर्माण के लिए विशेष रूप से उत्पीड़ित समुदाय को आवासीय आवास प्रदान करने के लिए भूमि अधिग्रहण में कुछ महीनों की देरी, उन्हें स्थगित या स्थगित किया जा सकता है और मामले की विशेष परिस्थितियों में माना जा सकता है कि यह एक आकस्मिक आवश्यकता नहीं है।लेकिन, यदि इसे मौजूदा मामले की परिस्थितियों में पढ़ा और सहसंबद्ध किया जाता है, तो मेरा विचार है कि आक्षेपित अधिसूचना के तहत अधिग्रहण का इरादा भूमि अधिग्रहण से पहले एक वास्तविक दुश्मन समूह की कार्रवाई का मतलब नहीं है, क्योंकि एक बार जब यह देश की रक्षा के

पहलू से निपट रहा है, तो यह बिना कहे चला जाता है कि अधिग्रहण की कार्यवाही को वास्तविक विद्रोह की प्रतीक्षा करने में देरी नहीं की जा सकती है, क्योंकि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की स्थलाकृति और लंबी दूरी की गोलीबारी के भारी यांत्रिक उपकरणों के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित सशस्त्र बलों की तैनाती के उद्देश्य को देखते हुए, इसके लिए युद्ध की तैयारी के एक महत्वपूर्ण पहलू और तैयारी के तत्व पर विचार करने की आवश्यकता है। किसी देश की रक्षा अपने आप में एक तत्काल आवश्यकता होगी, जिसमें किसी भी तरह से देरी नहीं की जा सकती है और वह भी, मौजूदा मामले में, जब 1962 के भारत–चीन युद्ध के बाद इसका आकलन किया गया था, जब पहली बार सीमा चौकी को 1968 में तैनात किया गया था, और बाद में, इसे भारत सरकार द्वारा दो दर्रों की रक्षा के लिए आईटीबीपी की 14 वीं बटालियन की तैनाती के लिए लिया गया निर्णय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो भारतीय क्षेत्र में पड़ोसी देश, चीन की दुश्मन समूह द्वारा प्रवेश का आसान सुलभ क्षेत्र था, और गृह मंत्रालय के साथ निर्णय के साथ रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए पत्राचार के अनुसार, यह था और इसमें तैयारी का एक तत्व था, जो वास्तविक सैन्य कार्रवाई की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था, इसलिए यह एक निर्णय था।

105. इस प्रकार, मौजूदा मामले में अधिग्रहण की प्रकृति, सभी तत्वों, सार्वजनिक उद्देश्य को संतुष्ट करती है; जनता की आवश्यकता; देश की रक्षा की आवश्यकता; किसी भी अचानक सैन्य विद्रोह का सामना करने के लिए सैन्य कर्मियों की तैयारी; उच्च हिमालय में समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर युद्ध किराए पर रक्षा कर्मियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए; और इसके अलावा और कुल मिलाकर, देश की रक्षा को व्यक्तिगत आवश्यकता को ओवर ट्रैक करने और दरकिनार करने के लिए पर्याप्त सुनिश्चित किया जाना है, भले ही इसे कानून के तहत कुछ सुरक्षा दी जानी हो, क्योंकि कानून को तर्कसंगत रूप से लागू किया जाना चाहिए और जब इसकी रक्षा की बात आती है तो देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उदार रूप से समझा जाना चाहिए।

106. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक हालिया निर्णय में, जैसा कि (2020) 9 एससीसी **356,** हरि कृष्ण मंदिर ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य में बताया गया है, यह एक ऐसा मामला था, जहां यह पुणे में एक निजी सड़क से संबंधित विवाद से संबंधित था, जिसे पुणे नगर निगम के स्वामित्व वाली सड़क के रूप में घोषित किया जा रहा था, हालांकि अभिलेखों के अनुसार, इसे निजी व्यक्ति के नाम पर और एक निजी सड़क के रूप में दर्ज किया गया था।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा 96 और 97 में भारत के संविधान के

अनुच्छेद 300क के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' के सिद्धांत के तहत यह निर्धारित किया था कि 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' के सिद्धांत में व्यापक रूप से दो तत्वों की पूर्व संतुष्टि शामिल है (i) कि संपत्ति का कब्जा विशेष रूप से सार्वजनिक उद्देश्य और सार्वजनिक हित के लिए लिया गया है और (ii) सार्वजनिक उद्देश्य या सार्वजनिक हित की अवधारणा के तहत कब्जा लेने का पालन उचित मुआवजे के भुगतान के साथ किया जाना है।उक्त फैसले में कहा गया है कि संपत्ति का अधिकार, हालांकि इसे संविधान संशोधन के बाद मौलिक अधिकार नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी, यह एक संवैधानिक अधिकार है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत संरक्षित है, जिसमें मानवाधिकारों की सुरक्षा की बुनियादी संरचना है और कार्यकारी या प्रशासनिक निर्णय का मनमाने ढंग से भारत के संविधान के अनुच्छेद 300ए की भावना के खिलाफ प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक आवश्यकता की अवधारणा के तहत उसके निजी अधिकार से वंचित किया जा सकता है। कानून के अनुसार मुआवजा दिया जाता है।पैरा 96 और 97 को नीचे निकाला गया हैः–

> "96. संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है, लेकिन यह अभी भी अनुच्छेद 300–ए के तहत एक संवैधानिक अधिकार है और एक मानव अधिकार है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा विमलाबेन अजीतभाई पटेल बनाम वत्सलाबेन अशोकभाई पटेल में कहा गया है।भारत के संविधान के अनुच्छेद

300–ए के जनादेश को देखते हुए, किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के अलावा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है।अपीलकर्ता न्यास को कानून के अनुसार छोड़कर उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है।

97. भारत के संविधान के अनुच्छेद 300–ए में प्रतिष्ठित क्षेत्र के सिद्धांत का समावेश है, जिसमें दो भाग शामिल हैं, (i) सार्वजनिक हित में संपत्ति का कब्जा; और (ii) उचित मुआवजे का भुगतान।जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बिहार राज्य बनाम परियोजना उच्च विद्या, शिक्षक संघ; जिलुभाई नानभाई कछार बनाम गुजरात राज्य; बिशंभर दयाल चंद्र मोहन बनाम यू. पी. राज्य सहित कई निर्णयों में अभिनिर्धारित किया गया है, राज्य के पास जनता के लाभ के लिए स्वामी की संपत्ति को लेने या नियंत्रित करने की शक्ति है। तथापि, जब कोई राज्य ऐसा कार्य करता है तो वह गिरनार व्यापारी बनाम महाराष्ट्र राज्य में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित न्यायसंगत प्रतिकर देकर क्षति की भरपाई करने के लिए बाध्य है।

107. उपर्युक्त प्राधिकारियों के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को इस विवाद को इस अवधारणा से भी देखना होगा कि सार्वजनिक उद्देश्य की अवधारणा पर श्री जे. नारायण द्वारा लिखित "सार्वजनिक उद्देश्य की अवधारणा" नामक पुस्तक में भी विचार किया गया है।उक्त पुस्तक में, एक बार फिर, यह प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा भूमि पर कब्जा करने की शक्ति हमेशा सामाजिक और आर्थिक सुधारों और देश के नागरिक के शांतिपूर्ण और सुरक्षित जीवन पर असर डालने वाले इसके व्यावहारिक बड़े सामाजिक परिणामों के पाठगत संदर्भ में होनी चाहिए।

108. उक्त पुस्तक में, इसने उल्लेख किया था कि तकनीकी रूप से, न्यायपालिका के पास अभी भी यह निर्धारण की अंतिम शक्ति है कि क्या अधिग्रहण मामले की परिस्थितियों के दिए गए सेट में सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति की गई है या नहीं, लेकिन प्रकृति और इसकी जटिलता, जिसका मूल्यांकन एक आधुनिक राज्य के भविष्य में, सामान्य रूप से और राष्ट्र के व्यापक हित में किया जा सकता है, विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को अत्यधिक उन्मूलन करने के लिए, जो देश की बुनियादी आवश्यकता हो सकती है, यह सरकार को सामाजिक कल्याण और सामाजिक सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने की आवश्यकता को चुनने में अधिक विवेकाधिकार देता है ताकि देश को भविष्य की किसी भी व्यावहारिक जटिलताओं से विकसित किया जा सके और सुरक्षित किया जा सके।

109. श्वाट्र्ज द्वारा लिखित एक अन्य पुस्तक में, जो "द कमेंटरी ऑन द कांस्टीट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स" थी, रिंज कंपनी बनाम लॉस एंजिल्स और ब्रैग बनाम वीवर के दो प्रमुख निर्णयों का उल्लेख करते हुए, यह प्रावधान किया गया है कि "सार्वजनिक उपयोग के लिए एक निजी संपत्ति को विनियोजित करने की आवश्यकता, एक न्यायिक प्रश्न नहीं है।यह शक्ति स्वाभाविक रूप से विधानमंडल में रहती है और इसका

प्रयोग या तो विधानमंडल द्वारा या लोक अधिकारी को सौंपी गई शक्ति के तहत किया जा सकता है।इसके पृष्ठ संख्या 259 में आगे यह प्रावधान किया गया है कि "क्या यह आवश्यक है, और यह स्पष्ट है कि दी गई संपत्ति को लिया जाना चाहिए, विधायी प्रश्न हैं और कोई बात नहीं है कि किस पर और निर्णय द्वारा आरोप लगाया जा सकता है और उस पर सुनवाई आवश्यक नहीं है, यदि कानून के अनुसार सम्यक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।"द. जैसे ही संपत्ति के मालिक को एक न्यायिक मंच का आश्वासन दिया जाता है, संवैधानिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, जिसमें वह यह प्रदर्शित कर सकता है कि क्या वह इस मुद्दे को संभाल सकता है कि भूमि वैध सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ली गई है और उसकी संपत्ति और नुकसान का मूल्य स्थापित कर सकता है, जिसका वह हकदार होगा।

110. अर्थात्, उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भी, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहण के उद्देश्य पर जांच का निहितार्थ न्यायालयों, यहां तक कि संवैधानिक न्यायालयों द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक तत्व और कारकों को निर्धारित करने के संदर्भ में बहुत सीमित है।तथापि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण की अनिवार्यता के लिए तैयार किया गया निष्कर्ष एक अनन्य विधायी निर्धारण है, और इसे विधायी अधिदेश या कानून

के अधिकार क्षेत्र पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जो ऐसे विषयों को नियंत्रित करता है और इसे न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं बनाया जा सकता है।

111. संवैधानिक अपेक्षाएं तब तक पूरी होती हैं, जब तक संपत्ति के मालिकों को आश्वासन दिया जाता है और न्यायिक मंच प्रदान किया जाता है, जिसमें कोई यह प्रदर्शित कर सकता है कि क्या वह इन अधिकारों को बनाए रख सकता है कि भूमि का अधिग्रहण वैध सार्वजनिक उद्देश्य के उद्देश्यों के लिए नहीं है या यदि वह अपनी संपत्ति और नुकसान का मूल्य स्थापित करने में समर्थ है, जिसके लिए वह हकदार होगा। सार्वजनिक आवश्यकता के लिए निजी संपत्ति प्राप्त करने के लिए कानून के तहत एकमात्र सुरक्षा, और विशेष रूप से, राष्ट्र की आवश्यकता और इसकी रक्षा के लिए, संविधान के अनुच्छेद 300 ए के तहत सुरक्षा को वैध मुआवजा प्राप्त करने के लिए संरक्षित किया जाना है। क्षति या संपत्ति का मूल्य, जिसे इस प्रकार अपने अधिकार में ले लिया गया है।

112. उस पहलू की जांच केवल एक सार्वजनिक उद्देश्य के अस्तित्व को निर्धारण की सीमा तक सीमित है और एक पहलू यह है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति लेने की आवश्यकता एक विधायिका का निर्धारण है, और यह विशेष रूप से विधायिका या प्राकृतिक न्याय के

लिए होगा, जैसे कि संविधान और प्रशासन के मंत्रिस्तरीय प्राकृतिक न्याय के तहत तैयार किया गया है, सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति लेने के लिए, और यही कारण है कि, यदि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण के उक्त इरादे को अन्य देशों के संवैधानिक जनादेश के संदर्भ में पढ़ा जाता है, तो यह कायम रखने योग्य निर्धारित किया गया था कि एक निजी संपत्ति के अधिग्रहण में राज्य के लिए कोई प्रतिरक्षा नहीं है, जिसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए विनियोग की शक्तियों द्वारा कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन तर्क के आधार पर

113. ऊपर दिए गए सभी तर्कों और तर्कों के लिए इस न्यायालय का विचार है कि देश की प्रासंगिकता, देश के एकीकरण, देश के नागरिकों को शांतिपूर्ण जीवन का आश्वासन देने के बारे में लागू कानून के संवैधानिक जनादेश और आत्मा के अलावा, इस न्यायालय का विचार है कि यह एक नागरिक के लिए तभी माना जा सकता है जब वे देश की रक्षा संरचना को सुरक्षित कर लें और किसी भी अचानक सैन्य सम्बंधित से निपटने के लिए इसकी ताकत और इसकी तैयारियों को इसके रक्षा कर्मियों या ऐसी किसी भी अन्य एजेंसी को पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके बढ़ाया जाता है, और विशेष रूप से, रणनीतिक बिंदु पर, जहां भारत एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है, जो मुश्किल से 20 से 25 किमी है।सम्बंधित भूमि से दूर, वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे।

यही वह समय है जब विभिन्न वेदों ठीक होना देश की रक्षा की प्रासंगिकता पर भी पौराणिक रूप से विचार किया गया है, और विशेष रूप से अथर्व वेदों के कुछ अंशों पर निर्णय के इस चरण ठीक होना विचार करने की आवश्यकता है, ताकि देश की रक्षा की आवश्यकता के दृष्टिकोण से अधिसूचना के महत्व और आवश्यकता को निर्धारण किया जा सके।

114. अंत में, किसी देश के महत्व और उसकी रक्षा की अवधारणा एक अलग या नया सिद्धांत नहीं है, जिसे आधुनिक कानून द्वारा विकसित या चर्चा की गई है, जैसा कि अब विभिन्न देशों द्वारा कानून बनाया जा रहा है, बल्कि यह एक पुराना सिद्धांत है, जिसे हमारे देश के पौराणिक वेदों और प्राचीन ग्रंथों द्वारा माना गया था, उदाहरण के लिए अथर्व वेदों ने अपने **धारा** 5/19/4 में देश की रक्षा की आवश्यकता और आवश्यकता पर चर्चा की है।अथर्व वेदों के निम्नलिखित उद्धरण भी आक्षेपित अधिसूचना द्वारा किए जाने वाले अधिग्रहण का समर्थन करते हैं।प्रासंगिक भाग यहाँ नीचे निकाला गया है:–

> "ब्रह्मगवी पच्यमाना यावत् साभिविजंग्डहे।
> तेजो राष्टंस्य निहन्ति न वीरो जायते वृषा ।।
> अथर्ववेद 5/19/4"

115. शाब्दिक रूप से, हमारे देश के प्राचीन ग्रंथों का मूल उद्देश्य, अथर्व वेदों के उपरोक्त अंशों को देखते हुए, पुजारी और सम्राटों द्वारा दिए गए प्राचीन ग्रंथों और अधिसूचना द्वारा इसकी भविष्यवाणी की गई थी, बल्कि यह एक कर्तव्य है कि देश के सम्राट द्वारा किया जाने वाला मूल निहित अधिकार और कर्तव्य अपनी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, क्योंकि यह समूह के किसी भी आक्रमण से इसे बचाने का मुख्य उद्देश्य है, और इसमौजूदा, यहाँ अधिग्रहण भी अथर्व वेदों के उपरोक्त स्लोक के इरादे के भीतर है, जहां राष्ट्रीय महत्व पर जोर दिया गया है कि देश को बचाने के मौजूदा सम्राट का प्रमुख कर्तव्य है।

116. अथर्व वेद संहिता में, भाग–2 ने अपने अध्याय–24 में, अपने पैरा 4750 में देश के महत्व पर चर्चा की थी, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि मानव समुदाय को, एक विशेष देश के रूप में, देश की समृद्धि और रक्षा के लिए सभी प्रयास करने होंगे।प्रासंगिक भाग यहाँ नीचे निकाला गया है:–

"अथर्ववेद संहिता भाग–२

ख्२४ राष्टंसूक्त ,

ख्ऋषि–अथर्वा। देवता–मन्त्रोक अथवा ब्रह्मणस्पति।

छन्द–अनुष्टुप्, ४–६,८ त्रिष्टुप्, ७ त्रिपादार्षी गायत्री,

४७५0. येन देवं सवितारं परि देवा अधारयन्। तेनेमं ब्रह्मणस्पते
परि राष्टांय धत्तन ।।

हे ब्रह्मणस्पते ! देवों ने जिस प्रकार सवितादेव को चारों ओर से
धारण किया, उसी विधि से इस महान् शान्ति के अनुष्ठाता यजमान को

राष्टं की सुरक्षा के लिए सत्रद्ध 1/4तत्पर1/2 करें ।।१ ।।"

117. वास्तव ठीक होना, यदि अथर्व वेदों के उपरोक्त अंशों ठीक होना निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान ठीक होना रखा जाए, तो इसके बजाय यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्र की सुरक्षा इस तरह से की अधिसूचना चाहिए, जिसठीक होना, जब सीता को रावण द्वारा अपहरण कर लिया गया था और उसे अशोक वाटिका ठीक होना रखा गया था, वास्तव ठीक होना, उसे चारों कोनों से देवताओं द्वारा संरक्षित किया गया था ताकि उसे किसी भी नुकसान से बचाया जा सके।

118. इस प्रकार, उपरोक्त तर्कों और तर्क को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है किः

1. प्रस्तावना की भावना के आलोक में देश की रक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जो अपने नागरिकों की इच्छा के अनुसार एक देश का गठन करने का इरादा रखता है, यह भारत के क्षेत्र पर किसी भी विदेशी विद्रोह से मुक्त, देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए समावेशी होगा।

2. इस न्यायालय का विचार है कि प्राचीन ग्रंथों और भूमि अधिग्रहण के लिए जारी अधिसूचना में व्यक्त सार्वजनिक उद्देश्य के कारण,

अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे रक्षा को पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करना सार्वजनिक उद्देश्य के दायरे में होगा और अधिसूचना जारी करना देश के साथ निहित प्रतिष्ठित अधिकार क्षेत्र की शक्तियों के प्रयोग के भीतर होगा।

3. इस न्यायालय का विचार है कि दिए गए कारणों के लिए, जब प्रस्तावना स्वयं देश के नागरिकों की ओर से तैयार की गई थी, तो इसका उद्देश्य एक एकीकृत भारत प्रदान करना था, उक्त उद्देश्य को राष्ट्र की सुरक्षा की कीमत पर किसी विशेष समुदाय के अधिकार को लागू करके विविधीकृत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रस्तावना में 'नागरिक' शब्द का उपयोग किसी भी उप–जाति या आरक्षित जाति या जनजातियों के लिए होगा, जैसा कि संविधान में शामिल है और उनके अधिकार, जो प्रकृति में व्यक्तिगत हो सकते हैं, को देश के अधिकारों पर प्राथमिकता या सर्वोच्चता नहीं होगी।

4. इस न्यायालय का विचार है कि जब यह रक्षा आवश्यकता है और वह भी, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, जहां क्षेत्र की दुर्गमता के कारण उच्च ऊंचाई पर युद्ध महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है,

जो वाहन चलाने योग्य नहीं है, तो व्यक्तिगत अधिकार प्रबल नहीं होंगे।

5. याचिकाकर्ताओं के लिए कोई पक्षपातपूर्ण नहीं है, विशेष रूप से जब, निर्णय के मुख्य भाग में पहले से ही निपटाए गए अनुपात को देखते हुए, उनके अधिकारों को देखा जा रहा है सार्वजनिक प्रयोजन को पूरा करने के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के परिणामस्वरूप पर्याप्त मुआवजे के भुगतान द्वारा, प्रतिष्ठित क्षेत्र के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए, और उस स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता पूर्वाग्रह से ग्रस्त होंगे या राज्य द्वारा किया गया कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 300 ए का उल्लंघन है।

6. यहां तक कि अधिकार, जो भूमि पर याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किया जाता है, वास्तव में, रिकॉर्ड के कारण, जो याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष लाया गया है या जैसा कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा साबित करना दिया गया है, यह किसी भी आदेश द्वारा एक अक्षम्य अधिकारों की स्थापना की पुष्टि नहीं करता है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाना है, क्योंकि निहित होने सम्बंधित, के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप Z.A.

& L.R. अधिनियम, राज्य के साथ भूमि का निहित होना हो सकता है न कि व्यक्ति के साथ और इसमें निहित होना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्णय के अनुसार, मिट्टी की जुताई के लिए निहित अधिकार तक सीमित होगा न कि उस स्वामित्व तक जो राज्य के साथ निहित है।

7. याचिकाकर्ताओं का यह दलील कि वे 1880 से कब्जे में हैं, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा स्थापित नहीं है, क्योंकि उनके साक्ष्य जो रिकॉर्ड पर रखे गए हैं, से पता चलता है कि वे 1967 से कब्जे में हैं, हालांकि यह एक तथ्य था जिसे प्रतिवादीओं द्वारा नकार दिया गया था, जो अन–खंडन किया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने 1990 के बाद से सम्बंधित भूमि पर कोई कृषि गतिविधि नहीं की थी।

8. यह तर्क देने ठीक होना कि याचिकाकर्ता भूमि पर एक कृषि गतिविधियों को ले जा रहे थे, यह बोझ था जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा एक कृषि गतिविधियों को करने के रिकॉर्ड पर आवश्यक दस्तावेज रखकर निर्वहन किया जाना था, जो इस तथ्य के कारण स्थापित नहीं किया गया था, कि यहां तक कि उनके अपने राजस्व रिकॉर्ड, जिस पर, उन्होंने भरोसा किया है, भूमि पर अपने प्रकृति के कब्जे या उनके कार्यकाल को स्थापित नहीं करते हैं,

जिसके तहत, भूमि की श्रेणी या वर्गीकरण, वे Z.A की धारा 129 के प्रावधानों के भीतर आएंगे। & L.R. अधिनियम, जिसे भूमि अभिलेख नियमावली के पैरा–ए, 124 के साथ पढ़ा जाएगा।

9. चूंकि भूमि का अधिग्रहण रक्षा आवश्यकताओं के लिए किया जा रहा है, इसलिए इस न्यायालय का विचार है कि अधिनियम द्वारा किसी भी तरह का संरक्षण दिए जाने के बावजूद, देश की रक्षा आवश्यकता को कम करने के लिए किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता है, और विशेष रूप से, जब ऊपर बताए गए अनुपातों के अनुसार, अनुच्छेद 300 ए द्वारा परिकल्पित याचिकाकर्ताओं का अधिकार अभी भी संरक्षित है।

10. गृह मंत्रालय और गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिए जा रहे लगातार निर्णयों को देखते हुए, जैसा कि रिकॉर्ड पर विभिन्न संचारों और सामरिक रिपोर्ट से स्पष्ट होगा, जिसे दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर रखा गया था भूमि का रणनीतिक स्थान, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार भारतीय क्षेत्र तक आसानी से पहुँचने वाले दोनों पर नज़र रखने के लिए अधिक महत्वपूर्ण था, i.e. "लासार गाद" और "इंटरनेशनल पास", भूमि का किसी व्यक्ति के महत्व के बजाय सैन्य महत्व था।

+

11. सामरिक रिपोर्ट और सर्वेक्षण, जो सक्षम राजस्व और सैन्य अधिकारियों द्वारा किए गए हैं, यह देखा गया है कि भूमि का स्थान मुश्किल से 20 से 25 किमी है।अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, यह एक पर्वत श्रृंखला के ठीक नीचे स्थित है, जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट होगा, कि यह दुश्मन देश की गोलीबारी सीमा से बाहर होगा और पहले से मौजूद समूह प्रतिष्ठानों और बंकरों के पास स्थित होगा।

12. आगे यह पाया गया है कि भूमि इतनी स्थित थी कि भारी समूह के उपकरण और लंबी दूरी के फायरिंग उपकरणों को आसानी से भूमि से तैनात किया जा सकता था, जिसे अर्धसैनिक और सैन्य बलों की रक्षा आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिग्रहित करने का प्रस्ताव था।

13. अतः, उपर्युक्त कारणों के कारण, इस न्यायालय का विचार है कि किसी व्यक्ति या समुदाय के व्यक्तिगत अधिकारों के बावजूद, यह किसी भी परिस्थिति में, देश की रक्षा के अधिकारों या आवश्यकता को ओवरराइड नहीं कर सकता है, इसलिए अधिग्रहण किसी भी स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त नहीं है, जो याचिकाकर्ताओं के लिए अधिकार की जांच करने के लिए खुला

छोड़ सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अधिग्रहण।

119. उपर्युक्त कारणों के आलोक में, इस न्यायालय का विचार है कि सभी तर्क और ऊपर दिए गए तर्क के लिए, आक्षेपित अधिसूचना किसी कानूनी और स्पष्ट दोष से ग्रस्त नहीं है, इसलिए, रिट याचिका में योग्यता का अभाव है और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

(शरद कुमार शर्मा, जे।)
04.03.2022

Translation has been done through AI tool- Anuvaad.
By- Soniya
Civil Judge.
Haldwani-Nainital.